IMPACT 9.154 iijif FACTOR


Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh, Tq.Dist.Beed
Pin-431 126 (Maharashtra)
Mob.09850203295

ISSN 2319 9318


कौशल आधारित अधिगम और रोजगार


MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

# विद्यावार्ता®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal


## महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय

किला भवन, इन्दौर

एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार

# कौशल आधारित अधिगम और रोजगार

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा प्रायोजित

आयोजक

स्वामी विवेकानंद करिअर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ

एवं IQAC


प्राचार्य
डॉ. चंदा तलेरा जैन

सहसंयोजक
प्रो. पूजा जयस्वाल

संयोजक
डॉ. सीमा तिवारी

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक शोध पत्रिका
विद्यावार्ता™

महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
किला भवन, इन्दौर

स्थापना वर्ष-1963

# एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार

## कौशल आधारित अधिगम एवं रोजगार

दिनांक 31 अगस्त 2023 (समय : 12:00)

प्रायोजक :
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल (म.प्र.)

आयोजक :
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन एवं IQAC प्रकोष्ठ

**Editor**
**Dr. Seema Tiwari**

**Publisher**
**Dr. Bapu g. Gholap**
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

❖ **विद्यावार्ता** या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. **न्यायक्षेत्र:बीड**

“Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat**.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Date of Publication
30 Sep. 2023

# Vidyawarta™

## International Multilingual Research Journal


www.विद्यावार्ता.कॉम®

YouTube Channel

*Vidyawarta is peer reviewed research journal. The review committee & editorial board formed/appointed by Harshwardhan Publication scrutinizes the received research papers and articles. Then the recommended papers and articles are published. The editor or publisher doesn't claim that this is UGC CARE approved journal or recommended by any university. We publish this journal for creating awareness and aptitude regarding educational research and literary criticism.*

*The Views expressed in the published articles,Research Papers etc. are their writers own. This Journal dose not take any libility regarding appoval/disapproval by any university, institute, academic body and others. The agreement of the Editor, Editorial Board or Publicaton is not necessary. Editors and publishers have the right to convert all texts published in Vidyavarta (e.g. CD / DVD / Video / Audio / Edited book / Abstract Etc. and other formats).*

***If any judicial matter occurs, the jurisdiction is limited up to Beed (Maharashtra) court only.***

Indexed

IMPACT 9.154 iijif FACTOR

Govt. of India,
Trade Marks Registry
Regd. No. 2611690

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. • International Multilingual Research Journal • CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM • ISO 9001:2015

**http://www.printingarea.blogspot.com**

## कार्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग

## इंदौर संभाग, मोती तबेला इंदौर, 452004

Phone No 0731-2464924 Fax 111111No. 2362055

---

### शुभकामना सन्देश

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर के स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ और IQAC के द्वारा “कौशल आधारित अधिगम और रोजगार” विशय पर, सफलतापूर्वक संपन्न किए गए वेबिनार के लिए मैं महाविद्यालय की माननीय प्राचार्या, वेबिनार की संयोजिका और आयोजन समिति के समस्त सदस्यों को बधाई प्रेषित करती हूँ।

**डॉ. किरण सलूजा**
अतिरिक्त संचालक, इंदौर संभाग
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
शासन, भोपाल

## प्राचार्य की कलम से

कौशल आधारित अधिगम, शिक्षा का ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यावहारिक धरातल पर कौशल एवं दक्षताओ को विकसित करने पर जोर देता है। संचार क्रांति के इस युग में अच्छा रोजगार मिलना युवा वर्ग के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है।

हमारा भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, युवाओं में कौशल विकास किए जाने की सतत् आवश्यकता है।

शासन एवं नवीन शिक्षा नीति 2020 को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर युवाओं को अधिकाधिक सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। यह वेबिनार इसी तारतम्य में आयोजित किया गया है।

इतने महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस वेबिनार से युवा वर्ग को सशक्त दिशा मिलेगी, और हम सभी लाभान्वित होंगे।

स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन समिति की संयोजक डॉ. सीमा तिवारी, सह–संयोजक डॉ. पूजा जायसवाल और वेबिनार आयोजन तथा तकनीकी समिति के सभी सदस्यों को इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत–बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएँ देती हूँ।

प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ चन्दा तलेरा जैन
महारानी लक्ष्मीबाई कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर

# <u>संपादकीय</u>

विश्व पटल पर विश्वगुरु और आर्थिक महाशक्ति बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर भारत में, युवाओं में कौशल विकास तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उन्नति अत्यावश्यक है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। भारत सरकार सहित समस्त संबंधित संस्थानों के द्वारा इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन एवं प्रकोष्ठ एवं IQAC प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रयासों से "कौशल आधारित अधिगम और रोजगार" जैसे समसामयिक विषय पर उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र. ) की अनुमति से एक दिवसीय वेबीनार आयोजित किया गया। इस आयोजन में विभिन्न विषय विशेषज्ञों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत शोधपत्रों का वाचन करने के साथ–साथ इनके संकलन की आवश्यकता महसूस की गई ताकि भविष्य में विद्यार्थियों द्वारा इनका लाभ उठाया जा सके।

वेबीनार के आयोजन की स्वीकृति हेतु मैं उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन की आभारी हूँ। उद्घाटन सत्र में, मुख्य संरक्षक के रूप में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग डॉ. किरण सलूजा के उद्बोधन से हमें प्रेरणा और संबल प्राप्त हुआ। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

वेबिनर की संरक्षक के रूप में महाविद्यालय की संस्था प्रमुख डॉ. चंदा तलेरा जैन के सहयोग और हृदयगामी मार्गदर्शन हेतु मै उनका आभार प्रकट करती हूँ

वेबिनार की आयोजन समिति की सदस्य डॉ. अनुराधा अवस्थी, डॉ. संगीता शर्मा, प्रो. पूजा जायसवाल, प्रो. आयशा ताहिरा खान, डॉ. आरती चौहान एवं डॉ. शैल श्रीवास्तव को उनके निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ।

साथ ही तकनीकी समिति के श्री आशीष कपूर एवं महेश विश्वकर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके तकनोकी सहयोग से यह वेबिनर निर्विघ्न संपन्न हुआ।

Seema Tiwari

डॉ. सीमा तिवारी

प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान/संयोजक

स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ

## प्रतिवेदन

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर का एक मुख्य उद्देश्य छात्राओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना है। इस हेतु संस्थान सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है। इन कार्यक्रमों का आयोजन "स्वामी विवेकानन्द करियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ" द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट सेल वर्ष 2005–06 से कार्यरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करना एवं उन्हें रोजगार/स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना हैं। डॉ. सीमा तिवारी (संयोजक) की देखरेख में कैरियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ छात्रों को शैक्षणिक, पेशेवर और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम, व्याख्यान और कार्यशालाएं आयोजित करता है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से समाज के वंचित वर्ग से आने वाली छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र बनाया जा सके, साथ ही उनके व्यक्तित्व और उनके संचार कौशल का विकास हो सके। स्वामी विवेकानन्द करियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ छात्राओं में उद्यमशीलता एवं कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सेल द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है।

महाविद्यालय मे "स्वामी विवेकानन्द करियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ" द्वारा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल से प्राप्त आदेश क्रमांक 863/260/आउशि/शाखा– 5 'अ'/2023 दिनांक 14/07/2023 के परिपालन में दिनांक 31/08/23 को एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का विषय "कोशल आधारित अधिगम एवं रोजगार" था । वेबिनार में बीज वक्ता के रूप में डॉ. ब्रह्मदीप अलुने, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, आदर्श महाविद्यालय विदिशा, म.प्र. उपस्थित हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य में रोजगारोन्मुखी शिक्षा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यवक्ता के रूप में डॉ. कपिलदेव यादव प्राध्यापक अर्थशास्त्र, श्री राम कालेज ऑफ कामर्स, नई दिल्ली एवं डॉ. अनिता पटेल प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान, श्री आर. बी. आर्टस, श्री के. बी. कॉमर्स, श्री वी. सी. जे. साइंस महाविद्यालय, खम्बात, गुजरात ने अपने बहुमूल्य विचारों से श्रोताओ को लाभान्वित किया। वेबिनार हेतु 269 प्रतिभागियों ने गूगल फॉर्म के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत किया ।

सह–संयोजक
श्रीमती पूजा जायसवाल
सहायक प्राध्यापक गृह
विज्ञान विभाग

# शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,

**किला भवन, इंदौर**

## राष्ट्रीय वेबिनार
## "कौशल आधारित अधिगम एवं रोजगार"

**आयोजन समिति**

**मुख्य संरक्षक**
डॉ. किरणबाला सलूजा
अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, इंदौर

**संरक्षक**
डॉ. चंदा तलेरा जैन
प्राचार्य, शा. म.ल.बा. कन्या स्नात. महाविद्यालय , इंदौर

**संयोजक**
डॉ. सीमा तिवारी
प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान

**सह-संयोजक**
श्रीमती पूजा जायसवाल
सहा. प्राध्यापक
गृह विज्ञान

**सदस्य**
डॉ. अनुराधा अवस्थी
सह. प्राध्यापक
गृह विज्ञान

**सदस्य**
डॉ. संगीता शर्मा
सह. प्राध्यापक
समाजशास्त्र

**सदस्य**
डॉ. शैल श्रीवास्तव
सह. प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान

**सदस्य**
श्रीमती आयशा ताहेरा खान
सहा. प्राध्यापक

**सदस्य**
डॉ. आरती चौहान
सहा. प्राध्यापक
वनस्पतिशास्त्र

**शोध पत्र समीक्षा समिति**

- **डॉ. सीमा तिवारी**
- **श्रीमती पूजा जायसवाल**
- **डॉ. अनुराधा अवस्थी**
- **श्रीमती आयशा ताहेरा खान**
- **डॉ. शैल श्रीवास्तव**
- **डॉ. आरती चौहान**

www.vidyawarta.com/03 _ http://www.printingarea.blogspot.com

# INDEX

01) Communication: A key skill to enhance the employability for youngsters
**Dr. Neha Sharma, Indore** ||12

02) Skill Development and New Education policy 2020
**Dr. Laxmi Barelia, Dr Pooja Gupta, Bhopal** ||16

03) To study inclination of youth towards handicraft-A skill ....
**Dr Namrata Khurana, Dr Uday Singh Ningwal, Dhar** || 18

04) PART OF COMMUNICATION IN EMPLOYMENT
**Pooja Jain, Indore** ||21

05) SKILL DEVELOPMENT AND WOMEN EMPOWERMENT
**Kanchan Shrivastava** ||24

06) Assessing the Effectiveness and Impact of Pradhan Mantri....
**Pramod Giri, Lateri Dist. Vidisha (MP)** ||26

07) गृहविज्ञान की कौशल आधारित शिक्षा प्राप्ति से बढ़ते रोजगार के अवसर
**डॉ अनुराधा अवस्थी, किला भवन, इंदौर** ||33

08) गृह विज्ञान और रोजगार
**डॉ. छाया हार्डिया, प्रियंका वर्मा, उज्जैन** ||36

09) व्यवसायिक शिक्षा तथा नवीन शिक्षा नीति
**डॉ. गोमती चेलानी, इंदौर** ||39

10) डेयरी उद्योग, दुग्ध उत्पादन इकाई में स्वरोजगार के अवसर
**डॉ. राजमल सिंह राव, बडवानी (मप्र)** ||43

11) सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग, युवा वर्ग के लिए संभावनाएं....
**डॉ. सीमा तिवारी, इंदौर** ||48

12) राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२०, भारतीय पारम्परिक विरासतो एवं उदयमान....
**डॉ. आरती चौहान, इंदौर (म.प्र.)** ||51

13) स्टार्टअप प्रबंधन
**परागी गुप्ता** ||59

14) कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण
**वन्दना सिसोदिया** ||64

15) कुशल कार्यबल तैयार करना : नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका
**डॉ. ज्योति मेहता, इंदौर** ||70

16) रोजगारोन्मुखी शिक्षा और कौशल विकास
**डॉ. शैल श्रीवास्तव, इन्दौर** ||74

17) महिला सशक्तिकरण और कोशल विकास
**आयशा ताहैरा खान, किला भवन, इंदौर** ||77

18) जनजातीय समुदाय में कौशल विकास की आवश्यकता एवं महत्व
**पूजा जायसवाल, इंदौर** ||79

19) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
**डॉ. संगीता शर्मा, इंदौर** ||84

20) पर्यटन और व्यवसाय
**डॉ. उशा महोबिया, इन्दौर** ||85

www.vidyawarta.com/03 — http://www.printingarea.blogspot.com

**01**

# Communication: A key skill to enhance the employability for youngsters

**Dr. Neha Sharma**
Guest Faculty
Government M L B Girls P G College, Indore

***********

**INTRODUCTION :**

The qualified human resources with high competitiveness and employability skills are needed to face the era of technological disruption, but employers find a lack of expertise among job seekers. Insufficient skills are related to the issue of education quality. Communication, communication, communi -cation. We all know it's important, but communication skills can be challenging to develop and implement at work. The rise of remote and hybrid work hasn't made it any easier, either.

Yet, effective communication at work can be transformative for individuals, teams, and businesses. We're here to show you why communication is important in the workplace and how to start building your and your team's communication skills today.

Communication is a core skill involving a wide range of "sub-skills" essential for the workplace and for the hiring process that will get you there.

**COMMUNICATION SUB-SKILLS:**

**1. Written And Oral Communication**

Verbal communication is using words to convey information and it includes both written and oral communication. Oral communication skills mean that you can speak clearly, concisely, and without misinterpretation. That's essential even if your job isn't centred around speaking. Say, you're the server at a restaurant. Having oral communication skills is a must if you want to establish rapport with your customers and provide a good service.

Written communication is just as important. While there may be a few jobs that don't require writing a single word, in 90% of cases you'll need to write when:

- Writing emails to your colleagues
- Drafting a report for your boss
- Communicating with customers via email

If you're skilled at a particular kind of writing, such as copywriting, or editing, make sure to mention that in your resume or your job interview.

**2. Presentation**

Presentation skills doesn't just mean a person is good at presenting a PPT presentation in front of your colleagues.

Presentation skills are also about how we present our ideas and intentions in the workplace, or about how we present ourselves in a job interview. As such, it's another must-have communication skill for our resume, whatever our field of work might be.

**Presentation skills are useful for all sorts of situations, including:**

- Software engineers explaining how their code works.
- Statistician presenting their findings to other employees
- Sales manager explaining to a client why they need a product.

**3. Active Listening:**

Active listening requires paying close attention to the speaker by engaging with them to ensure you're getting the essence of the conversation. It additionally involves removing all other distractions and asking clarifying questions, thus making them feel heard.

Active listening doesn't come in handy only in jobs like customer service, or design, where understanding and making clients feel heard is integral. Active listening is also needed if you are to successfully interact with your

colleagues, succeed in the workplace, or even ace your job interview.

If you ask us, active listening skills give you extra points as a candidate no matter your profession (and you should definitely add it to your resume).

**4. Nonverbal Communication**

Communication consists of much more than just speaking. It involves body language, posture, gestures, eye contact patterns, and facial expressions, among others.

This type of communication often helps more in inciting trust among your coworkers, or from clients, than verbal communication. At the same time, it makes it possible for you to see beyond what a person is saying and right into what they mean, or feel.

As you can imagine, nonverbal communication is a skill that comes in handy for the vast majority of professions (especially sales or leadership roles), not just the world of business.

Instead of adding it to your resume, aim to demonstrate your nonverbal communication skills during your job interviews. This includes maintaining eye contact, avoiding hand gestures, or controlling your facial emotions.

**5. Feedback**

Feedback - both providing and accepting it - is a skill that goes hand in hand with several other communication components such as active listening, respect, open-mindedness, and teamwork. Truly encouraging feedback isn't possible without really understanding what the speaker means, respecting their opinion, and keeping an open mind.

So, for example, if you were receiving feedback from a supervisor, you'd listen and accept the evaluation without judgment - even if you didn't agree. You wouldn't interrupt them, but you'd wait until the end to ask clarifying questions to make the process as constructive as possible.

On the other hand, if you were the one giving feedback to a colleague, you'd do so through a fact-based evaluation and you'd offer them time to respond. You'd additionally consider their needs and offer negative feedback discreetly.

Being able to give/take feedback is pretty much a guarantee for career success. That's because it's tied with the willingness to learn, the ability to adapt, the openness to accept constructive criticism, and the critical reasoning that it takes to provide it.

**6. Respect**

Respect is one of the fundamentals of successful communication and the communication skill to bring along on the job interview. It involves active listening and patience (among others) and it's vital if you are to be considered for - or keep - any type of job.

Being respectful is about letting others speak and knowing when to initiate conversation or respond. Little gestures can go a long way to respecting recruiters and colleagues alike - staying focused and removing all distractions or being polite are just two among many.

When it comes to the job interview, interrupting recruiters or wasting their time by going off-topic are signs of rudeness and will most likely cost you the job.

**7. Confidence**

Confidence is the next skill in line necessary for a good first impression during your job interview. And if you're wondering - yes, you can be respectful and confident at the same time. The two are not mutually exclusive, just equally important.

Confidence is a character trait that shows you're sure about your words, actions, and decisions - and that's something people respond to positively.

If you're not naturally confident, worry not - there are methods to appear confident even if you don't feel like it.

**Some ways to appear more confident include:**

- Maintaining eye contact during the job interview

- Sitting up straight with open shoulders
- Speaking in a friendly - but firm - tone of voice
- Preparing in advance so you don't stumble on your words

If, on the other hand, you're the naturally confident type, keep in mind not to overdo it with bravado. Sometimes, too much confidence can come across as arrogance or rudeness and that's not going to sit right with most people.

**8. Clarity**

Clarity is an indispensable part of oral communication. It involves structuring your thoughts logically and using the right words to convey them as effectively as possible.

If you can't communicate clearly, be it due to a hectic thought pattern or inappropriate language, your job interviews will suffer.

Imagine, for example, giving a complicated answer to a simple question, or using street jargon ("hey interview fam, nice to meet").

**9. Honesty**

Honesty is a communication skill you should strive to incorporate in all aspects of your professional life.

As a rule of thumb, honesty should characterize your work ethic for obvious reasons, the most important being that lying about your skills and qualifications is the least dependable method for success. You can rest assured that, at some point, the truth will come out.

Being honest with your colleagues and supervisors about anything work-related, on the other hand, shows that you value transparency. It also proves that you are confident to accept your mistakes and take responsibility for your actions.

**10. Friendliness**

You might be wondering how one can be both friendly and professional during a job interview. Well, friendliness doesn't have to stand in the way of your professionalism, just like confidence doesn't stand in the way of politeness.

Friendliness during your interview will show recruiters that you are cooperative, open-minded, and a good team member - something sought after in all employees. More importantly, you don't have to go overboard to convey that you are a friendly person; a warm smile, a genuine greeting, or wishing a good day are enough to show it.

**11. Public Speaking**

Public speaking is many people's worst fear. Actually, studies shows that public speaking is feared more than death.

And, to be fair, even the most extroverted among us will get an increased heart rate and sweaty palms when they need to address a crowd.

Since public speaking is one of the most important communication skills (whether you're doing a presentation at work or telling a story to your friends), we thought we'd provide some tips on how to get better at it:

1. Prepare in advance. Being nervous before your speech doesn't necessarily mean you'll do a bad job! Everyone gets nervous before addressing a crowd, but as long as you prepare in advance by practicing your presentation with people you feel comfortable with, you should be more than ready to deliver!

2. Know your audience. Learn as much as possible for your audience in order to tailor your choice of words, information amount, and other elements of your speech accordingly. For example, if you're presenting to a crowd of Millenials for your Journalism 101 class, you'd be better off keeping your speech short, to the point, and light-hearted. You can even throw in some pop-culture references, memes, or jokes to make the speech even more engaging. If, on the other hand, you're talking about a more serious topic (e.g. capital punishment), then you'd want to maintain a bit more of a serious tone, even if it's for a class.

3. Organize your material. Create the framework for your presentation, including the topic, purpose, general idea, and main points, to grab the attention of your audience right off the bat.

4. Be attentive to feedback and adapt to

it. Is your audience struggling to keep up with what you're saying? Slow down! Are they laughing at your jokes? Keep em' coming!

5. Let your personality shine through. Your audience will greatly like your speech if you act like yourself. Work your quirks, mannerisms, and personality into your speech and you'll seem a whole lot more genuine.

6. Don't read from the text. Reading directly from a script is bound to keep you from impacting the crowd - you'll just seem like a robot reading a script. Instead of directly reading from your notes, create a thorough outline to guide you through your speech instead (without diving too much into specifics).

7. Take advantage of non-verbal communication. What you do with your hands and voice matters, just like any other type of non-verbal cue. As such, make sure to pay attention to how you use your body language, preferably by practicing in advance.

8. Grab attention from the get-go. A startling stat, personal story, or relevant anecdote will help you grab your audience's attention from the start. Avoid saying something generic like "here's what I'll be talking about today."

9. Conclude dynamically. Whether we like it or not, most people will remember the conclusion of your presentation more than anything else. Make it memorable by including a strong statement.

10. Take advantage of audio-visual aids. Audio and visuals, like videos that are relevant to your speech or music that's related to what you're saying, can reinforce your message. Use these sparingly, though, you don't want to distract or overwhelm your audience.

**CONCLUSION:**

Communication undeniably stands as a cornerstone skill that significantly enhances employability among youngsters while simultaneously refining their overall personality.

The ability to convey thoughts, ideas, and information effectively is not only an essential trait sought after by employers across various industries but also a vital tool for personal and professional growth.

Effective communication fosters strong interpersonal relationships, bolsters teamwork, and promotes a positive work environment. It allows individuals to express themselves confidently, share their unique perspectives, and contribute constructively to their workplace. Moreover, it plays a pivotal role in problem-solving, conflict resolution, and decision-making, all of which are integral components of the modern workforce.

Beyond its professional benefits, proficient communication augments personal development. It cultivates self-confidence, self-awareness, and empathy, empowering individuals to navigate the complexities of both their careers and personal lives. It enables them to connect with others on a deeper level, building trust and rapport that can lead to lasting, meaningful connections.

As the job market becomes increasingly competitive and dynamic, the value of effective communication cannot be overstated. Youngsters who prioritize honing their communication skills gain a distinct advantage in securing employment opportunities, progressing in their careers, and ultimately realizing their full potential. Moreover, the broader impact of improved communication resonates throughout society, fostering understanding, collaboration, and innovation.

In essence, communication serves as a linchpin for personal and professional success. By recognizing its significance and investing in its development, youngsters not only increase their employability but also embark on a transformative journey towards becoming well-rounded, confident individuals who can positively influence their workplaces and communities. Embracing effective communication is not merely a skill; it is a gateway to a brighter, more prosperous future.

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318 

**02**

# Skill Development and New Education policy 2020

**Dr. Laxmi Barelia**

**Dr Pooja Gupta**
Department of Chemistry, Govt. MVM, Bhopal

**********

**Abstract :**

For any nation, knowledge and skills are the main drivers of social and economic development. Countries with higher levels with better standards of skills adjust more effectively to the challenges and opportunities in domestic and international job markets. Being youngest country in the world with average age 29 years with over 62% of its population in the working age range (15-59 years) and over 54% of its overall population under 25. However, over the following ten years, the 15-59 age group is anticipated to have a population pyramid bulge During the next 20 years the labour force in the industrialized world is expected to decline by 4%, while in India it will increase by 32%. This poses a formidable challenge and a huge opportunity. India needs to equip its workforce with employable skills and knowledge so they can significantly contribute to the economic growth of the nation and derive benefit from this demographic dividend, which is anticipated to persist for the next 25 years. On July 15, 2015, on the first World Youth Skills Day, the Prime Minister unveiled SKILL INDIA, which contains four significant and complementary programs of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

**Introduction: -**

The Prime Minister launched SKILL INDIA MISSION on July 15, 2015, on the occasion of the first ever World Youth Skills Day, it contains four significant and related projects from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship viz. Sector Skill Councils (SSCs), the National Skill Development Agency (NSDA), the National Skill Development Corporation (NSDC), the National Skill Development Fund (NSDF), and 187 training partners are all registered with NSDC. Additionally, the Ministry of Skill Development wants to collaborate with the industry's network of colleges, skill development institutes, and other partnerships. For multi-level participation and more effective implementation of skill development programs, cooperation with pertinent Central Ministries, State governments, international organizations, industry, and NGOs have also been started.

**Objectives: -**

This study based on secondary data gathered from various sources such as research articles, government schemes, programmes and policies including online sources. The objective of this study to assess the impact of the ongoing skill development programmes also the new dimension added by NEP 2020 in the area of skill development.

**Review of literature:**

**A. Skill development initiative scheme in Madhya Pradesh**

1.Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) scheme was launched in 2015 to provide short-term training, skilling through ITIs and under the apprenticeship scheme Since 2015, the government has trained over 10 million youth under this scheme.

2.Sankalp and Strive: The Sankalp programme which focuses on the district-level skilling ecosystem and the Strive project which aims to improve the performance of ITIs are other significant skilling interventions

3.Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE): Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) is a new

World Bank funded project that has been approved by Expenditure Finance Committee (EFC) in November 2016 for a total cost of Rs. 2200 crore (US $ 318 million).

The project falls under the Programme for Results (P4R) based category of World Bank that ensures outcome-based funding. The project aims at creating awareness through industry clusters/ geographical chambers that would address the challenge of involvement of micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs). The Project would also aim at integrating and enhancing delivery quality of ITIs. In order to ensure achievement of outcome these ITI would be competitively selected for upgradation under the scheme

4.The Madhya Pradesh Skills Development Project :-(MPSDP) will assist the Government of Madhya Pradesh (Go MP) in transforming its technical and vocational education and training (TVET) system to create a skilled workforce that meets the evolving development needs of the state (Duppada, 2022)

**The project components are:**

a. Global skills park (GSP) established for advanced training and TVET support. GSP will establish international quality advanced training institutes, along with entrepreneurship and other TVET support clusters. The main training clusters in GSP will consist of: -

b. Centre for Occupational Skills Acquisition (COSA), which will impart job-ready skills for technology-oriented manufacturing and service sectors.

c. Centre for Advanced Agricultural Training (CAAT), which will focus on smart farming technologies to train a skilled workforce needed for the growth of the state's agricultural sector.

d. GSP will also include, among others, centre for entrepreneurship development and innovation; centre for TVET practitioners' development, and centre for skill research and development. The other ITI focused program also planned.

**2. To analyse the status of skill gap in India and to understand the benefits of skill development**

Unemployment is not a new issue in our country. According to India Skills Report 2022 by Wheebox, only 48.7% of total youth in India is employable (Bholane, 2023). This means almost 1 out 2 Indian youths are not employable.

The study also says that about 75% of all the companies surveyed reported a skill gap in the industry. Skill gap is affecting the employability scenario in almost every sector. As per the International Labor Organization, there will be a skill deficit of 29 million by 2030, which will significantly affect the country's GDP. According to research conducted by NASSCOM, every year more than 3 million graduates and post-graduates are added to the Indian human-resource and out of these, only 25% of IT graduates are considered employable 2 by fast growing IT & ITES industry.

**How employability has changed over the year: -**

| Years | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employability | 40.44% | 45.60% | 47.38% | 46.21% | 45.9% | 50.3% |

According to a survey by Skillsoft, the skills gap in the information technology sector is getting significantly worse, as the industry grapples with talent shortage and employee retention. A whopping 66% of IT decision-makers see skill gaps in their teams as a major problem.

The study found that the skill gap problem is being driven by both difficulties in hiring and retaining workers as well as underinvestment in training and development opportunities for existing staff.

**Approach To Deliverables**:

**1) Diversity of skills:** There is a need to identify, catalog and project the range and depth of skills e.g. traditional, industrial-era and post-industrial era skills to understand and present the vast array of skills that individuals can choose from.

**2) Talent pool:** The ultimate measure is

the "500 Million" skilled people. Skill inventory along with its various levels and grades will be created.

3) Employment outcomes Skill training must ensure a job for those who seek it. The placement ratio will be monitored and placed in the public domain by agencies involved in skill training

**Conclusion:** -

Over 90% of the working-age population falls within the informal sector, primarily due to a lack of requisite skills for formal employment. Although the divide remains significant, India has witnessed substantial collaborative efforts over the past decade involving the government, industries, and the education sector to bridge this gap. Graduates leaving college often face challenges in securing employment due to a skills mismatch. However, if India can successfully integrate general education and vocational training, this discrepancy can be addressed. A robust skill-oriented education model has the potential not only to revolutionize the nation's perception of career opportunities but also to usher in a creative and innovative approach to global leadership (Kumar, May 5, 2022).

**References :**

1.Bholane, K. P. (2023). National Education Policy 2020: Catalyst for Skill Based Education. In K. P. Bholane, New Education Policy 2020 (pp. 17-23). Vaijapur: Researchgate.

2.Duppada, D. P. (2022). Skill Development in India with Reference to the New . IJIRT, 54-60.

3.kumar, d. s. (5 may 2022). Vocational Education And Skill- Enhancement in The NEP 2020. ijcrt, 87-92.

**4.**National Education Policy 2020.Government of India

5.https//:www.msde.gov.in

6.https//:www.aicte-india.org

❑❑❑

**03**

# To study inclination of youth towards handicraft-A skill based subject of NEP

**Dr Namrata Khurana**
Assistant Professor,
Madhay Pradesh higher education,
MAHARAJA BHOJ GOVERNMENT
P.G.COLLEGE, DHAR, INDIA

**Dr Uday Singh Ningwal**
Assistant Professor,

***********

**Abstract-:**

Handicraft means any craft which is handmade. It is an art where useful products are made using simple tools like scissors and other non-automated tools like hooks etc. the oldest handicraft is dhokara assort of metal casting about 4000 years old. Handicraft has its roots in the rural crafts. Many crafts have been practiced for century, while others are modern inventions or popularizations of crafts which were originally practiced in limited geographic area.These products are produced within a specific community and involve blue collar label.

NEP 2020 paves way to revive the dying arts of our country. It has also announced to employ rural artisans as guest faculty to impart education to students on various art forms. The National Research Foundation (NRF), envisioned in the NEP will not only focus on scientific research but will also be a catalyst in promoting quality research in art, music, philosophy, writing et al. The research focuses on inclination of youth towards these subjects. A sample of about 130 individuals was drawn from various regions of Dhâr district. The survey consisted of 57.6% males and the rest were females. The study used

a validated questionnaire with fifteen multiple-choice items covering the participants' demographic data. About 78% students were found to be highly inclined towards handicraft as a skill based subjects. Mostly female's students were found to likely incline towards handicraft as a skill based subjects.

**Keywords:** NEP 2020, handicraft, dhar, NRF.

**Introduction:**

Many crafts have been practiced for century, while others are modern inventions or popularizations of crafts which were originally practiced in limited geographic area.These products are produced within a specific community and involve blue collar label.

Handicraft involves a variety of products some of them to be listed are.

- Soap making
- Wood carving.
- Basket weaving
- Flower decoration.
- Bandhani
- Batik art
- Pottery
- Hand bags
- Bagru art
- Toy making
- Lace making
- Leather work
- Crochet.
- Carpet making

Any many more art forms known all over the world especially in India.

**Indian handicraft portal**

Indian handicraft portal is an initiative of government of India for digitization of handicraft products and to provide various services to artisans and other in an efficient and transparent manner. The page URL is https://indian.handicrafts.gov.in/en.

There are 2 schemes running on basically national handicraft development programme.(NHDP) to provide livelihood to artisans and to improve product quality. And comprehensive handicrafts cluster development scheme (CHCDS) to build cluster of handicraft channels across the country. Art is a great way for students with disabilities to express themselves and gain confidence in their abilities. Students with disabilities can learn the art industry by learning how to draw and how to create their own art. The aims of art for students with disabilities are to understand their own emotions and feelings learn how to express themselves, experience social interaction and develop self-confidence by creating artwork from an emotional level. The scope of art for students with disabilities allows them to discover the skills that are most useful for them to fulfil their desired career.

CBSE has also launched a 12 hour module of handicraft from class 6 onwards. Art integration is inclusion of art to understand the concepts of other subjects as well , here art and craft is not taught as a separate subject it is merging of art forms with other subjects to make classroom teaching more joyful .The art forms prescribed by NEP 2020 include drawing & painting, paper crafts, puppetry, sculpting, photography, performing arts etc.

Not just that, art-integration in classroom learning can also enable schools and teachers to go beyond the conventional subjects and focus on deeper learning like socio-emotional, cultural, mental health, and other areas. Art-integration can also be used to create inclusive classrooms where students can be sensitized towards opposite genders, differently abled peers and broader communities.

Learning through art is also beneficial because it has been proven through research that it can lead to longer retention and better attention from students. It also makes classroom learning a collaborative experience for all the students through which they can also imbibe qualities like teamwork, empathy, coordination, cooperation, and communication. Art-integration also makes learning a very personal

and meaningful experience for the student, which is essential for creating self-awareness. Having talked about this, it is also important to highlight that being creative is a crucial need in today's work irrespective of which career option one chooses. If a child wants to make a career in arts, then art-integration can hone them and help in preparing them from an early stage. For those who want to pursue other career options, having a creative bent can help them in excelling in their respective fields as well.

It is anticipated that the NEP will not only reduce the social stigma associated with considering vocation as a career opportunity but will also provide students with promising career. The policy will play a vital role in equipping the manpower of the country with not only technical but also soft skills among graduate and post graduate students. The talent-skill gap exists at various levels and is significant. It is affecting the employability scenario in almost every sector. As per the International Labour Organization, there will be a skill deficit of 29 million by 2030, which will significantly affect the country's GDP. NEP 2020 paves way to revive the dying arts of our country. It has also announced to employ rural artisans as guest faculty to impart education to students on various art forms. The National Research Foundation (NRF), envisioned in the NEP will not only focus on scientific research but will also be a catalyst in promoting quality research in art, music, philosophy, writing et al.

**Material and method:**

A survey was conducted on a sample of 130 young representative of the population of Dhâr district Age19-21 years. A random sampling method and a questionnaire was applied to about 130 subjects out of which 57.6% were males and remaining were females. Participants were selected according to the national quota method (gender, age, geographical density and region). No abnormal finding was observed. Participants responded to questions on knowledge of NEP-2020, age, level of study, their idea about Skill based initiative of government of India, the hours they spent on skill development, the response rate was 100%.

**Result and discussion:**

From the survey analysis the following data was obtained about 57.6% males responded while the rest females responded. About 100% respondents were undergraduate students less than 19 years. 73% respondents were living along with their parents the rest were living in hostels, as paying guest etc. 78% respondent showed to have an inclination towards handicraft as a skill based subject in their course. Still about 42% youngsters were found to have no knowledge about various handicrafts of india.54% students responded that there is no scope in handicraft industry. 81% responded about knowledge of various initiatives of NEP. About 89% students responded that learning various kinds handicraft is costly and time consuming in India.

In conclusion a including handicraft as a subject of NEP is a great initiative and will open doors to employment and will enhance the knowledge and skill of youngsters of our country.

**References :**

· TarakHalder, J. Sujathamalini, G. Ravichandran. According to NEP 2020, the role of art education techniques in school level for inclusion of students with disabilities. International Journal of Research and Review. 2023; 10(3): 370-373. DOI: https://doi.org/10.52403/ijrr.20230343.

· https://indian.handicrafts.gov.in/files/scheme_file/nhdp.pdf

· http://egyany.in/handicrafts-of-madhya-pradesh/

· https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/explained-role-of-nep-in-enhancing-skill-development-among-students-1981740-2022-07-30

04

# PART OF COMMUNICATION IN EMPLOYMENT

**Pooja Jain**
Assistant Professor of Zoology,
Govt. MLB Girls P G College, Indore

************

**ABSTRACT :**

Communication chops play a great part not only in employment as well as in each and every field of life. The proper effective communication at the plant benefits both hand and the employer. Good communication skill leads to success in every field whether professional or particular. Good communication skills make proper collaboration, and remote work more effective this drives inventions and knowledge sharing. It Improves inter-departmental collaboration, extremity operation, plant safety, success of workers. It increases hand engagement and productivity therefore; we can say communication chops are of utmost importance in employment.

**PREFACE** :

Communication chops can be grueling to develop and apply at work. The rise of remote and cold-blooded work has been made successful by effective communication. This can be transformative for individuals, brigades, and businesses. Communication is important in the workplace. Communication in the plant is important because it boosts hand morale, engagement, productivity, and satisfaction. Communication is also crucial for better platoon collaboration and cooperation. Eventually, effective plant communication helps drive better results for individualities, brigades, and associations. By erecting good communication chops has profound short- and long-term benefits for your association. An effective prophet is suitable to motivate their platoon to get further done with better results and smaller misconstructions. All of these effects can contribute to the company's success as well as your own particular success as a leader Plant communication and its types Different communication channels are ideal for different types of communication. Depending on the type of information being conveyed, those different channels can enhance or abstract from how it's entered.

An effective prophet will develop different chops and tools to match the type of communication.

**Leadership communication**-

These are one- way dispatches by leaders to their brigades. The thing may be to inform or modernize. Leaders also frequently communicate to convert, encourage, and inspire commitment. They frequently communicate through illustrations further than data.

**Upward communication**-

directors frequently have to communicate with their own directors and with other leaders who aren't in their direct chain of command. These may take the form of memos emails, reports, or a niche in a standing meeting. Anyhow of the format, these types of dispatches should be considered more formal.

**Updates**-

These are brief and a type of strong communication. It may be visual, audio, verbal, or written to draw the followership's attention to what's most important. This might include surprises, obstacles, and implicit pitfalls, as well as triumphs.

**Donations**-

donations are communication tools that are generally aimed at a larger followership with advanced stakes. They've objects like informing, impacting, and prevailing. In addition, these also remove sweat from public speaking, and we have high anticipation for entertainment as well as sapience.

**Meetings**-

Meetings, whether large or small, are a critical part of a plant's internal communication strategy. These are one of the least understood and most overused types of communication. Effective meetings make community between brigades and snappily communicate information.

The stylish meetings are largely cooperative and leave actors feeling reenergized, not drained.

**Client dispatches**-

All of the considerations of communication among workers go twice for guests. Be deliberate and plan your dispatches to give what your client needs, in the way they prefer, and produce a positive print for the company and the product.

Informal relations- Informal dispatches include emails and exchanges making requests, asking for information, responding to requests, and giving or entering support and guidance. In addition to moving the work of the association forward, these informal dispatches form social connections, structure culture, establish trust, and chance common ground.

**Communication chops are essential for Better engagement**-

Better communication results in lesser hand engagement and enhanced hand productivity and eventuality. therefore, we can conclude, that their donation and input truly make a difference.

**Increased morale**-

platoon members with low job satisfaction take further time off of work, are less productive when in-office, and frequently negatively impact the productivity of other workers when they're present. still, when a hand has an understanding of the work that they've to do and how it connects to the overall success of the platoon, they bring further energy and pride to their work.

**Bettered productivity**-

Better communication ways help workers perform their assigned duties more. coffers and time can be saved through these ways. By reducing stress further work was done.

**Reduced churn-**

As a crucial factor in hand satisfaction and engagement, communication adds value to the association by reducing the development of professed and seasoned staff members.

**Greater fidelity**-

Longer- term, keeping workers for numerous times can add strength to the company. Endured hand has sufficient moxie to drive invention, break critical problems, and lead others. By proper and effective dispatches hand feels how they're treated and valued as individuals this impacts loyalty.

**More collaboration-**

companies' moment uses technologies that do not allow platoon members to be in the same room, the same structure, or indeed the same country. This shift presents new communication challenges, which means Nagger can grease collaboration by helping groups communicate effectively when using the rearmost technologies. Reduced plant conflicts erecting clear communication can ameliorate company culture and help misconstructions between directors and workers.

**Greater provocation**-

Communication skill is hearing the why and following up with a because. This approach will help you motivate workers. Ways to develop communication chops at work Suppose it through- There are numerous dispatches fabrics, but if you want to ameliorate your communication chops, start by getting in the habit of thinking. Test your understanding with co-workers or your director

**Give it time**-

Plan what you want to say and review your communication to make sure it's actually doing the job you need it to. For written dispatches, especially, revise, revise, revise. Flashback, great communication might feel royal, but it infrequently is.

**Make it easy**-

Plant communication nearly always has a larger thing. People are busy. Don't make them work too hard to understand what you're saying and what you need them to do. State your ideal and main point from the morning of a donation or written communication so that your followership knows where you are going. also, fill in the details.

**Simplify**-

In everyday work dispatches, be aware of not making the other party work too hard to understand. Find a clear, simple phrasing to synopsize your point. Repeat it in the morning, middle, and end, and use a simple visual to make your point clear and memorable.

**Trial and diversify**-

Work on developing different tactics for different communication requirements. Focus on experimenting with one aspect of your communication at a time. Pay redundant attention to structure informal dispatches, for formal meetings or updates.

**Practice and reflect**-

Be deliberate about reflecting on what goes well and what does not in your day-to-day communications. However, try to identify whether you easily communicated what you demanded, If a discussion with a colleague did not yield the anticipated results.

**Consider the full package**-

Consider recording yourself through many relations to gain sapience into what your full package is communicating in your diurnal relations with your platoon.

**Seek feedback**-

Ask many trusted co-workers and your director to rate your communication chops. Start by asking them to rate your written and spoken communication independently.

How to ameliorate communication when working ever Communicating well is indeed more important for leaders and directors during remote work. Doing it well can help make trust and connection and avoid the frustrations due to miscommunication. There are many areas to consider to ameliorate remote communication

**Clarify prospects-**

State prospects outspoken and repeat them at the end of a communication. Indeed, ask the other person to translate their understanding of your prospects.

**Engage in 2- -way inflow**-

Being remote can make it easier for workers to check out and liberate. Be deliberate and creative about giving others a part in communication. Ask questions, use polling and ranking tools, and solicit responses in the form of emojis, gifs, or one-word descriptors. Flashback to the power of in-person- A well-drafted platoon drone call or in-person meeting can establish a better connection and participated understanding, giving others a chance to surface areas of misalignment. **Focus on quality**-

People may feel defensive of their time when working, so make sure that live events are well-allowed - out. shoot dockets, meeting objects, or background reading ahead of time to help people prepare to have productive exchanges.

**Produce an informal space**-

Assuming good intentions and a sharing culture are both foundational for effective day-to-day communication at work. Show you watch- You do not have to spend a lot of time checking in with people and asking about their particular lives. It's worth reminding yourself that the donors of your dispatches are real people who have their own challenges, distractions, expedients, and fears. Before getting on a videotape call or firing off a dispatch, try picturing that person on the other end.

**Conclusion** :

Communication always tops the list of chops in demand by employers. There is a reason. Communication is what makes our professional and particular connections go

easily. It's how we show care, beget change, and get effects done. Business guiding for your platoon and yourself can help with this skill. That's reason enough to ameliorate and keep perfecting these important chops.

**Bibliography :**


- Doyle, A. s (2019). Communication Chops for Workplace Success. recaptured November 11, 2020 fromthebalancecareers.com
- Heathfield, S.M. (2019). You Can Boost Hand Morale. Simple Ideas for Perfecting Morale in Your Plant. recaptured November 11, 2020 fromthebalancecareers.com
- 5 Ways to Reduce Hand Development. recaptured November 11, 2020 fromForbes.com Burnside- Lawry, J. (2011). The dark side of stakeholder communication Stakeholder comprehension of ineffective organizational listening. Australian Journal of Communication, 38(1), 147- 173, 149.
- Adu- Oppong, A.A., & Agyin- Birikorang, E. (2014) (Online). Communication in the plant Guidelines for Improving Effectiveness. Glob. J. Commer. Manag. Perspect, 3(5), 1- 6. recaptured from https//www.longdom.org/articles/communication-in-the-workplace-guidelines-for improving-effectiveness


❑❑❑

05

# SKILL DEVELOPMENT AND WOMEN EMPOWERMENT

**Kanchan Shrivastava**
Student of M.A. Political Science

**********

**Skill development -**

A prerequisite for women empowerment India is Celebrated the world over for its bright and Vivacious while in many amount developed Countries, the amount of working population is decreasing by the day, India has a huge advantage since its demographic dividend is heavily tilted towards the youth. If we approach this through an economic lens, India has a lot to gain since its media age is merely 28 years and Consequently a younger. Workforce Translate into increased face of development and of economic growth. However the participation of women in india's workforce has been inadequate for over decades and in order to reap the Complete benefits of demographic dividend at this gap has to be bridges the earliest economy. A developing Indian economy needs around 103 million skilled workers between the age groups of 15-29 are not in umployment, education, or training out of this 100 Million around 88.5 million youth are Women While There has definitely been an increase in the Preperation of women receiving vocational training over the part few years, this increase is visible lesser than that received by men. To hut the same in numbers while the proportion of working-age Women receiving vocational training increased from 6.8% in 2011-2012 to 6.9% in 2018-19, the Increase proportion of working age recieving training 14.6% to 57.% percent in 2018-19. unahancing sustainable rural development and livelihoods. Social

outcomes are reflected in indicators of income inequality and haverly. employment outcomes are reflected by indicators of employment rates, unemployment, Youth not in School, and earnings.

**The momentum of Digital India in Skill Development**

There is a need to incorporate ICT (Information and Communication technology) for providing skill development solutions. It on should focus the formation of interind based or mobile platform which would Connect killed women and employers on women re-willing to enter the workforce after a break or those affected by migration.

**Women Empowerment Through Skill Development**

Women and economic participation and empowerment are fundamental to Strengthening women's rights and enabling them to have control over their lives and exert influence in Society. Women's economic empowerment is a prerequisite for Sustainable development Gender equality and empowered women are catalysts for multiplying development efforts.

The government of India has enacted Various rules and regulations within the Constitutional framework to improve female representation in different professions.

Certain Successful methods to retain girls and women in the workforce can be as follows :

· Introduce trainees to role models in respective sectors.

· Provide more and more hands opportunities.

· Collect and display testimonials so that trainees Can relate and take more interest in the program mme.

· Fetch Candidates rapidly in underserved populations.

· Develop a Comprehensive equity plan to identify and address discriminatory practices and artificial barriers to girls' annulment.

**Challengers:-**

India faces multifaceted challenges when it Comes to ensuring women's participation in the labor force on one hand the government is undertaking Continuous to ensure that girls have a higher rate of inrolment and minimum dropout rates in the primary, Secondary, and higher education, there are still a huge number of Women who hold degrees that still do not have Jobs. This essentially paints to the fact that literacy alone connact translate into effective employment other barriers to effective. employment of women in the form of social, historical and cuttrol hindrances also have to be addressed. further the stereotypical gender biass that came into play when women enter the workforce puts them at a further disadvantaged position as compared to men.

Also, the time spent by women in performing unpaid care and domestic work after keeps then from intering the formal workforce.

Anather issue of concern is the skilled ratio of men and women participation rates in different sectors.

According to Rajeev Chandrashekhar, Minister of State for skill Development and entrepneourship and electronics and Inframation Technology, Digitisation and re-skilling are key tools in not just impawering women to re join the workforce in the past-pandemic ira but also in creatin new becoming sectors in the economy. The government is therefore, directing its skill building initiatives and the new education policy to ensure that more women participate in previously undisourd fields. The aim of govererment is to provide equal possibilities to men and women in terms of skill and incawaging them to use those abilities to generate appartunities for themsellers in the workplace or through micro-interepreneversship.

**Skill india Mission**

Womens get a Special focus under skill India mission. Since its inception, Ministry of skill Development and Entrepreneurship has undertaken several initiating to achieve women

empowerment through skill developmet. Increase of women participation in workforce further boost to our economy and skill India mission is Committed to facilitate this through equipping women with market relevant Skills. and lead them to a path of Self-Sufficiency through entreprenestip.

**Initiatives Long term skill development training Via Industrial Training Institutes (ITIs)**

- short term kill Developmet training.
- Entrepreneurial Initiating.
- Recognition of prior learning.
- Apprenticeship Training.
- Future jabs and industry-Oriented policy Interventions
- Policy Interventions
- Special Women - Centric projects
- partnerships with private and non-Governmet Organisation to boost Skill developmest.
- projects in pradhan Mantri Mahila Kausal Kendra (PMMKK)
- Skill development not only creates employment spportunity but also impowerment opportunity but also empower them. The aim of skill development in case of women, is not just simply preparing them for jobs, but also to boost their performance by impraving the quality of work in which they are involved.

**"I raise my voice not He that I can shaid, but tso that thase without a vioice an be heard...... We connact all succeed when half of us are held back ".**

**Refrences :**

1. www.unicef.org/rosa/media/3926/file/Breaking
2. https://skillsip.nsdcindia.org/sites/default/files
3. invest.india.editorial outlook
4. https://indianexpress.com
5. censusindia.gov.in
6. skill India
7. Center for Social Research.

**06**

# Assessing the Effectiveness and Impact of Pradhan Mantri Kaushal Vikash Yojana (PMKVY)

**Pramod Giri**
Guest faculty, Sociology
Government college Lateri Dist. Vidisha (MP)

***********

**Abstract** :

In the last two decades the Government has implemented several large public career counseling projects, planning and progress in promoting youth employment and career opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), launched in 2015, has been a cornerstone of India's efforts to empower its youth with employable skills. PMKVY is known as a key measure to provide youth with skills-based preparedness that enables youth safety and career stability. Over the years, this ambitious program has evolved to address the nation's growing skill demands. The paper delves into the performance of PMKVY, examining its impact, challenges, and future prospects. Presented paper Comparative analyse the outcome of three phases of PMKVY with the help of secondary data.

**Keywords** :- Skill development, PMKVY, Skill training, Job Placement, Challenges and Areas for Improvement.

**1. Introduction :-**

The Government of India has set a determined and ambitious target for skill development to meet the demands of a skilled workforce. To achieve the goal, a formal skills development structure was initiated, starting with the mobilization of candidates, followed by counseling, training, assessment, certification, placement, monitoring and follow-up. All agreed

that the right use of technology can help overcome most of the challenges and give the Skill India mission the much-needed boost. The Government of India launched a new program 'National Skills certification and Reward Scheme' (STAR) under the National Skill Development Corporation (NSDC) in 2013, and allocated Rs 1 billion for training one million youth. Under this program, 14.5 million young people were trained and 120,000 means 8.5% among them got jobs. Recognizing the skills challenge, MSDE was founded in 2014. On July 15, 2015, the Prime Minister inaugurated the Skill India Mission and announced the National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015 and PMKVY. The field of training and apprenticeship was transferred to the MSDE from the Ministry of Labor. PMKVY was approved on March 20, 2015 with budget approval of Rs 1.5 billion, with an aim to train 2.4 million people including 1.4 million new trainees and 10 million recognition of prior training (RPL). This program was implemented by the NSDC. In July 2016, the government announced Rs 12,000 crore for skill training of 10 million youth under PMKVY (2016-20) and Rs 5 million under National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) (2016-20). 10,000 crore rupees was sanctioned for skill training of trainees.

The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) has evolved significantly since its inception in 2015. Here's an overview of its evolution through different phases:

- **PMKVY 1.0 (2015-2016):**

PMKVY was first launched in 2015 with the goal of training 24 lakh (2.4 million) Indian youth in various skills. Skill training was provided through various training centers, and successful candidates received a monetary reward. The primary focus was on improving employability and addressing the skills gap.

- **PMKVY 2.0 (2016-2020):**

PMKVY 2.0 expanded its scope to cover over 200 job roles across 40 sectors. Candidates who completed training received monetary rewards, and the program introduced placement-linked skill development to improve job placements. Greater flexibility was introduced in choosing training centers and courses, making it more accessible to candidates.

- **PMKVY 3.0 (2020-2021):**

PMKVY 3.0 embraced digital technology, offering training online to adapt to the changing landscape brought about by the COVID-19 pandemic. There was a greater emphasis on training for digital and new-age skills, aligning with the evolving job market. A move towards outcome-based skill training was made, ensuring that candidates were not just trained but also assessed and certified for their skills. The funding model was revamped, with an increased focus on quality and transparency.

- **PMKVY 4.0 (Announced):**

In the 2023 budget, the Union Finance Minister announced that the government would be launching PMKVY 4.0, establishing the National Digital Library and more. PMKVY 4.0 continues to adapt to the changing needs of the workforce. This phase is designed to promote entrepreneurship and self-employment among the youth. PMKVY 4.0 also aims to provide global mobility to Indian youth by offering skills that are internationally recognized. The scheme will also include new Industry 4.0 courses such as coding, AI, robotics, mechatronics, IOT, 3D printing, drones, and soft skills. On-the-job training, industry partnerships, and course alignment with industry needs will be emphasized. Thirty Skill India International Centers will be established across various states to prepare youth for international opportunities.

PMKVY has evolved over the years to ensure that it remains relevant and effective in equipping Indian youth with the skills needed for employment and entrepreneurship. Each phase has built upon the previous one,

expanding its scope, embracing technology, and addressing the evolving demands of the job market, making it a dynamic and essential program for skill development in India.

**2. Review of Literature-**

Joshi and Pandey (2020), finds that there was a significant relationship between youth's satisfaction and the three components of the PMKVY training i.e., Resources and support, Training quality and Infrastructure. However, many improvements are needed in infrastructure facilities such as better toilets, more classrooms, tools and practice areas, laboratories. This will significantly increase youth satisfaction and training under PMKVY. Bapat and Pandey (2019), attempted to Evaluate the perception of PMKVY beneficiaries and find that the perception of the PMKVY scheme among its beneficiaries is majorly positive. But it has some lacunae that reduce the efficiency of the scheme. Addressing these gaps will improve its effectiveness and help the scheme move one step closer to the goal of completing the youth sector and providing them with better livelihoods. Patnaik, Satpathy and Suhagi (2018) Attempt to understand the importance of ITeS and PMKVY. For this purpose, secondary data is reviewed and the objective of this paper is to conduct an empirical study of Pradhan Mantri Kaushal Vikash Yojana. They observed that the present initiative of PMKVY plays an important role in the life of unemployed people and also helps in improving the skills of the workforce. ITeS is a game changer in this direction. Tripathi M (2021), study the skill development model of India in the context of the Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojna (PMKVY). Found a positive relationship between the actual Human Resource Requirement and the estimated Human Resource Requirement in 22 key sectors. Further observed that there is a significant contribution of the PMKVY scheme in skilling the workforce and a significant number of candidates got placed after training under the PMKVY.

**3. Objectives of the Study-**

The main object of the present paper is to study the effectiveness of the PMKVY and to find out the challenges and areas of improvement for the implementation of PMKVY.

**4. Research Methodology-**

This is a secondary data-based research paper. The data obtained from PMKVY reports, NSDC reports, research articles and other research reports, have been classified and analyzed to fulfill the objectives of the study.

**5. Analysis -**

**Skill Development and job placement:**

Skill development and job placement are two fundamental aspects of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) program, which aims to empower India's youth with employable skills. PMKVY offers a diverse range of skill development programs across various sectors, including manufacturing, healthcare, agriculture, information technology, and more. These programs are designed to equip candidates with industry-relevant skills through training provided by authorized centers. While equipping candidates with skills is crucial, PMKVY also focuses on connecting them with employment opportunities. Job placement is a critical aspect, and PMKVY addresses it through various strategies.

**Table No. 01 Skill development and job placement under PMKVY**

| Phase | Enrolled candidate | Completed training | Assessed | Certified | Placed |
|---|---|---|---|---|---|
| PMKVY 1.0 (2015-16) | 19,86,016 | 19.86,016 | 19,51,487 | 14,51,636 | 2,66,826 (18.38%) |
| PMKVY 2.0 (2016-20) | 1,14,84,724 | 1,10,00,708 | 99,20,742 | 91,57,547 | 21,41,575 (23.38%) |
| PMKVY 3.0 (2020-21) | 7,94,976 | 7,37,502 | 5,82,629 | 4,31,808 | 42,909 (9.93%) |
| Total | 1,42,65,716 | 1,37,24,226 | 1,24,54,858 | 1,10,40,991 | 24,51,491 (22.20%) |

Source- PMKVY Dashboard https://www.pmkvy official.org/ Till 09 September 2023

Under PMKVY 1.0 (2015-2016), a total of 19,86,016 candidates were enrolled for training while 19.86,016 completed the training whereas 19,51,487 candidates were assessed and 14,51,636 were certified and 2,66,826

among them were reportedly placed which is 18.38%. Under the second phase, PMKVY 2.0 (2016-2020) there were 1,14,84,724 candidates enrolled whereas 10,10,00,708 completed the training programme and 99,20,742 were assessed but 91,57,547 out of them certified. 23.38% were placed after the completed training.

This is one of the major developments coming from this scheme. In July 2020, PMKVY 3.0 was approved by the government. It has approved a budget of Rs 948.9 million for training 800,000 candidates in the financial year 2020-2021. Skill Implementation of this program started from January 15, 2021. Total 7,94,976 enrolled under this phase of the scheme and 4,31,808 were certified which is 54.31%. Among total certified candidates, 9.93% were placed. PMKVY is a comprehensive initiative that not only imparts valuable skills to India's youth but also strives to connect them with meaningful job opportunities, contributing to their economic empowerment and the nation's growth.

**Recognition of Prior Learning (RPL):**

RPL is a significant component of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY). RPL is designed to acknowledge and certify the existing skills and knowledge of individuals, particularly those who have acquired skills through informal means, work experience, or other non-formal channels. Here's a closer look at RPL under PMKVY:

The primary goal of RPL is to provide formal recognition and certification to individuals for skills they already possess but haven't been certified for. It aims to bridge the gap between formal and informal learning by giving due credit to an individual's practical skills and experience.

RPL assessments are conducted by certified assessors who evaluate candidates based on industry-recognized standards. Candidates undergo a skill assessment, and if they meet the required criteria, they receive a formal certificate that validates their skills. This recognition allows individuals to enhance their employability and access better job opportunities.

Individuals interested in RPL can approach PMKVY-approved training centers or assessors. The assessors evaluate the candidate's skills and knowledge through practical assessments, interviews, and other relevant methods. If the candidate meets the required standards, they receive a certification that is nationally recognized. RPL is inclusive, allowing people from various backgrounds and age groups to participate. It promotes lifelong learning by encouraging individuals to continuously update their skills.

**Table No 02 training under RPL**

| Phase | Enrolled candidate | Completed training | Assessed | Certified |
|---|---|---|---|---|
| PMKVY 1.0 | 1,81,810 | 1,81,810 | 1,77,988 | 1,19,157 |
| PMKVY 2.0 | 62,72,669 | 61,41,870 | 54,08,281 | 51,21,000 |
| PMKVY 3.0 | 2,65,766 | 2,62,705 | 2,05,434 | 1,87,698 |
| Total | 67,20,245 | 65,86,385 | 57,91,703 | 54,27,855 |

Source: PMKVY Dashboard.

RPL benefits individuals by certifying their skills, making them more competitive in the job market. It can lead to career advancement and higher earning potential for those who have valuable but undocumented skills. Employers benefit by having a workforce with certified skills, which can lead to increased productivity and quality of work. It helps in reducing the skills gap by formally recognizing skills acquired outside of traditional education. Total 67,20,245 candidate ware registered under RPL, 65,86,385 were completed training, 57,91,703 were assessed and 54,27,855 candidates were certified under all three phases of PMKVY.

Recognition of Prior Learning (RPL) is an integral part of PMKVY that recognizes and certifies the skills individuals already possess, contributing to their employability and career growth. It also benefits employers by ensuring that their workforce is skilled and competent. RPL plays a crucial role in promoting lifelong learning and bridging the gap between formal

education and real-world skills.

**Rozgar Mela -**

In the PMKVY Program, social and civic mobilization is of paramount importance. Enhancing transparency and accountability, active involvement of the Community will help to exploit its collective knowledge in order to be able to work more effectively. In the light of these considerations, PMKVY has made specific reference to the involvement of target beneficiaries through a defined mobilization process. With a view to giving candidates an understanding and advice on the courses, DSMs and SSDMs organize training for them before they are enrolled.

Kaushal Mela is a camp approach where awareness building and recruitment of qualified candidates are carried out. These training events provide information on different skill development options that are available under the PMKVY scheme as well as an overview of possible career paths and potential income generating opportunities.

Rozgar Melas are usually held in large assembly rooms with booths for each employer. Each booth will normally be manned by several representatives from the firm and, as they engage in conversation with applicants, at least two of them shall stand next to tables. The Rozgar Melas are also Organised online so that job opportunities can be accessed quickly and easily at the click of a button. The Rozgar Melas range in size from 5 to 100 employers. Rozgar Melas Organised by the DSC and SSDMs to provide good career opportunities for candidates will take place at PMKVY 3.0.

**Table No. 03 Rozgar Melas**

| No | Detail | Parliamentary Constituency Level | District Level | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozgar Melas Conducted | 914 | 43 | 957 |
| 2 | Candidates Registered | 162194 | 3716 | 165910 |
| 3 | Candidates Selected | 72349 | 1908 | 74257 |

Data as per the reports from April 2018 – February 2020, Source- https://www.pmkvy official.org/rozgar-kaushal-mela

Rozgar Melas provides a valuable opportunity for candidates to showcase their newly acquired skills and for employers to identify talent that matches their specific requirements. Under PMKVY, Rozgar Mela Organised at two different level first is Parliamentary Constituency and second is district level with the help DSC and SSDMs. Total 957 Rozgar Mela Organised under PMKVY, as there are 914 under Parliamentary Constituency Level and 43 district level. There were 1,65,910 candidates registered for the Rojgar Mela and 44.5% candidate were selected for different job role. These events facilitate the exchange of information and job offers, leading to job placements and career advancement for many participants. Rozgar Melas under PMKVY not only bridge the gap between skilled individuals and employers but also contribute to reducing unemployment and boosting economic growth by ensuring that skills developed through the program translate into meaningful employment opportunities.

**Challenges and Areas for Improvement:**

While Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) has made significant strides in skill development and job placement, it faces several challenges and areas for improvement: Some areas that require attention include:

**I. Quality Assurance:** Ensuring the consistent quality of training across all centers remains a challenge. Maintaining high standards is essential for the program's long-term success. To address this challenge, PMKVY must strengthen its quality control mechanisms, establish standardized training practices, and regularly monitor and evaluate the performance of training centers. Ensuring that the skills imparted through PMKVY meet industry standards and employer expectations is crucial for the long-term success and impact of the program, making quality assurance an essential focus area for improvement.

**II. Geographical Disparities:**

Geographical disparities pose a significant challenge to the effective implementation of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY). While the program has made strides in urban areas, rural and remote regions continue to face limited access to skill development opportunities. The concentration of PMKVY centers and resources in urban hubs often leaves candidates from rural backgrounds at a disadvantage, hindering their ability to access quality training. Addressing this challenge requires a concerted effort to expand the program's reach to underserved regions, ensuring that skill development is accessible to all, regardless of their geographical location. Bridging these disparities is essential for PMKVY to fulfill its goal of equipping India's youth with the skills they need to succeed in the job market and contribute to the nation's economic growth.

**III. Employer Engagement:** Employer engagement stands out as a notable challenge for the PMKVY. Active collaboration with employers is vital for fine-tuning training programs, ensuring that candidates receive education that precisely matches industry requirements, and facilitating job placements. To address this challenge, PMKVY needs to actively engage with a broader spectrum of industries, understand their evolving needs, and foster strong employer relationships. A more significant involvement of the private sector in curriculum design, assessment, and job placement processes can bridge the gap between skill development and actual job opportunities, making PMKVY even more effective in boosting youth employability and economic growth.

**IV. Post-Placement Support:** Providing support and guidance to candidates after job placement is crucial for long-term success. Continuous monitoring of candidates' progress in their careers can help ensure they remain skilled and competitive. Ensuring that these individuals continue to excel in their chosen fields is essential for the long-term impact of PMKVY. Therefore, the program needs to focus on establishing comprehensive post-placement support mechanisms, including mentorship programs, skill upgrading opportunities, and resources for career progression. By addressing this challenge, PMKVY can enhance its effectiveness in not only providing job placements but also ensuring that these placements lead to fulfilling and sustainable careers for its beneficiaries.

**V. Continuity of Learning:** While the program has successfully equipped individuals with essential skills and facilitated job placements, the journey of skill development shouldn't end there. Encouraging a culture of continuous learning and upskilling among PMKVY graduates is crucial in a rapidly changing job market. However, many graduates may struggle to access opportunities for further education or advanced courses. Addressing this challenge entails offering pathways for lifelong learning, advanced skill development, and higher education to PMKVY beneficiaries. By promoting ongoing skill enhancement and adaptability, PMKVY can ensure that its graduates remain competitive and resilient in their careers, contributing to their long-term success and India's economic growth.

While Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana has achieved significant milestones in skill development and job placement, addressing these challenges and focusing on areas for improvement is essential to make it even more effective in shaping India's skilled workforce for the future. Adaptability, quality assurance, inclusivity, and industry relevance should remain at the forefront of PMKVY's efforts to empower India's youth with the right skills for employment and entrepreneurship.

**5. Conclusion** -

PMKVY has made significant strides in imparting skills to millions of Indian youth. The program's focus on diverse sectors, including

manufacturing, healthcare, agriculture, and technology, has allowed candidates to acquire a wide range of skills. This emphasis on skill development has enhanced the employability of beneficiaries and provided them with the tools to excel in their chosen fields. One of PMKVY's key achievements lies in its ability to link skill development with employment. Numerous candidates have successfully secured job placements or ventured into entrepreneurship after completing their training. The program's partnerships with various industries and employers have played a pivotal role in connecting skilled candidates with suitable job opportunities, ultimately boosting the country's workforce.

PMKVY has strived to be inclusive, reaching out to candidates from diverse backgrounds and geographies. Special initiatives have been launched to empower women through skill development programs tailored to their needs. This inclusivity has not only broadened the program's reach but also contributed to gender equality in the workforce. The introduction of Recognition of Prior Learning (RPL) has been a notable success of PMKVY. RPL enables individuals with prior experience to receive formal recognition and certification for their skills. This has been particularly beneficial for those who had acquired skills through informal means and were previously unrecognized in the job market. PMKVY's future looks promising with the introduction of PMKVY 4.0. This phase aims to promote entrepren eurship and self-employment among youth, further expanding their horizons. It also strives to provide skills that are internationally recognized, opening doors to global opportunities.

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana has undeniably made a significant impact on India's youth by equipping them with essential skills and enhancing their employability. While challenges persist, the program's continued evolution and adaptability demonstrate the government's commitment to fostering a skilled and capable workforce. With a proactive approach to address shortcomings and capitalize on emerging opportunities, PMKVY is well-poised to play a pivotal role in India's journey towards economic growth and prosperity.

**Reference-**


- Joshi A.K., Pandey K. N., (2020), Awareness, Perceptions and Youth Mobilization towards PMKVY Training in Haryana, International Journal of Management (IJM), Vol.11, Issue11, pp 2528-2537. http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=11
- Bapat S, Pandey A., (2019), Evaluating the perception of PMKVY beneficiaries, International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM), Vol: 03 Issue: 11 ISSN: 2590-1892
- Patnaik M., Satpathy and Suhagi S., (2018), Role of ITeS in Pradhanmantri Kaushal Vikash Yojana (PMKVY): A Conceptual Study, International Journal of Mechanical Engineering and Technology 9(8), 2018, pp. 907–914.
- Tripathi M., (2021), Effectiveness of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna in Bridging the Skill Gap of Workforce in India, Sambodhi, Vol. 44, No.1, pp. 304, ISSN: 2249-6661
- Bhuvana S., Kavya and Geetanjali P. (2019). A Study on Effectiveness of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna Centres in Bengaluru Regions, UAS - JMC, 4 (2), 22-25
- Mahipatsinh D. Chavda and Bharat S. Trivedi, (2015), Impact of Age on Skills Development in Different Groups of Students, International Journal of Information and Education Technology, Vol. 5, No. 1.
- Thakur, K.S. and Agrawal, Mini. (2019). Impact of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna on the Productivity of Youth in Gwalior Region, India. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (4), 801-806.

➢ B.C. M. Patnaik, Ipseeta Satpathy and Snigdha Suhagi (2018). Role of ITES in Pradhanmantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY): A Conceptual Study, International Journal of Mechanical Engineering and Technology 9(8), 907–914

➢ Agrawal M, Singh C, Thakur KS. (2020), Demographic Dividend: Skill Development Evidence in India. SSRN Electronic Journal.; vol. 4(2):pp. 18-24.

❑❑❑

**07**

# गृहविज्ञान की कौशल आधारित शिक्षा प्राप्ति से बढ़ते रोजगार के अवसर

**डॉ अनुराधा अवस्थी**
सह प्राध्यापक (गृह विज्ञान)
शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला भवन, इंदौर

**********

**शोध सारांश :**

वर्तमान समय में प्रत्येक युवती शिक्षा प्राप्त कर के आत्मनिर्भर होना चाहती है और किसी न किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त करना चाहती है, इससे जहाँ एक ओर परिवार की आय में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण और विकास में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती है परिणामस्वरूप देश का विकास होता है। जब परिवार की गृहिणी घर के बाहर जा कर रोजगार करती है तो उसे घर और परिवार से संबंधित कार्यो के लिये कम समय मिलता है और ऐसे में वह घरेलू कार्यों के लिये परिवार के बाहर के व्यक्तियों एवं संस्थाओं से सहायता लेती है और इन परिस्थितियों ने गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त छात्राओं के लिये रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न कर दिये हैं, जैसे–जैसे महिलाओं की शिक्षा एवं रोजगार बढ़ रहे हैं इनमें और वृद्धि होती जा रही है। गृह विज्ञान की शिक्षा कौशल आधारित शिक्षा है जिसमें भोजन पकाने के अतिरिक्त, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, छपाई, बच्चों की देखभाल, निर्देशन एवं परामर्श के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की ललित कलाऐं, इंटीरियर डिजाइनिंग, पुष्प सज्जा, रंगोली अल्पना, नक्शे बनाने आदि के कौशल सिखाये जाते हैं जिन्हें सीख कर छात्राऐं विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं जो कि इस प्रकार है :—

**गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों में रोजगार के अवसर**

**(अ) आहार एवं पोषण में रोजगार के अवसर :**

आहार एवं पोषण विज्ञान गृह विज्ञान संकाय

का सबसे लोकप्रिय विषय है। वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली इतनी व्यस्त एवं अनिश्चित हो गई है कि हम अपनी प्रथम आवश्यकता भोजन को भी अनेक बार उपेक्षित कर देते हैं, इसी के संबंध में जानकारी और जागरूकता के अभाव में समस्याओं का सामना करना होता है। भोजन और पोषण के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करके छात्राऐं निम्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं :—

(१) डायटीशियन या पोषण अधिकारी के रूप में विभिन्न अस्पतालों, हैल्थ क्लब/जिम, और पोषण उत्पाद बनाने वाली कंपनियों में कार्य कर सकती है।

(२) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र संघ में पोषण सलाहकार एवं पोषण अधिकारी के रूप में कार्य कर सकती हैं। छात्राऐं इनके विभिन्न प्रोजेक्ट जो समुदाय में चलाये जाते हैं उनमें नियुक्ति पा सकती है।

**(३) पोषण पुर्नवास केन्द्र** :— राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में कुपोषण को कम करने हेतु बच्चों के लिये चलाये जाने वाले पोषण पुनर्वास केन्द्र में छात्राऐं पोषण अधिकारी बन सकती है।

**(४) फूड साईन्टिस्ट** :— विभिन्न भोज्य उत्पादों का प्रमाणीकरण करने वाली संस्थाओं और फूड एनालिसिस करने वाली संस्थाओं में फूड साईन्टिस्ट बन सकती है।

**(५) शिक्षक** :— आहार एवं पोषण विज्ञान अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है जैसे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, योग आदि। इन विषयों का ज्ञान देने वाली संस्थाओं में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य किया जा सकता है।

**(६) क्वालिटी कन्ट्रोलर** :— विभिन्न भोज्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों को बनाने वाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में क्वालिटी कन्ट्रोलर का कार्य किया जा सकता है।

**(ब) वस्त्र तन्तु विज्ञान में रोजगार के अवसर** :—

वस्त्र मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। आज के युग में वस्त्र तथा परिधान का महत्त्व बहुत बढ़ गया है क्योंकि परिधान को व्यक्तित्व का अंग माना जाने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति आकर्षक एवं फैशनेबल परिधान पहनना चाहता है, मनुष्य की इसी इच्छा ने इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत से अवसर उत्पन्न कर दिये हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार है :—

**(१) फैशन डिजाइनर** :— प्रत्येक व्यक्ति आधुनिक एवं फैशनेबल परिधान सिलवाना एवं पहनना चाहता है इसलिये वस्त्र तन्तु विज्ञान के क्षेत्र में निपुण छात्राऐं डिजाईनर बन सकती है। वे फैशन इलेस्ट्रेशन सीख कर नये नये डिजाइन विकसित करती हैं।

**(२) परिधानों की रंगाई एवं छपाई** :— आधुनिक समय में परिधानों को घरेलू स्तर पर आसानी से रंगा और छापा जा सकता है अत: छात्राएं घरेलू स्तर पर स्क्रीन ब्लॉक या स्टेन्सिल छपाई एवं रंगाई का लघु उद्योग चला सकती है।

**(३) कढ़ाई एवं सिलाई का बुटिक** :— परिधानों को अनोखा बनाने और आकर्षण उत्पन्न करने के लिये कढ़ाई एवं सिलाई का उपयोग होता है, इन्हें सीख कर घर पर ही परिधानों की सिलाई का उद्योग बहुत कम पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है।

**(४) ऐसेसरीज़ डिजाईनर** :— आजकल परिधान के साथ ही डिजाईनर जूते, पर्स, बेल्ट, बकल, हेयरक्लिप, हेयर बैन्ड, साड़ी पिन जैसी ऐसेसरीज उपयोग में लाई जाती है। बहुत कम पूंजी से इनके निर्माण का लघु उद्योग खोला जा सकता है।

**(५) वस्त्र टेस्टिंग और प्रामाणीकरण संस्थाओं में रिसर्च ऐैनेलिस्ट** :— सभी वस्त्र और परिधान बनाने वाली कंपनियों के क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग में टैक्स्टाईल टेस्टिंग का ज्ञान प्राप्त छात्राऐं रिसर्च ऐैनेलिस्ट बन सकती है।

**(६) परिधानों का व्यापार** :— विभिन्न वस्त्र बनाने वाली कंपनियों और रेडिमेड वस्त्र बनाने वाली कंपनियों के वस्त्र क्रय करके स्थानीय बाजारों में या घर से बिक्री करके धन अर्जित किया जा सकता है। बहुत सी गृहिणियाँ शहरों में जयपुर की चादेर, कोटा की साड़ियाँ या माहेश्वरी साड़ियाँ खरीदकर मुनाफे के साथ बेच कर धन अर्जित कर रही हैं।

**(७) शिक्षक** — विभिन्न फैशन टेक्नालॉजी से जुड़ी संस्थाएँ और परिधान निर्माण सिखाने वाली संस्थाऐं जैसे पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में शिक्षक का कार्य भी किया जा सकता है।

**(स) पारिवारिक संस्थान प्रबंध के क्षेत्र में रोजगार के अवसर** :—

फैमिली रिर्सोस मैनेजमेन्ट गृह विज्ञान संकाय का यह विषय परिवार और समुदाय में उपलब्ध सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रबन्धन का ज्ञान प्रदान करता है इसकी जानकारी प्राप्त करके छात्राऐं निम्न रोजगार प्राप्त कर सकती हैं :—

**(i) इंटीरियर डिजाईनर :—** पारिवारिक संसाधन प्रबंध के अन्तर्गत कला के तत्वों, डिजाईनिंग के सिद्धान्तों का व्यवस्थित ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान से इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है। इसमें आजकल बहुत संभावनाऐं हैं।

**(ii) सहायक इंटीरियर डिजाईनर :—** इंटीरियर डिजाइनर बनने हेतु स्वयं का ऑफिस खोलना होता है और डिजाइनिंग का विशेष ज्ञान प्राप्त करना होता है जो व्यय साध्य है अत: डिजाईनर के सहायक के रूप में केवल नक्शे बनाने या पर्दे सिलने या पेंटिग्स बना कर एक सहायक के रूप में घर से कार्य करके आय प्राप्त की जा सकती है।

**(iii) इवेन्ट मैनेजर :—** प्रबन्धन का ज्ञान प्राप्त करके कार्यक्रम प्रबन्धक या इवेन्ट मैनेजर का कार्य किया जा सकता है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियाँ सेमिनार, सभा, विवाह, जन्मदिन जैसे कार्यक्रम का प्रबन्धन करती है जो ऐसे छात्र छात्राओ को नौकरी प्रदान करती है जिन्होंने कार्यक्रम प्रबन्धन का ज्ञान प्राप्त किया है।

**(iv) हॉस्पिटेलिटी मैनेजर :—** विभिन्न हॉस्पिटेलिटी या आतिथ्य सत्कार से जुड़ी संस्थाऐं जैसे होटल टूरिज्म और हॉस्पिटल से जुड़ी संस्थाऐं हॉस्पिटेलिटी मैनेजर के रूप में रोजगार देती हैं।

**(v) प्रोजेक्ट ऑफिसर :—** सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाऐं एवं क्लब विभिन्न समाज कल्याण के प्रोजेक्ट चलाती है और वे प्रोजेक्ट ऑफिसर की नियुक्ति करती है।

**(vi) कर्टन डिजाइनर :—** बड़े शहरों में इंटीरियर डिजाइनिंग के लिये विभिन्न प्रकार के पर्दे डिजाइन किये तथा सिले जाते हैं इनका कार्य भी घर से ही कम पूंजी लगा कर किया जा सकता है।

**(vii) नर्सरी/पौधों/पुष्पों की डिजाइनिंग :—** आजकल भवनों में पौधों एवं पुष्पों की सजावट का काम भी बहुत किया जाता है अत: इस क्षेत्र में भी रोजगार के बहुत अवसर है।

**(स) मानव विकास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर :**

मानव विकास विषय मनुष्य के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान देता है। इसमें बाल्यावस्था, पूर्व शालेय अवस्था, शालेय अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढावस्था और वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन के लिये परामर्श एवं निर्देशन भी इसी में सम्मिलित है। इस विषय में निम्न रोजगार के अवसर है :—

**(१) नर्सरी स्कूल या प्ले स्कूल खोलना** —

आजकल छोटे बच्चों की देखभाल में परिवार को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योकि माताऐं घर से बाहर रोजगार करती हैं अत: नर्सरी स्कूल या प्ले स्कूल खोल कर आय अर्जित की जा सकती है।

**(२) डे केयर सेन्टर :—** रोजगार में लगी माताऐं दिन भर के लिये या स्कूल के बाद ऐसे सेन्टर में बच्चों को भेजती है। ऐसे डे केयर सेन्टर भी आय प्राप्ति का एक स्त्रोत होते हैं।

**(३) काउन्सलर :—** बच्चों की देखभाल एवं कैरियर निर्माण में विशेषज्ञ रूप में सलाह देने के लिये काउन्सलिंग सेन्टर खोल सकती है।

**(द) गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर :—**

गृह विज्ञान संकाय का यह विषय उपरांकित चारों विषयों की जानकारी को समाज में प्रसारित करने का ज्ञान प्रदान करती है। गृह विज्ञान के सभी विषय जीवन जीने की कला सिखाते हैं अत: इनसे संबंधित ज्ञान सभी परिवारों के लिये उपयोगी होता है इसलिए समाज कल्याण के दृष्टिकोण से सम्पूर्ण समाज में इनका प्रसार किया जाना आवश्यक है। इस विषय का ज्ञान प्राप्त कर छात्राऐं निम्न रोजगार प्राप्त कर सकती है :—

**(१) स्वयं सेवी संस्थाओं में नौकरियाँ :—**

प्रसार शिक्षा का ज्ञान प्राप्त छात्राऐं विभिन्न समाज सेवी संगठनों के कार्यों में रोजगार प्राप्त कर सकती है। वर्तमान में ऐसी अनेक संस्थाऐं हैं जो

पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और आर्गेनिक उत्पाद बनाने का कार्य कर रही हैं।

**(२) स्वयं सेवी संस्थाओं की स्थापना :—**

छात्राऐं मिलकर अपनी स्वयं सेवी संस्थाऐं बना सकती हैं। विभिन्न प्रकार की कलात्मक कढ़ाई, बुनाई, रंगाई या छपाई का कार्य करने वाली महिलाएं संयुक्त होकर अपना एक समूह बना कर किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर सकती हैं।

**(३) बाल विकास कार्यक्रमों में भागीदारी :—**

आधुनिक समाज में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरुकता बहुत बढ़ गई है इसलिये शासकीय एवं अशासकीय अनेक कार्यक्रम बच्चों तथा महिलाओं के लिये चलाये जाते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में प्रोजेक्ट ऑफिसर या कार्यकर्ता का कार्य किया जा सकता है।

**(४) महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी :**

प्रत्येक जिले में चलाई जा रही शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये आगनवाड़ियाँ चलाई जाती हैं इनके सुपरवाइजर के रूप में नौकरी प्राप्त की जा सकती है।

**(५) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नौकरी :—**

ग्रामीण विकास के लिये ग्रामीण अंचलों में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु गांवों में स्थित कार्यालयों में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

**(६) शोधकर्ता या सर्वेक्षण कर्ता :—**

अनेक समाज सेवी संस्थाऐं तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास से संबधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षण एवं शोध का कार्य करवाती हैं उनके इस कार्य में सहायता करने हेतु प्रसार शिक्षा को ज्ञान रखने वाली छात्राऐं इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं।

इस प्रकार गृह विज्ञान के प्रत्येक विषय का ज्ञान छात्राओं में विभिन्न प्रकार के कौशल सीखा कर उन्हें अनेक क्षेत्रों में कुशलता प्रदान करता है जिससे उन्हें बहुत प्रकार के रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

**References :-**

1. Nikita Joshi, Scope of Home Science, Collegedunia.com

2. Daily Excelsior, Home Science Career Aspects, E-paper 28/08/22.

3. Ranjan K. Baruah Career Options in Home Science, The Sentinel, E-paper

**08**

# गृह विज्ञान और रोजगार

**डॉ. छाया हार्डिया**

**प्रियंका वर्मा**
सहायक प्राध्यापक गृहविज्ञान
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन

***********

**शोध सारांश :**

गृह विज्ञान एक विस्तृत और रोजगार संभावना से युक्त क्षेत्र है। इस विषय से स्नातक और स्नातकोत्तर करने के उपरांत न केवल सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरियां भी हासिल की जा सकती है। बल्कि साथ ही कई प्रकार के रोजगार भी स्वरोजगार भी प्रारंभ किया जा सकते है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा समय—समय पर कई तरह की रिक्तियां प्रकाशित की जाती है। जिसमें सिर्फ गृह विज्ञान की छात्राएं ही आवेदन कर सकती है। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग भी रिक्तियां प्रकाशित करता है जिसमें आवेदन के लिए गृह विज्ञान की किसी भी शाखा में बैचलर अथवा मास्टर डिग्री होनी चाहिए। गृह विज्ञान में करियर में चार क्षेत्र होते हैं— फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट तथा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने पर आप इन्हीं क्षेत्रों में नियोजित हो सकते हैं इसके अलावा बायोकेमेस्ट्री, बायोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, हेल्थ केयर एंड हाइजीन आदि क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता हासिल करके जाब प्राप्त किया जा सकता है। गृह विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद युवतियां गृह विज्ञान पर आधारित लघु उद्योग की शुरुआत करने पर भी अच्छी कमाई कर सकती है।

**कुंजी शब्द** : लघु उद्योग, स्वरोजगार, कौशल

**प्रस्तावना :**

जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गृह

विज्ञान का संबंध घर में रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य तथा उनकी खुशी से संबंधित है, क्योंकि गृह विज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र है। इसलिए इसमें विज्ञान और कला दोनों क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। इस प्रकार गृह विज्ञान अंतर क्षेत्रीय विषय का प्रतिनिधित्व करता है, जो युवा प्रशिक्षण प्रशिक्षणर्थियों को अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने घर तथा अपने परिवार की सही ढंग से देखरेख और जीवन में अपने करियर या व्यवसाय के लिए तैयार होने को प्राप्त करने में सहायता करता है। गृह विज्ञान एक विस्तृत और रोजगार संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है। गृह विज्ञान का अध्ययन हमें ना सिर्फ घर को सुचारू रूप से चलाने का ज्ञान प्रदान करता है, अपितु बच्चों को अपना निजी जीवन संवारने, घर परिवार में सभी के साथ मधुर संबंध रखने तथा पारिवारिक जीवन स्तर ऊंचा उठाने में भी सहायता करता है। साथ ही गृह विज्ञान विषय का ज्ञान बच्चों को रोजगार के लिए भी सक्षम बनाता है गृह विज्ञान के अध्ययन से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हम घर पर रहकर ही कोई स्वरोजगार कर सकते हैं या घर के बाहर किसी संस्था में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। गृह विज्ञान में करियर की अपार संभावनाएं हैं। गृह विज्ञान से रोजगार की राह आसान हो जाती है। गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, जैसे भोजन तथा पोषण, संप्रेषण तथा विस्तार, संसाधन प्रबंध, मानव विकास, वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। हम परिवार के बाहर तथा परिवार के अंदर अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंधों को सिखाते हैं तथा विकसित करते है। हम अपने संसाधनों को जैसे समय, ऊर्जा तथा धन के प्रबंधन की विधि को भी सिखाते हैं ताकि हम परम संतोष को प्राप्त कर सके। गृह विज्ञान में उन कौशलों को सीखने की विधियां भी शामिल है जो हमारे परिवार तथा समुदाय विशेष के रूप से गरीबों के बेहतर जीवन के लिए उपयोगी होती है।

**गृह विज्ञान के प्रमुख पांच घटक या विशेषज्ञ के क्षेत्र निम्न अनुसार हैं—**

➢ आहार तथा पोषण विज्ञान
➢ संसाधन प्रबंधन
ε वस्त्र तथा परिधान विज्ञान
➢ मानव विकास
➢ प्रसार शिक्षा

वर्तमान में गृह विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि प्रत्येक शाखा की अपनी विशेषताएं है। जिनमे विषय विशेषज्ञता एवं व्यवसाय के विभिन्न अवसर मौजूद है। गृह विज्ञान अपनी विषय वस्तु के महत्वपूर्ण भाग को विशुद्ध विज्ञान से प्राप्त करता है जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा स्वच्छता। यह मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामुदायिक विकास, संप्रेषण मीडिया और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में भी विषयवस्तु को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह एक अंतर क्षेत्रीय विषय है जो विज्ञान तथा कला पाठ्यक्रमों से ऊर्जा प्राप्त करता है। विज्ञान और कला का संयोजन गृह विज्ञान के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसमें से कुछ निम्नानुसार है—

➢ परिवार के सदस्यों के बीच अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण
➢ परिवार जिसकी आप देख रहे करते हैं
➢ भजन जो आप कहते हैं
➢ घर जिसमें आप रहते हैं
➢ कपड़े जो आप पहनते हैं
➢ संसाधन जो आप उपयोग करते हैं
➢ आपके आसपास का वातावरण
➢ सफल करियर के लिए कौशल और वातावरण

गृह विज्ञान विषय में उपलब्ध विभिन्न अवसरों का अध्ययन करने से पूर्व हमें रोजगार तथा स्वरोजगार की अवधारणाओं को समझना होगा। इन अवधारणाओं को समझने के लिए एक उदाहरण इस प्रकार है, जैसे एक दर्जी जब अपनी खुद की सिलाई की दुकान खोलना है, तो वह स्वरोजगार कहलाता है, किंतु जब वह वेतन पर किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री में कार्य करता है, तो उसे नौकरी कहते है। वेतन रोजगार का अर्थ है कि आप किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के बदले में वेतन प्राप्त करते है। स्वरोजगार से तात्पर्य है कि आप एक उद्यम के स्वामी स्वयं है तथा उस उद्यम के संचालन तथा वित्त पोषण का कार्य स्वयं करते है।

**गृह विज्ञान के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर—**

गृह विज्ञान से संबंधित कुछ स्वरोजगार इस

प्रकार है—

- खाद्य संरक्षण का व्यवसाय
- कैटरिंग का व्यवसाय
- पाककला कुकिंग सीखना
- विशेषज्ञ के रूप में व्यवसाय
- कैंटीन मालिक के रूप में
- पार्टियों की कैटरिंग सेवा के प्रबंधक के रूप में
- तैयार वस्त्रो का व्यवसाय
- बुटीक मलिक के रूप में
- कढ़ाई का व्यवसाय
- सिलाई कटाई की कक्षाएं चलाना
- घरेलू हस्थकला की वस्तुओं का व्यवसाय
- आंतरिक सज्जा का व्यवसाय
- मेहंदी रंगोली पुष्प व्यवस्था आदि की कक्षाएं चलाना
- क्रैच के मालिक के रूप में
- होटल एवं गेस्ट हाउस में स्टाफ
- सुविधा प्रबंधन, गेस्ट हाउस चलाना, घर पर चलने वाली पेइंग्स सेवा प्रदान करना
- नर्सरी स्कूल डे केयर सेंटर बलवाड़ी के मालिक के रूप मे
- समाज कल्याण कार्यक्रम
- खाद्य संरक्षण बकरी तथा कन्फैक्शनरी उत्पादन सेवा
- अतिथि आवास गृह और पेइंग गेस्ट हाउस के मालिक के रूप में
- बच्चों वह महिलाओं की पत्रिकाओं के लेखक के रूप में
- घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ना
- घर से संचालित क्राफ्ट केंद्र हॉबी पाठ्यक्रम कक्षाएं आयोजित करना
- आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुओं का डिजाइनर बनना
- स्वयं की दुकान या उधम चलाना
- घर से ही भोजन सेवा
- सामाजिक उद्यमी प्रशिक्षण तथा सुविधा प्रदाता
- परामर्शदाता
- विपणन अनुसंधान एजेंसियां मीडिया उत्पादन तथा प्रबंधन संप्रेषण तथा विकास परामर्शदाता
- वस्त्र सजावट, सॉफ्ट टॉयज बनाने की कक्षाएं चलाने के रूप में
- विज्ञान उपहार की पैकिंग ताजा व सूखे गुलदस्ते विक्रय करता के रूप में
- उपभोक्ताओं के अधिकारों के सलाहकार के रूप में

**गृह विज्ञान के क्षेत्र में वेतन रोजगार के अवसर—** गृह विज्ञान विषय से संबंधित कुछ वेतन रोजगार इस प्रकार हैं—

- किसी खाद्य उद्योग में कैंटीन, रेस्टोरेंट या होटल आदि में को किया निरीक्षक के रूप में
- अस्पताल आदि में आहार विशेषज्ञ के रूप में
- कैंटीन, रेस्टोरेंट या होटल में आहार विशेषज्ञ के रूप में
- स्कूल कॉलेज में अध्यापन, पॉलिटेक्निक में अध्यापन
- प्रसार तथा संप्रेषण विकास संगठन में स्टाफ परामर्शदाता
- पैटर्न मास्टर, रंगरेज, दर्जी और कढ़ाई करने वाले के रूप में
- प्रिंटर और बुनकर के रूप में
- परिरक्षित व प्रसंस्कृत भोजन इकाई के मालिक के रूप में
- परामर्शदाता
- ड्रेस डिजाइनिंग गारमेंट निर्माण टेक्सटाइल डिजाइनिंग
- व्यावसायिक केदो बैंक ऑफिस दुकान होटल आदि में आंतरिक सज्जाकार के रूप में
- शिल्पकार के रूप में
- प्रसार तथा संप्रेषण विकास संगठन में स्टाफ परामर्शदाता
- जनसंपर्क तथा मानव संपर्क विभाग में स्टाफ
- रसोईया सर्विस स्टाफ, कैटरिंग रेस्टोरेंट कॉफी टी शॉप आदि का स्वामी
- हाउसकीपर के रूप में
- एक्सपोर्ट हाउस में स्टाफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग इकाई में स्टाफ
- बचत व निवेश योजनाओं के प्रतिनिधि के रूप में

- नर्सरी स्कूलों, डे केयर सेंटर, बलवाड़ी के कर्मचारियों के रूप में
- क्रैच में सहायक के रूप में
- किंडरगार्टन में अध्यापक के रूप में
- गृह विज्ञान महाविद्यालय व गृह विज्ञान विषय पढ़ने वाले विद्यालयों के प्रयोगशाला सहायक के रूप में
- ड्राई क्लीनिंग की दुकान में कर्मचारियों के रूप में
- गृह विज्ञान प्रसार कर्मी के रूप में
- टीवी या रेडियो कलाकार के रूप में
- अनुसंधान संहिता के रूप में
- कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में
- सरकारी एंपोरियम शोरूम एंटीक शॉप्स में कर्मचारी
- उत्पादन इकाइयों में कर्मचारी

**सारांश —**

गृह विज्ञान एक विस्तृत और रोजगार संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है। गृह विज्ञान का अध्ययन हमें ना सिर्फ घर को सुचारू रूप से चलाने का ज्ञान प्रदान करता है। अपितु बच्चों को अपना निजी जीवन संवारने, घर परिवार में सभी के साथ मधुर संबंध रखने तथा पारिवारिक जीवन स्तर ऊंचा उठाने में भी सहायता करता है। साथ ही गृह विज्ञान विषय का ज्ञान बच्चों को रोजगार के लिए भी सक्षम बनाता है। गृह विज्ञान के अध्ययन से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हम घर पर रहकर ही कोई स्वरोजगार कर सकते हैं या घर के बाहर किसी संस्था में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। गृह विज्ञान में करियर की अपार संभावनाएं हैं। गृह विज्ञान से रोजगार की राह आसान हो जाती है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ—**

1- www-jansatt-com
2- hindi-webdunia-com/career&options
3- navbharattimes-indiatimes-com
4- httpp://www-jagranjosh-com

❑❑❑

**09**

# व्यवसायिक शिक्षा तथा नवीन शिक्षा नीति

**डॉ. गोमती चेलानी**
प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर

**********

**सारांश :**

मनुष्य की समस्त क्षमताओं के विकास हेतु शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, ताकि एक समान तथा न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इस सर्वांगीण विकास के अन्तर्गत आर्थिक उन्नति, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक समानता की स्थापना, तथा राष्ट्रीय एकीकरण के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा सम्मिलित है।

आज हम ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकि ज्ञान के तीव्रतर विकास के दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण में वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास के कारण हमें अपनी ऊर्जा, भोजन, जल तथा स्वच्छता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन कौशलयुक्त श्रम की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा का समावेष अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्तुत शोधपत्र में नवीन शिक्षा नीति (२०२०) के न्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा के समायोजन पर विचार किया जाएगा। इस हेतु नवीन शिक्षा नीति के अन्तर्गत विद्यमान विविध प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा तथा उन प्रावधानों के गुण दोषों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा

**परिचय :**

सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के साथ साथ उसके समाड तथा राष्ट्र के उत्थान हेतु अत्यंत आवश्यक है। नवीन शिक्षा

नीति (२०२०) के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा के विविध तत्वों पर पुनर्विचार किया गया है जिससे उसे सर्वसुलभ, लचीला, समसामयिक, प्रासंगिक, समावेषी तथा रचनात्मक बनाया जा सके।

**व्यवसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति :**

वर्तमान में भारत में २२०४ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लगभग १२१०८ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्तान, १४६३ सरकारी पॉलीटेक्नीक, २५२३ निजी पॉलीटेक्नीक, लगभग ७३८ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना केंद्र हैं। इसके बावजूद बारहवीं पंचवर्षीय योजना (२०१२—१७) के अन्तर्गत यह अनुमानित किया गया था कि भारत के १९ से २४ वर्ष के आयु समूह में कार्य करने वाले व्यक्तियों के केवल ५ प्रतिशत को औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सकी है, जबकि डेनमार्क में यह ५० प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह ५२ प्रतिशत, जर्मनी में ७५ प्रतिशत तथा दक्षिण कोरीया में ९६ प्रतिशत है। १

ये आंकड़े भारत में व्यवसायिक शिक्षा के तत्काल विस्तार की आवश्यकता को दर्शाते हैं। भारत में औपचारिक व्यवस्यायिक शिक्षा के प्रतिशत की अल्पता का एक कारण यह है कि यहां व्यवसायिक शिक्षा का प्रारंभ कक्षा ११वीं से किया जाता है तथा कक्षा ११वीं तक अनेक विद्यार्थी शिक्षा छोड़ चुके होते हैं। शेष बचे विद्यार्थियों में से भी बहुत कम विद्यार्थी ११वीं तथा १२वीं में प्राप्त व्यवसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा के स्तर तक आगे तक जारी रख पाते हैं। व्यवसायिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू न कर पाने का एक अन्य कारण यह है कि व्यवसायिक शिक्षा को अकादमिक शिक्षा की तुल्ना में निम्न श्रेणी का माना जाता था और इसे केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त माना जाता था जो पढ़ाई में अधिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे या जो कक्षा ८ के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे।

नवीन शिक्षा नीति के अन्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा हेतु एक बड़ा लक्ष्य यह रखा गया है कि वर्ष २०२५ तक ५० प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा। इस विशाल लक्ष्य की प्राप्ति किस हद तक संभव हो पाएगी, यह तो समय ही बता सकता है। इसके अतिरिक्त अब सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) में व्यवसायिक शिक्षा को भी शामिल कर दिया गया है। पूर्व में केवल सामान्य शिक्षा को ही इसमें शामिल किया जाता था।

नवीन शिक्षा नीति के अन्तर्गत कक्षा छठवीं से ही व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसे पूर्व व्यवसायिक शिक्षा की संज्ञा दी गयी है। इस प्रावधान को रखने का उद्देश्य समस्त विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर विविध कौशलों से युक्त प्रशिक्षण के अवसरों से अवगत करना है, जिससे कि वे आगे चलकर अपने रोजगार को आसानी से चुनने में समर्थ हों। शिक्षा के व्यावसायीकरण का विस्तार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त शासकीय तथा शासन से सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों तक किया जाएगा। कक्षा छठवीं से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों को दस दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें स्थानीय विशेषज्ञों जैसे सुतार, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं कक्षा छठवीं से कक्षा बारहवीं तक विद्यार्थियों को इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे। कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में ऐसी समछ का विकास करना है, जिससे वे रोजगार के विभिन्न विकल्पों तथा उन्हें प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों से अवगत हो सकें तथा आगे चलकर व्यवसायिक प्रशिक्षण ग्रहण कर रोजगार प्राप्त करने हेतु तत्पर हो सकें। शिक्षा को श्रम बाजार तथा सामुदायिक सेवाओं से जोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक के द्वारा विद्यार्थी सहायता सेवा का प्रारंभ किया जाएगा।

विद्यार्थियों के कैरियर का चुनाव करने के लिए कौशल आधारित अभिरुचि टेस्ट (Skill Based Aptitude Test SBT) आयोजित किये जाएंगे। व्यवसायिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु सजगता कार्यक्रम (Awareness Programmes) आयोजित किये जाएंगे।

यह पाया गया है कि व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य शिक्षा की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है उन्हीं विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त माना जाता है जो मुख्य शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। नवीन शिक्षा नीति के अन्तर्गत इस दृष्टिकोण को परिवर्तित कर व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य शिक्षा के साथ जोड़ने का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाना है। योजना यह रखी गयी है कि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाए और उच्च शिक्षा में उसे किसी एक व्यवसाय में कुशलता प्राप्त हो सके तथा अन्य अनेक व्यवसायों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हो सके। इससे उनमें श्रम के प्रति सम्मान विशेषकर भारतीय शिल्पकलाओं के प्रति सम्मान के भाव जागृत हो सकें। इतना ही नहीं उनमें व्यवसायिक कौशल के साथ साथ उद्यमिता के कौशल का विकास भी हो सके, ताकि शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात वे अपना व्यवसाय चलाने की स्थिति में हों।

यह प्रयास किया जाएगा कि स्थानीय कलाकार तथा स्थानीय समुदाय विद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करें और विद्यार्थियों को नवीनतम तक्नीकी ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करें। साथ ही विद्यार्थियों को आजीवन नवीनतम ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके लिए सीखो तथा कमाओ (Earn and Learn) की पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिये।

**समुदाय तथा उद्योगों की सहभागिता**

व्यवसायिक शिक्ष, जिसे एक दशक में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना है, को सफल बनाने हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Industrial Training Institute ITI) पॉलीटेक्नीक, कौशल ज्ञान प्रदाता, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, समुदाय के सदस्य, शिल्पी, स्थानीय उद्योग, आदि के साथ समायोजन करना होगा। कुछ विद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाएं बनायी जाएंगी, जिनका उपयोग अन्य विद्यालयों द्वारा भी किया जा सकेगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु भी स्थानीय उद्योगों के साथ समन्वय किया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्ता की जाएगी। इस हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं तथा ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी।

**उच्च शिक्षा स्तर पर व्यवसायिक प्रशिक्षण**

विद्यालयीन शिक्षा की ही तरह उच्च शिक्षा के स्तर पर व्यवसायिक सिक्षा को मुख्य शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थाएं व्यवसायिक शिक्षा या तो स्वयं या स्थानीय उद्योगों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से प्रदान करेंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्योगों की सहभागिता से इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। यहां से विद्यार्थियों को केरीयर मार्ग दर्शन प्राप्त होगा तथा अपना व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु उचित जानकारी व मार्ग दर्शन प्रदान किया जाएगा। स्थानीय साधनों की उपलब्धता तथा स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थाएं कौशल आधारित, जिनमें सॉफ्ट स्किल भी सम्मिलित है, कम अवधि के सर्टीफिकेट कोर्स आयोजीत करेंगी।

भारत में अनेक विद्यार्थी मुक्त विद्यालय (Open School) के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं इसलिए व्यवसायिक शिक्षा को मुक्त विद्यालय के साथ भी जोड़ा जाएगा।

नवीन शीक्षा नीति के अन्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है इसकी मॉनीटरिंग की व्यवस्था। इस हेतु एक ऑनलाईन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों की समस्त जानकारी दर्ज की जाएगी। मॉनीटरींग की इस व्यवस्था से हमें यह ज्ञात होगा कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और किन नये क्षेत्रों में कार्य किया जाना संभव है।

**व्यवसायिक शिक्षा का क्रियान्वयन**

व्यवसायिक शिक्षा के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा (National Skill Qualification Framework NSQF) की स्थापना सन २०१३ में की गयी थी इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित मानकों को भी जोड़ा जाएगा तथा जिन्होंने पूर्व व्यवसायिक शिक्षा

ग्रहण की है उनको भी स्मान्य शिक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी। इस समस्त योजना को चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। सर्व प्रथम व्यवसायिक शिक्षा की वर्तमान स्तिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन के पश्चात हमें यह ज्ञात करना होगा कि हमारी आवश्यकता क्या है। यह कहा जाता है कि विद्यार्थी जब वास्तविक व्यवसायिक जीवन में प्रवेश करता है तब वह अपने विद्यार्थी जीवन में सीखे गये कौशल में से एक अल्प भाग का ही उपयोग कर पाता है अत: हमें एक ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है जो हमारी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो।

भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। यदि इसका एक बड़ा भाग कौशल की दृष्टि से विकसित होगा तो यह देश के साथ साथ विश्व की कौशल संबन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकता है। यह तभी संभव है जब हमारे कौशर विकास कार्यक्रम वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

इसके अतिरिक्त हमें सामान्य शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा के मध्य भेद को समाप्त कर उदोनों को एकीकृत करना होगा। इस एकीकरण को सफल बनाने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी परिवर्तन कर उसे व्यवसायिक शिक्षा के अनुकूल बनाना होगा। व्यवसायिक शिक्षा को सामुदायिक अपेक्षाओं तथा उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की भी आवश्यकता है।

हमें अपने शिक्षण संस्थाओं के आधारभूत ढांचे में परीवर्तन करना होगा। वर्तमान शिक्षण संस्तानों का आधारभूत ढांचा केवल सामान्य शिक्षा के अनुकूल है। कहीं कहीं तो यह सामान्य शिक्षा के अनुकूल भी नहीं है। उसे हमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा के अनुकूल बनाना होगा।

हमें अपने पाठ्यक्रम को भी व्यवसायिक शिक्षा के अनुसार तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परीवर्तित करना होगा। इसके साथ ही हमें मूल्यांकन की पद्दति में भी परीवर्तन करने की आवश्यकता है व्यवसायिक शिक्षा का मूल्यांकन केवल वार्षिक मूल्यांकन पद्धति से नहीं किया जा सकता। इस हेतु सतत् तथा प्रक्रितिगत मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता है। न केवल विद्यार्तियों का अपितु कौशल के पाठ्क्रम का सतत मूल्यांकन आवश्यक है ताकि उसे समय की आवश्यकताओं के अनुसार परीवर्तित किया जा सके।

**निष्कर्ष** : यह तथ्य सर्वमान्य है कि वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा भी अत्यन्त आवश्यक है। नवीन शिक्षा नीति के अन्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है तथा कक्षा छठवीं से ही विद्यार्थियों के लिए कोई न कोई व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। इस हेतु जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनकी पूर्ति हेतु विद्यार्थी, समाजस स्वयंसेवी संस्थाएं तथा शासन के सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है।

**सन्दर्भ सूची** :

1- National Education Policy 2020 Ministry of Human Resource Development – Government of India

2- Reimagining vocational education – Background paper for Teacher's fest- NCERT

❑❑❑

**10**

# डेयरी उद्योग, दुग्ध उत्पादन इकाई में स्वरोजगार के अवसर

**डॉ. राजमल सिंह राव**
सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी (मप्र)

***********

**प्रस्तावना —**

भारत कृषि प्रधान देश है यहाँ समेकित कृषि पर कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन किया जाता है, जिससे पशुपालन और कृषि दोनों को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। भारत में गुजरात की आमूल दुग्ध डेयरी पुरे देश की रोल माडल डेयरी है जो आजादी के समय से पूर्व से ही दुग्ध उत्पादन कर रही है, इसकी स्थापना दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गिस कुरियन ने की थी इसको माडल मानते हुए पुरे देश में दुग्ध व्यवसाय का प्रचार प्रसार इसी से होता है। डेयरी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में दुग्ध बेचकर धन कमाकर उस धन को स्वतंत्रता संग्राम में लगे है, मध्य प्रदेश में भी शासन के सहकारिता विभाग द्वारा संचालित साँची दुग्ध संघ से पुरे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन कर व्यवसाय किया जाता है, डेयरी व्यवसाय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का सबसे आसन उद्योग है। नौकरी से थक हारकर या फिर नौकरी से पहले ही आप अपने बिजनेस में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो डेयरी का व्यवसाय आपके लिए सही साबित हो सकता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और २०२६ तक ये इंडस्ट्री ३१४ अरब डॉलर यानी २६ लाख करोड़ रुपये की हो जाएगीद्य सरकार ने इसके लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए फंड भी जारी किया है. अगर आप डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें. यहां आपको इस बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है. डेयरी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको अपने आसपास के इलाके में लोगों की डेयरी संबंधी जरूरतों को समझना होगा. अगर आपके इलाके में खुले दूध की बजाय लोग पैकेट बंद दूध लेना ज्यादा पसंद करते हैं तो आप फिर अमूल, साँची या मदर डेयरी जैसी कंपनियों से संपर्क कर सकते हैंद्य  जो आपसे सारा दूध खरीद कर अच्छा दाम आपको देंगीद्य साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि किस पशु के दूध की कीमत आपको ज्यादा मिल रही है. जैसे भैंस का दूध गाय के दूध से महंगा बिकता है तो उसमें मुनाफा भी अधिक होने की उम्मीद है।

**कृषि आधारित उद्योग —**

दुग्ध उद्योग कृषि आधारित व्यवसाय है। यदि कृषि को लाभ का धंधा बनाना है तो कृषि के साथ पशु पालन करना होगा, यह देखा गया है की कई कृषक खेती तो करते है परन्तु पशुपालन नहीं करते है एसे में किसानो को खेती में मुनाफा कम होता है। कृषि से निकलने वाला लीटर, भूसा, चारा, पशु चारे के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। और पशुओ का उत्सर्जी पदार्थ, गोबर, आदि हमें जैविक खाद के रूप में व बायोगैस उत्पादन में उपयोग में आ जाता है। इस प्रकार समेकित कृषि पशुपालन के साथ—साथ करने से कृषि व पशुपालन से अधिक लाभ कमाया जा सकता है।

**दूध उत्पादन व्यवसाय में लाभ एवं हानि —**

दुग्ध उत्पादन उधोग सफल कारोबार है। हमें केवल दूध उत्पादन के कारोबार को शुरु करने से पहले योजनाओं, प्रभावी रणनीतियों को बनाने, और उसके अनुसार अपने मस्तिष्क को तैयार करने की आवश्यकता है। यह बहुत अधिक महँगा कारोबार नहीं है और किसी के भी द्वारा, जो इसके बारे में अच्छे से जानता हो, तो उसके द्वारा इसकी शुरुआत थोड़ी सी पूँजी लगाकर की जा सकती हैय हालांकि, इसे १००% सफल बनाने के लिए, एक व्यक्ति को भीड़ में दौड़ने और बन्द आँखों के साथ अपना कारोबार शुरु करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक व्यक्ति जो गंभीरता से इस व्यवसाय को शुरु करना चाहता है, तो उसे व्यापार शुरु करने से पहले अपनी आँखों को खोलने, पक्ष—विपक्ष का विश्लेषण करने, इस कारोबार के बारे

में सबकुछ विस्तार से जानने और आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है। यदि हम सही तरीके की रणनीति के साथ दुग्ध उत्पादन को शुरु करेंगे, निश्चय ही हम इसमें बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे। और आसानी से स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।

१. मानवीय शक्ति को प्रभावी तरीके से प्रयोग करना और उन्हें सकारात्मक तरीके से मन लगाकर पशुपालन करना

२. प्रजनन, भोजन देने, देखभाल करने, अस्वस्थ्य पशुओं को स्वस्थ पशुओं से बदलने और अन्य सामान्य प्रबंध का स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से करना।

३. कृषि उत्पादों के निपटाने का कुशल तरीका अपनाना

४. अच्छी व्यवसायिक योजना बनाना

५. फार्म हॉउस तैयार करना

**निश्चित लक्ष्य और रणनीति तय करना —**

दूध उत्पादन के व्यापार को शुरु करने से पहले आपको रणनीतियों, उद्देश्यों, योजनाओं को निर्धारित करने की आवश्यकता है। ऐसा करना, आपको सही रास्ते पर अपने व्यापार को चलाने में मदद करने के साथ ही असफलता के ऊपर सफलता के अवसर में वृद्धि करता है। दूध उत्पादन कोई आसान क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह लोगों के लिए खाद्यान्न उत्पादकों के व्यापार से संबंधित होता है। लोगों और खाद्यान उद्योग की ऊंची उम्मीदों के लिए दुग्ध उत्पादक व्यापारी के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य कच्चे दूध और दूध उत्पादकों की सुरक्षा और गुणवत्ता होना चाहिए। अनुकूल दशाओं के अन्तर्गत अच्छी स्वास्थ्य दशाओं के सहित स्वस्थ पशुओं से स्वास्थ्यवर्धक दूध प्राप्त करने की निश्चितता होनी चाहिए।

वे लोग जो इस व्यवसाय में कार्यरत हैं, वे एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रबंध प्रणाली के भी हिस्से होने चाहिए। अच्छी कृषि प्रणाली, स्वास्थ्य और पशुपालन प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता है। पशुओं को रोगों से बचाने के लिए इनकी देखभाल पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय को शुरु करने से पहले उद्देश्यों को निर्धारित करना, प्रबंध के लिए आवश्यक सभी क्षेत्रों को घेरने में व्यापारी की मदद करते हैं। दूध उत्पादन के व्यापार के लिए ध्यान देने वाले कुछ बिन्दु निम्नलिखित है जिन्हें फॉर्म हॉउस में प्रबंधन करना चाहिएरू—

१. फार्म हॉउस का बुनियादी ढांचा तैयार करना

२. उत्तम ब्रिड की पशु प्रजातियाँ का चयन करना

३. पशुओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा का रखरखाव करना

४. दूध निकालते समय स्वच्छता का ध्यान रखना

५. पशुओं के चारे व पानी की व्यवस्था का प्रबंधन करना

६. पशु कल्याण और अनुकुलतम वातावरण का प्रबंधन करना

७. कुशल और ज्ञान रखने वाले कर्मचारी को रखना

८. पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए प्रभावी नियंत्रक उपाय टीकाकरण करना

९. कुल व्यय और लाभ आदि का खाता प्रबंध करना

१०. उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी नियंत्रक बिन्दु

**उद्योग शुरू करने के लिए जरुरी आवश्यक सामग्री—**

डेयरी उद्योग शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है की आपके पास कृषि भूमि होना चाहिए यदि ज्यादा कृषि भूमि नहीं है तो लगभग ५०००० वर्ग फिट भूमि हॉट तो भी आप दुग्ध उद्योग की लघु यूनिट टायर कर सकते है, जो ५—१० पशुओ की हो सकती है, यदि बड़े पैमाने पर उद्योग करना है तो लगभग २ एकड़ कृषि भूमि की आवश्यकता होती है। डेयरी उद्योग प्रारम्भ करने के लिए निम्नांकित आवश्यकता होती है।

१. व्यापार शुरु करने के लिए आवश्यक पूँजी होना जरुरी है ।

२. व्यापार शुरु करने से पहले पूँजी के अनुसार मापदंडों का निर्धारण करें।

३. व्यापार का उद्देश्य, प्रकृति और लक्ष्य के

साथ प्रबंध करे।

४. व्यवसाय संचालन की प्रक्रियाओं लक्ष्य के अनुसार रखे।

५. व्यापार की प्रक्रिया के प्रबंध और नियंत्रण के लिए प्रभावी तरीके अपनाएं।

६. कर्मचारियों के लिए कार्य करने के लिए अच्छा कार्यशील वातावरण बनाये रखे।

७. पशुओं के रहने के लिए कृषि फार्म में अनुकूल वातावरण रखे।

८. कराधान दायित्वों में कमी नहीं होना चाहिए।

९. व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक स्तर की ऊर्जा।

**डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार रुप में दूध उत्पादन के व्यापार को शुरु करने से पहले ध्यान देने योग्य प्रमुख बिंदु —**

१. आपको व्यापार योजना को विकसित करना चाहिए। और ताकत (स्ट्रेंथ), कमजोरी (वीकनेस), मौका या अवसर (अपरट्यूनिटी) और खतरों (थ्रेट्स)) विश्लेषण करना चाहिए, जो व्यापार की सफलता के लिए उपलब्ध संसाधनों और अन्य आवश्यक संसाधनों को जानने में मदद करते हैं।

२. दूध के लिए जानवरों की संख्या का निर्धारण और उस बाजार का निर्धारण जिसमें की आप अपना दूध बेचना चाहते हैं।

३. व्यापार को शुरु करने के लिए आवश्यक मानवीय शक्ति को सुनिश्चित करना, पशुओं को खरीदने के लिए आवश्यक धन, रहने के लिए स्थान बनाना, डेरी के बिलों का भुगतान और अन्य अपेक्षित व्ययों को सुनिश्चित करना।

४. दूध उत्पादन के बारे में जानने के लिए विशेषज्ञों से आवश्यक सुझाव लेना और चारा खिलाना, गायों और भैंसों की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। व्यापार योजना को विकसित करने के लिए आप अपने माता—पिता और बड़े बुजुर्गों से भी राय ले सकते हो और प्रबंध प्रणाली की रचना कर सकते हो।
५. अन्य दुग्ध उत्पादों पर करीबी निगरानी यह देखने के लिए रखनी चाहिए कि, इन फार्मों पर कौनसी रणनीति सही से काम कर रही है और कौनसी नहीं।

६. अन्य किसानों, पशु चिकित्सकों, पोषण विशेषज्ञों, विस्तार शिक्षकों, बैंकरों, और अन्य आवश्यक लोगों के साथ दूध उत्पादन शुरु करने के लिए और डेरी के प्रबंधन पर अलग—अलग सुझाव जानने के लिए संबंधों का निर्माण करना चाहिए।

७. फसल और चारे के कार्यक्रम सहित पोषकों को विकसित करना आपके व्यवसाय के लिए अच्छा है, चाहे फिर कुल मिश्रित राशन या चराने की प्रणाली या दोनों का मिश्रण का प्रयोग हो।

८. स्तनपान कराने वाली और सूखी गायों और गर्भवती गाय व भैंसों के लिए पोषण वाले चारे की योजना को विकसित करना।

९. पशु उत्पादों से प्राप्त कचरे के प्रबंधन करने की योजना बनाना अच्छा है कि कैसे इसका प्रयोग एक उर्वरकों के रुप में किया जाए, जो आपके लिए आर्थिक संसाधन भी हो सकते हैं।

१०. यह व्यवसाय जैविक प्रणाली पर आधारित है और पशुओं के स्वास्थ्य, उनकी दूध उत्पादन की क्षमता, गाय और भैंस के मादा बच्चों के स्वास्थ्य, पुनरुत्पादन प्रणाली, और वित्तीय पहलुओं पर आधारित है। इसलिए, सकारात्मक भविष्य के लिए व्यापक फार्म योजना निर्माण करना चाहिए।

११. फार्म के आकार को निश्चित करना, जो आपकी इच्छा, बाजार की आवश्यकता, आवश्यक संसाधनों और बहुत सी चीजों पर आधारित है।

१२. दूध उत्पादन में सफल व्यापारी बनने के लिए व्यापार योजना का निर्माण करते समय विश्वसनीय सलाहकारों से प्रबंधन के प्रत्येक पहलु पर निश्चित सुझाव प्राप्त करने चाहिए। व्यापार की आगे की प्रगति के लिए सलाहकारों को सक्रिय भागीदारों के रुप में फार्म की सफलता में शामिल करना चाहिए और आपके पास फार्म की प्रबंधन टीम और लाभ टीम होनी चाहिए।

१३. पशुओं के साथ कुछ भी गलत होने— जैसे— पशु की मृत्यु, पुरानी पशुपालन प्रणाली, कीड़े से संक्रमित होना, बीमार पशु की स्वंय चिकित्सा करना, निम्नस्तरीय प्रजनन विकास आदि से देखभाल के लिए रणनीति को अवश्य विकसित करना चाहिए।

१४. राष्ट्र के कल्याण के लिए स्वस्थ दूध के

माध्यम से स्वस्थ पशुधन विकास करना। यह कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थायित्व पैदा करता है।

१५. आपकी किराया, आपरेटिंग (चराने की लागत, दूध उत्पादन, चराई बिल, पशु चिकित्सा बिल, आदि), विभिन्न चर (ईंधन, उर्वरक, चारा, गाय के बछड़ों और बैलों का विक्रय मूल्य, मशीनों की देखरेख आदि) और ह्रास लागत के बारे में सुनिश्चित योजना होनी चाहिए।

१६. आपको सभी चीजों की सकारात्मक रुप से अपनी पूँजी के अनुसार पशुओं की चिकित्सा और प्रबंधन की मासिक लागत को निर्धारित करना चाहिए।

१७. यह सुनिश्चित करना कि, दूध उत्पादन को शुरु करने के लिए स्थानीय सरकार ने कोई लाइसेंस शुल्क लगाया है या नहीं।

१८. यदि आप केवल मादा और स्वस्थ बच्चों को चाहते हैं तो आपको पशुओं की नस्ल में सुधार करने और व्यवसाय को नियमित रुप से चलाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली बहुत ही सुरक्षित है और इससे मवेशी के जीवन को खतरा कम रहता हैय इसके लिए आपको केवल समय पर प्रजनन के लिए एआई तकनीकी को लेने की आवश्यकता है। कृत्रिम गर्भाधान की प्रणाली के द्वारा पैदा की गई गाय अधिक मात्रा में उच्च प्रोटीन और वसा युक्त दूध देने में सक्षम होती है। अमेरिका में, दूध देने की शानदार क्षमता के कारण प्रत्येक दस में से नौ गाय होस्टलीन होती है।

१९. अन्य आम नस्लें, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस, शोर्ट्थोन, गुरेनसे आदि है।

२०. नए दूध उत्पादक के लिए सबसे पहली रणनीति पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इसे लोचदार निवेश के माध्यम से ऋण का प्रबंध करने के दौरान प्रयोग किया जाता है।

२१. इस व्यवसाय में अधिक लाभ प्राप्त करने और इसे अधिक सफल बनाने के लिए खुद की भूमि होना बहुत अच्छा होता है।

२२. आपको समानता निर्माण के तरीके के बारे में अवश्य जानना चाहिए, जो व्ययों को कम रखता है। ३०० ने किसानों पर १९९६—१९९९ में किए गए सर्वे के अनुसार, यह पाया गया कि उनमें से ९०% के पास व्यापार में प्रवेश करने के दौरान ७५ से भी कम गाय थी।

२३. उच्च दूध उत्पादन के लिए आपको अपनी गायों को अधिक प्रोटीन और कार्बोहाईड्रेड (लगभग २९ किलो चारा प्रति दिन दिया जाना चाहिए, जिसमें तिपतिया, घास, अल्फला घास, घास सिलेज, जौ, जई, मक्का, सोयाबीन, मक्का सिलेज, खनिज और विटामिन की खुराक सहित बिनौला शामिल देने चाहिए।

२४. आपको पर्याप्त और स्वच्छ पानी प्रणाली की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक गाय प्रतिदिन ८०—१८० लीटर तक पानी पीती है। उन्हें नहाने और उनके रहने के स्थान को साफ रखने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है।

२५. आपको गाय या भैंस के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिएय जैसे— दूध देना शुरु करने के लिए उसे सबसे पहले बच्चे को जन्म देना होता है, वह लगभग १५ महीने की आयु में उत्पादक बन जाती है और ९ महीने में अपने पहले बछड़े (जिसका वजन लगभग ४० किलो होता है) को जन्म देती हैय अर्थात् आप एक छोटी गाय से लगभग दो या तीन साल में दूध का उत्पादन करना शुरु कर देते हो। एक गाय लगभग १० महीनों तक लगातार दूध देती है और अगले बच्चे को जन्म देने से दो महीने पहले दूध देना बन्द कर देती है।

२६. बहुत सी गाय १० से अधिक गर्भाधारण कर सकती है हालांकि, एक गाय का गर्भाधारण करने की औसत आयु ४—५ होती है।

२७. आप प्रतिदिन ३० लीटर औसतन दूध प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिदिन दो बार दूध निकाल सकते हैं। आपको अपनी गाय का दूध नियमित रुप से एक ही समय पर (सुबह ५ बजे और शाम ५ बजे) निकालना चाहिए।

२८. आपको दूध निकालने के तरीके के बारे में अवश्य ज्ञान होना चाहिए अर्थात् जैविक दूध (एंटीबायोटिक मुक्त अर्थात् गाय को एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए और केवल जैविक चारा ही देना चाहिए) और परंपरागत दूध उत्पादन (जैविक साधनों के स्थान पर दूध उत्पादन)।

२९. अधिक दूध उत्पादन के लिए गाय के पहले गर्भाधारण प्रक्रिया को सुधारने के लिए, दूध न देने के समय

और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य प्रबंधन के दौरान आपको गाय के उचित पोषण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बछड़े के जन्म के तुरंत बाद उचित तरीके से दूध पिलाना चाहिए, उसका अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेड, खनिज और एंटीऑक्साइड को रखने वाले खाने को शामिल करना चाहिए।

**फार्म हाउस तैयार करना —**

फार्म हाउस तैयार करने के लिए लगभग २ एकड़ कृषि भूमि होना चाहिए जिसमे पशुओ के लिए टीन शेड बनाकर उनके बंधने की व्यवस्था हो, ऐसे ही रात और दिन में बाधने के लिए अलग—अलग टीन शेड बनाने होते है गाय व भैस के लिए यह व्यवस्था अलग करना होती है, पशुओ को पानी के लिए नलकूप की व्यवस्था तथा सीमेंट की ठेल की व्यवस्था करनी होती है, चारा या भूसा खिलाने के लिए या तो सीमेंटेड शेड या अलग अलग टाफ्फ या तगारी रखना होती है, दाना और भूसे के लिए अलग अलग पात्र रखना होते है,साथ ही फार्म हाउस में कचरा प्रबंध इकाई, बायोगैस, और जैविक खाद इकाई स्थापित करना होती है। पशुओ के हरे चारे के लिए चरी बरसीम लचका बोने के लिए कम से कम एक बीघा का खेत अल्टरनेट बुवाई के लिए होना चाहिए, पशुओ के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण व प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था होना चहिये, पशुओ को टानिक व् उनके गर्भाधान हेतु कृतिम व जैविक गर्भाधान की व्यवस्था होनी चाहिए। आवश्यक कर्मचरियों की व्यवथा भी होना जरुरी है। कृषि यन्त्र समेकित किट प्रबंधन होना चाहिए।

**दुग्ध एकत्रण इकाई —** पशुओ, के दुग्ध निकलने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी या मशीन भी होना चाहिए,कच्चे दुग्ध के भण्डारण, शीतलन हेतु कोल्ड यूनिट होना चाहिए, फेट निकलने की मशीन, डिग्री मशीन, माप लीटर, टंकी, इलेक्ट्रोनिक वजन मशीन, मावा बनाने के भट्टी, दुग्ध पेकिंग पैकेड, पाकिंग मशीन परिवहन व्यवस्था होना आवश्यक है। लागत— लघु दुग्ध इकाई स्थापित करने के लिए लगभग १० लाख की लागत व बड़ी दुग्ध उत्पादन इकाई के लिए ३० लाख की लागत लगती है,फॉर्म हॉउस की भूमि की लागत प्रथक से रहेगी।

**उत्पादन और लाभ—** लघु इकाई में ६०—१०० लीटर दुग्ध प्रति दिवस उत्पादन कर सकते है और यदि आय की बात की जाय तो लघु इकाई में लगभग १.५० लाख रुपये मासिक आय होती है, यदि सभी सुविधा को काट दे शुध्ध लाभ ४० हजार तक प्रतिमाह हो सकता है और यही उद्योग हम बड़े पैमाने पर करे तो जो लगभग २० पशुओ की इकाई का करे तो प्रतिमाह लगभग ८० हजार से एक लाख तक कमाया जा सकता है,यदि पशुओ की संख्या ३० हो तो शुध्द मासिक लाभ लगभग २.५० लाख तक कमाया जा सकता है।

**उपसंहार —**

पशुपालन डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावना है यदि व्यक्ति ग्रामीण परिवेश में रहा है, और उसके पास कृषि भूमि है तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे आसान उद्योग डेयरी उद्योग ही है। वेसे भी दुग्ध का उत्पादन रोजाना खपत की तुलना में कम उत्पादन हो रहा है। वर्तमान के परिवेश में दुध के उत्पाद बड़े है अमूल जहा पुरे देश में अपना उद्योग कर सालाना करोडो रूपये कमा रही है, वही मध्यप्रदेश की साँची शासकीय डेयरी भी सालाना अच्छी कमाई कर लेती ये दोनों डेयरी देश का रेल माडल डेयरी है। यदि इनके अनुसार पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन किया जाय तो स्वरोजगार स्थापित किया जा सकता है और उत्तम कोटि का जीवन यापन किया जा सकता है।

**सन्दर्भ —**

➢ डॉ व्हाय एन शुक्ल, डॉ के. के. श्रीवास्तव,डॉ मेरी बी जान, डॉ. आर.सी. रामटेके,डॉ. उपासना साहू,डॉ. अंजू शर्मा,डॉ. नीतू गोरडिया, डॉ. गोतम राय डॉ. सुनीता राय,डॉ. निशा जैन,डॉ. महावीर सर्सिहा,

Online platform:

➢ https://ziploan-in/hi/article/dairy&entrepreneurship&development&plan&deds

➢ http://www-hpagrisnet-gov-in/hpagris/AnimalHusbandry/downloads/Dairy_Farming_Book-pdf

❑❑❑

11

# सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग, युवा वर्ग के लिए संभावनाएं एवं शासन के प्रयास

**डॉ. सीमा तिवारी**
प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय स्नातकोत्तर, कन्या महाविद्यालय इंदौर

*********

**Abstract :-**

नवीन शिक्षा नीति **NEP** २०२० का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुखी बनाना है ताकि युवा वर्ग को शिक्षा के उपरांत सही दिशा प्राप्त हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र, ६ करोड़ से अधिक उद्योगों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, कौशल विकास योजनाएं और प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धात्मकता के सहयोग से इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मंत्रालय के अधीन महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एम जी आई आर आई), राष्ट्रीय लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), खादी और ग्राम उद्योग (केवीआईसी) मंत्रालय के पास एमएसएमई को समर्थन देने के लिए देशभर में फैली क्षेत्रीय संरचनाओ का एक सशक्त नेटवर्क है जिसमें एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालय (**MSME- DFO**), एमएसएमई प्रशिक्षण केंद्र स्टेशन और प्रौद्योगिकी केंद्र, टूल्स रूम और तकनीकी संस्थान और **ज्ञटप्छ** के क्षेत्रीय कार्यालय, कॉयर बोर्ड और **NSIC** शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग भारतीय विरासत और परंपराओं को बचाए रखते हुए औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास की मूलभूत अवधारणा के क्रियान्वयन का प्रयास है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का योगदान लगभग ८ प्रतिषत है। रोजगार अवसर लगभग १२० मिलियन लोगों को इसके द्वारा प्रति वर्ष उपलब्ध होता है। भारत के द्वारा किए जाने वाले कुल निर्यात का लगभग ४५ प्रतिषत से अधिक का योगदान इन उद्योगों के माध्यम से होता है। यह कृषि के पश्चात दूसरा सर्वाधिक उच्च स्तर पर रोजगार का सृजन करने वाला क्षेत्र है जो युवाओं को नवीन उत्पादों को विकसित करने, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विकास को गति प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार राष्ट्र में नवोन्मेष को बढ़ावा मिलता है।

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में कार्य करने वालों की संख्या और वार्षिक उत्पादन की एक निश्चित राशि तय की गई है। **वर्ष २०२० में इसे निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है।**

| क्र | उद्यम का प्रकार | निवेश | कारोबार |
|---|---|---|---|
| १ | सूक्ष्म उद्योग | १ करोड़ रूपए | ५ करोड़ रूपए तक |
| २ | लघु उद्योग | १० करोड़ रूपए | ५० करोड़ रूपए तक |
| ३ | मध्यम उद्योग | ५० करोड़ रूपए | २५० करोड़ रूपए तक |

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एमएसएमई क्षेत्र की लगभग ६.३ करोड़ इकाइयों का विशाल नेटवर्क है जो भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान करता है। कुल एमएसएमई की लगभग ५० प्रतिषत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। भारतीय एमएसएमई विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है और उनके उत्पाद विदेशों में स्वीकार किए जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रयासों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है।

**भारत में एमएसएमई के समक्ष विद्यमान चुनौतियां :**

**१. नवाचार की कमी —**

भारतीय एमएसएमई द्वारा उत्पादित अधिकांश उत्पाद पुरानी प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। परिणाम स्वरूप लघु और मध्यम फर्म्स को अपने स्वयं के संस्थानों पर निर्भर रहने हेतु विवष होना पड़ता है। साथ ही बड़ी फर्म्स के साथ उत्पादकता की प्रतियोगिता में

निराश होना पड़ता है।

**२. संवाद और जागरूकता की कमी—**

जागरूकता की कमी के कारण ये संस्थान सरकार की आपातकालीन ''लाइन ऑफ क्रेडिट'', "स्ट्रेस्ड एसेट रिलीफ", इक्विटी भागीदारी और "फंड आफ फंड ऑपरेशन" का लाभ नहीं उठा पाते।

**३. औपचारिकता का अभाव—**

प्रौद्योगिकी को अपनाने में विलंब और आपूर्तिकर्ता और ग्राहक के बीच तालमेल का अभाव, देरी से भुगतान की सर्वकालिक समस्या इत्यादि मुख्य चुनौतियां हैं। विकास के लिए नई तकनीक को अपनाया जाना आवश्यक है। साथ ही ई—भुगतान को स्वीकार किया जाना चाहिए। इन हाउस इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वैश्विक बाजार के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए व्यवसाय संचालन की पुरानी विधियों के साथ—साथ, स्तरहीन प्रौद्योगिकी अपनाना, छोटे और मझौले आकार, डिजाइनिंग में सृजनात्मकता, पैकेजिंग और विपणन नीति में विशेषज्ञता का अभाव, इन्हें प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देता है।

**४. वित्तीय समस्याएं —**

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आसान ऋण की उपलब्धता इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, किंतु छोटे पैमाने पर इनके संचालन के कारण एमएसएमई जोखिम पूंजी को बढ़ाने में असमर्थ होते हैं और प्राप्त सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी असमर्थ होते हैं। हालांकि नवीन संरचनात्मक सुधारों के क्रियान्वयन के कारण कुछ सुधार संभव हुए हैं। बड़े उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एमएसएमई अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायक इकाई होती है, किंतु अधिकतर यह छोटी सहायक इकाईयां बड़ी इकाइयों से, देरी से भुगतान के कारण समस्या का सामना करती है। परिणाम स्वरुप उनका नगदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी की उपलब्धता प्रभावित होती है। ऐसे में नए उत्पादन के लिए ऑर्डर्स प्राप्त करने और सप्लाई करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।

दिसंबर २०१९ में किए गए एक सर्वे में विनिर्माण गतिविधियों में सभी इकाइयों में से ४४ प्रतिषत एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

यद्यपि देरी से भुगतान में जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है, किंतु लघु और मझौले उद्योग व्यापार के खोने के डर से इनकी शिकायत करने से डरते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की बाधाओ को दूर करने के लिए और कारणों की खोज के लिए आरबीआई ने २०१९ में श्री यू.के. सिंह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। जिन्होंने अध्ययन एवं समीक्षा के पश्चात आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए कई सिफारिश से प्रस्तुत की।

यह सफारिषें विधायी परिवर्तनों, बुनियादी ढांचे का विकास, क्षमता निर्माण, तकनीकी विकास, आपूर्तिकर्ता और ग्राहक के बीच मध्यस्थता को बेहतर बनाने, वित्तीय सहायता में सुधार और क्रेडिट वितरण से संबंधित है।

**५. आरबीआई द्वारा किए गए उपाय—**

रिजर्व बैंक द्वारा ऋण की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है।

१. विलंबित भुगतानों की समस्या का समाधान करने के लिए रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम, **TRDS** की शुरुआत की। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है जहां छोटे उद्योगों को, विलंबित भुगतान के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। अतः आने वाले वर्षों में इस समस्या का समाधान पाया जा सकेगा।

२. सरकार ने २०१८ में ५०० करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली सभी कंपनियों के लिए **TRDS** के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। फरवरी २०२० तक कुल ८२११ **MSME** विक्रेताओं ने पंजीकरण किया है जबकि इसके पूर्व मात्र १५५० कंपनियां **TRDS** के द्वारा पंजीकृत थी।

३. केंद्रीय बजट २०—२१ में शासन ने **MSME** के विलंबित भुगतानों की समस्या को दूर करने के लिए ऐप **(APP)** आधारित चालान, वित्त पोषण, उत्पादों की घोषणा की है जो **TRDS** के लिए मददगार साबित होगी।

**४. RMA against Bank Grarantee**

यह एक रॉ मटेरियल एसिस्टेंस स्कीम है जो

लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को कच्चा माल खरीदने के लिए वित्तीय सहयोग के लिए लागू की गई है।

५. **Credit facilitation through Bank**

**MSME** इकाइयों की क्रेडिट जरूरतों के लिए **NSIC** के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीकृत और प्राइवेट बैंकों के साथ एक **MOU** किया गया है, ताकि छोटे उद्योगपति अपने नजदीकी बैंक अधिकारियों से मिलकर बिना किसी शुल्क के सहयोग प्रदान कर सके।

६. **SINGLE POINT REGISTRATION SCHEME**

शासकीय खरीददारी के टेंडर्स के मामलों में, **EMD, Inform ediary Services,** वित्त, तकनीकी, व्यापार में राष्ट्रीय स्तर की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्य करती है।

७. **National Scheduled Cast and Scheduled Tribe Hub**

**SC, ST** के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए **(NSSH)** के द्वारा व्यावसायिक सहयोग किया जा रहा है।

इस प्रकार इस क्षेत्र में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं आवश्यकता इस बात की है कि सही नीतियों का निर्धारण किया जाए और **MSME** की समस्याओं को प्रभावी ढंग से दूर करने हेतु सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए इंडो जर्मन टूल रूम **(IGTR)**, **AICTE** और **NCVT** के द्वारा विद्यार्थियों के लिए शार्ट और लॉंग टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

**Short Term Training programme**

| S. No. | Course | Qualification | S. No. | Course | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certificate Course in CAD/CAM (Auto CAD, Soild works Creo) | ITI/Diploma/Degree in Engineeering (Prod./Mech/Indust.) | 28 | Advance Industrial Elect. Maintenance | ITI/Diploma/Degree in Electrical/Electronics Engineeering |
| | | | 29 | Auto CAD Electrical | |
| 2 | Advance Course in CAD/CAM (Unigraphics, Creo, CATIA) | | 30 | E-Plan | |
| | | | 31 | PLC Programming | |
| 3 | Master CAM | | 32 | SCADA | ITI/Diploma/Degree in Electrical/Electronics Engineeering |
| 4 | Solid Works | | 33 | VLSI | |
| 5 | Pro E/Creo | | 34 | Microcontroller Programming | |
| 6 | Unigraphics | | 35 | Embedded Systerm | |
| 7 | DELCAM | | 36 | MATLAB | |
| 8 | Catia | | 37 | REVIT ARCHITECTURE | Diploma/Degree in Elect/Instru/Compu/Mech B.Sc. Elec/Computer |
| 9 | CNC Programming Lathe | | 38 | 3D MAX | |
| 10 | CNC Programming Milling | | 39 | 3D Animation | |
| 11 | CNC Technology (Turning & Milling) | | 40 | Staad Pro | |
| 12 | CNC Simulator | | 41 | Auto CAD Civil | |
| 13 | Auto CAD | | 42 | C | |
| 14 | Computer Hardware & Networking | | 43 | C++ | Diploma/Degree in any Branch B.Sc./B.Com |
| 15 | Heat Treatment of Steels (Min Group of 8) | | 44 | JAVA PROGRAMMING | |
| 16 | Basic Course on Pneumatics (Min Group of 8) | | 45 | Internet of Things (IOT) | |
| 17 | Basic Course on Hydraulics (Min Group of 8) | | 46 | Artificial Intelligence | |
| 18 | Basic Course on Electro Pneumatics (Min Group of 8) | | 47 | Web Development | |
| 19 | Basic Cousre on Electro Hydraulics (Min Group of 8) | | 48 | Python Programming | |
| 20 | Inspection & Metrology (Min Group of 8) | | 49 | Machine Learning | |
| 25 | Robotics (Min. Group of 8) | | 49 | Cyber Security | |
| 26 | Basic Industrial Elect. Maintenance | | 50 | Power of BI Tool | |
| 27 | Big Data | | 51 | Tally | |

**उपलब्धियां :—**

भारत शासन के प्रयासों से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय विगत २४ वर्षों से कार्य कर रहा है।

वर्ष २०२२ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा ''उद्यमी भारत" कार्यक्रम में **MSME** क्षेत्र के लिए मुख्य पहल यथा — **MSME** के प्रदर्शन को बढ़ावा देना और तेज करना (रैम्प) योजनाएं, **MSME** निर्यातकों की क्षमता निर्माण (**CBFTE**) योजना और ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" (पीएमईजीपी) की शुरूआत की गई है जिसके अंतर्गत उद्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से एक करोड़ से अधिक **MSME** संस्थानों का पंजीकरण किया गया है।

पीएमईजीपी के तहत नई परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र के लिए २५ लाख से बढ़ाकर ५० लाख रुपए कर दी गई है और सेवा क्षेत्र के लिए १० लाख रुपए से बढ़ाकर २० लाख कर दी गई है।

**MSME** सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना को प्रारंभ किया गया है जिसमें २३००० से अधिक **MSME** पंजीकृत हो चुकी हैं।

४१वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में २०२२ में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की भागीदारी ७३ प्रतिशत है जो अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है।

दिनांक जनवरी, २०२२ से दिसंबर, २०२२ तक उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के तहत ९१,९३८ व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। २,६८,०७० लोगों को मंत्रालय के तहत विभिन्न टूल रूम और तकनीकी संस्थानों, टीसीएसपी के तहत स्थापित किए गए नये प्रोद्योगिकी केन्द्रों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, कॉयर बोर्ड, **MSME-NI** आदि के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इस प्रकार शासन द्वारा युवाओं में कौषल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में उन्नति के लिए लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय अत्यधिक प्रयासरत है। वर्ष २०२५ तक **MSME** मंत्रालय द्वारा अपने जीडीपी को ५० प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मैक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्कील

इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियान इस लक्ष्य को सहयोगी साबित हो रहे हैं। वास्तव में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को भारत सरकार ने "त्वरित, औद्योगिक विकास और ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादक रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न करने" के दोहरे उद्देश्य को साकार करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में माना है इसीलिए वे भारत के समग्र आर्थिक विकास के लिए सर्वोपरि है।

**संदर्भ :**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट

**MSME (hgtrs) Yearly Report 2022-23**

https://www.mposme.gov.in
https://www.timesofmalwa.in
https://mpmsme.gov.in
https://www.igtr.indore.gov.in
https://pib.gov.in
https://www. इंडिया सरकार भारत

❑❑❑

**12**

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति–२०२०, भारतीय पारम्परिक विरासतो एवं उदयमान आत्मनिर्भर भारत के परिचय की कुंजी साबित होगी

**डॉ. आरती चौहान**
सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र,
महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,किला भवन इंदौर (म.प्र.)

***********

**शोध सारांश –**

''भारत विश्वगुरु था, और रहेगा'', भारतीय प्राचीन पद्धतियों, परमपराओं, धरोहरों, कौशल एवं भारतीय जीवन दर्शन, को विश्व पटल पर रखने में भाषाई दक्षता की कमी को आवरोधक नहीं बनने दिया जायेगा द्य भारतवर्ष में प्रचलित प्राचीन शिक्षा पद्धति में परम्परागत शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, जिसमे गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षार्थियों को बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरुकुल में भर्ती किया जाता था, यह व्यवस्था हमारे धर्म ग्रंथो रामायण, महाभारत, में वर्णित आश्रमों, नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालयो तथा मध्यप्रदेश के उज्जैन में भगवान् कृष्ण की शिक्षा दीक्षा स्थली संदीपनी आश्रम उज्जैन के महत्वपूर्ण आश्रम थे, इन संस्थाओ में विदेशी विद्यार्थी भी अध्ययन करने आते थे, इन सभी आश्रम संस्थाओ में चरक, आर्यभट, सुश्रुत, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, थिरुवल्लुवर, आदि महान विद्वानों को जन्म दिया है, गणितज्ञान तथा वर्तमान में उपयोगी शिक्षा का स्वरोजगार महत्व, लघु उद्योग, प्राचीन इतिहासिक धरोहरे, क्षेत्रीय भारतीय भाषाएँ, विविधताए, तकनिकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा सुधार, भारतीय जीवन दर्शन, ज्योतिष शिक्षा योग, ध्यान हेतु राष्ट्रीय

शिक्षा नीति—२०२०, आजाद भारत में भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था हेतु मंत्रालय स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनाई गई, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९६८ में बनी, इसमे संशोधन कर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ में तथा देश की आधुनिक आवश्यकता एवं भारतीय प्राकृतिक एवं मानव संसाधनो के धारणीय उपयोग एवं भारतीय परंपरागत विरासतों, वेद, आयुर्वेद, भारतीय खगोल विज्ञान आदि विषयों से नई शिक्षा नीति परिपूर्ण रहेगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० के बारे में चर्चा जनवरी २०१५ में कैबिनेट सचिव टी.एस.आर सुब्रमणियम के नेतृत्व में समिति द्वारा शुरू की गई थी, २०१७ में समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। २०१७ की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा, २०१९ में पूर्व इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) प्रमुख वैज्ञानिक कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में नई टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जनता और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद मसौदे के साथ नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। नई शिक्षा नीति २९ जुलाई, २०२० को अस्तित्व में आई, यह शिक्षा नीति निश्चित रूप से भारतीय पारम्परिक विरासतो एवं उदयमान आत्मनिर्भर भारत के परिचय की कुंजी साबित होगी।

**मुख्य बिंदु** : आत्मनिर्भर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पारम्परिक विरासते एवं कौशल विकास

**प्रस्तावना —**

भारत क्षेत्रफल व जनसँख्या की द्रष्टि से विश्व का विशालतम देश है, भारत का अखंड स्वरूप क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, हमारी विशाल संस्कृति,वैदिक सभ्यता, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय महान वेद, आयुर्वेद, काल गणना खगोल ज्ञान, ज्योतिष एवं गणित ज्ञान, प्राचीन शिक्षा पद्धति, गुरुकुल की गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा और सीखने की पद्धति, आश्रम व्यवस्था, पारम्परिक कृषि व्यवसाय, प्राकृतिक संसाधन, वैश्विक पटल पर अनुकरणीय उदाहरण रहे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२०, भारत में निवासरत नागरिको के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इस नीति के प्रावधानों और लक्ष्यों के अनुसार देश में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा, भारत विकाशील देश से विकसित देश होने की दिशा में तेजी से बढेगा, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० को भारत की पिछली शिक्षा नीति १९८६ व संशोधन १९९२ के अपूर्ण लक्ष्यों एवं कमियों को आधुनिक आवश्यकताओ की मांग की पूर्ति को धारणीय विकास कार्यक्रमों के साथ पूर्ण करने के लिए घोषित की गई है। इस नीति के प्रभाव से भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति,भारत की विशाल एतिहासिक विरासत, धरोहरे, संस्कृति, भारतीय जीवन दर्शन,महान वेद एवं वैदिक पद्धतियों, भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य कलाएं के साथ— साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली वैश्विक पटल पर प्रकाशित होंगें।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० का प्रभाव —**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० को भारत सरकार के केंदीय मंत्रिमंडल ने २९ जुलाई २०२० को पारित किया है, जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ को प्रतिस्थापित करते हुए इसका स्थान लेते हुए इसके अपूर्ण लक्ष्यों को वर्तमान मानव संसाधन एवं समय की मांग के अनुरूप धारणीय विकास के साथ भारतीय नागरिको, विद्यार्थियो की आधुनिक आवश्यकताओ की पूर्ति के साथ—साथ सम्पूर्ण विकास करेगी द्य इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० को केंद्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पारित करने के साथ ही इस मंत्रालय का नाम भी परिवर्तित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय किया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्पूर्ण भारत के क्षेत्राधिकार भारत गणराज्य की सीमा रेखाओ के साथ—साथ भारतीय संविधान की सीमा तक यह वैश्विक पर भी लागू होगी।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० का उद्देश्य —**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० का लक्ष्य एवं उद्देश्य महान है, अच्छे नागरिको का विकास करने के साथ भारत में शिक्षा सुधार करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो जिसमे करुणा, सहानुभूति, साहस और लचीलापन वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य आधार हो जो की भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे सके, वर्तमान में २५

प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढाकर ५० % करना एवं २०३० तक इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० को प्रभावी एवं पूर्णरूप १०० % सकल नामंकन अनुपात का लक्ष्य पूर्ण कर लागू करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से जीडीपी का ६% हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया हैद्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२० की शैक्षणिक संरचना को इस प्रकार ५ . ३ + ३ + ४ से आकार दिया गया हैद्य नीति की इस संरचना के हिसाब से विद्यार्थियो की उम्र (३—८, में पहली से दूसरी कक्षा), (८—११ में तीसरी से पांचवी कक्षा), (११—१४, में छठी से आठवी कक्षा) तथा (१४—१८, में नवी से बारहवी कक्षा) इस प्रकार संरचना को आयु वर्ग में विभाजित किया गया है। NEP २०२० के तहत HHRO द्वारा 'बुनीयादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है इसके द्वारा वर्ष २०२५ तक कक्षा—३ स्तर तक के बच्चो के लिए आधारभतू कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

**भाषाएँ विविधता का संरक्षण —**

NEP—२०२० कक्षा—५ तक की शिक्षा में मातृभाषा एवं स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मात्रभाषा को कक्षा—८ और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कुल और उच्च शिक्षा में छात्रो के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

**शारीरिक शिक्षा —**

विद्यालयों में सभी स्तर पर छात्रों को नियिमत रुप से खेल—कूद, योग, न्रत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक शिक्षा व्यायाम योग जैसी सभी गतिविधियों में भाग ले सके।

**पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संम्बन्धी सुधार —**

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में प्रस्तावित सुधारो के अनुसार कला और विज्ञान, व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयो एवं पाठ्याक्रम व पाठ्योत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा—६ से ही शैक्षणिक विषयो एवं पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा द्य इसमे इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training& NCERT) द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रुपरेखा '(National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी। छात्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा—१० और कक्षा—१२ की परीक्षाओ में बदलाव किया जायेगा द्य इसमे भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे द्य छात्रो की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में 'परख (PARAKH)' नामक एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी द्य छात्र के प्रगति एवं मूल्यांकन तथा छात्रो के अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए ''कृतिम बुद्धिमता केंद्र (Artificial Intelligence& AI)'' आधारित सॉफ्टवेर का प्रयोग किया जायेगा।

**शिक्षण व्यवस्था से सम्बंधित सुधार —**

शिक्षको की नियुक्ति प्रभावी व पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाएगी तथा समय—समय पर किये गए कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगीद्य राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा वर्ष २०२२ तक शिक्षको के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (National Professional Standards for Teachers& NPST) का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रुपरेखा (National Curriculum Framework for Teacher Education&NCFTE) का विकास किया जायेगा। वर्ष २०३० तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता ४—वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जायेगा।

**उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान —**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के तहत उच्च शिक्षण संसथान में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को २६.३% वर्ष २०१८ से बढ़ाकर ५०% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संसथानो में ३.५ करोड़ नई सीटो को जोड़ा जाएगा। NEP—२०२० के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टिपल एंट्री एंड एग्जिट (Multiple Entry and Exit) व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत ३ या ४ वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर विद्यार्थी पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे, और उन्हें उसी के अनुरूप प्रमाणपत्र या डिग्री प्रदान की जाएगी, क्रमश: एक वर्ष के बाद प्रमाण—पत्र, २ वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, तीन वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री, ४—वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्रीद्य विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंको अथवा क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग—अलग संसथानो में छात्रो के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

**भारतीय उच्च शिक्षा आयोग —**

(Higher Education Commission of India&HECI) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)— २०२० से देशभर के उच्चशिक्षा संस्थानों में एकल नियामक, भारतीय उच्चशिक्षा परिषद (Higher Education Commission of India&HECI) की परिकल्पना की गई है, जो देशभर के कई उद्धेश्यो को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे, भारतीय उच्चशिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पुरे उच्चशिक्षा के क्षेत्र के लिए एकल स्वतन्त्र निकाय के रूप में कार्य करेगाद्य भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India&HECI) के कार्यो को प्रभावी रूप से निष्पंदन करने के लिए निम्न चार निकाय तैनात किये गए है।

१. राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा नियमाकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council)

२. सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council)

३. राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council)

४. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grant Council)

वर्तमान में उच्चतर शिक्षा के निकायों का विनिमय विश्वविध्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जाता हैद्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अंतर्गत देश में IIT एवं IIMS के समकक्ष वैश्विक मनको के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसन्धान विश्वविध्यालय की स्थापना की जाएगी।

**दिव्यांग विद्यार्थियो के लिए प्रावधान —**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियो के लिए सम्पूर्ण आवश्यक सुविधाओ के प्रावधान किये गए है, विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, के साथ सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

**डिजिटल शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान —**

राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रोधौगिकी मंच (National Educational Technology Forum) का गठन किया जायेगा। जो शिक्षण शैक्षणिक मूल्यांकन योजना, डिजिटल संसाधनों को विकसित किया जायेगा, सुचना प्रोधौगिकी इकाईयों का विकास किया जायेगा।

**पारंपरिक ज्ञान सम्बन्धी प्रावधान —**

भारतीय प्राचीन ज्ञान प्रणालियाँ, जैसे जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान, के साथ विविध भारतीय ज्ञान परम्पराओ के पाठ्यक्रमो को वैज्ञानिक तरीको से विकसित एवं लागू किया जायेगा।

**वित्तीय सहायता —** एससी/ एसटी के विद्यार्थियो को छात्रवृति एवं शोधवृति सहायता एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कमजोर विद्यार्थियो को भी छात्रवृति व शोध हेतु छात्रवृति का प्रावधान किया गया है, मेघावी विद्यार्थियो को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी है, ऐसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओ का सामना करने वाले विद्यार्थियो को विशेष आर्थिक सहायता कर समानता का अवसर प्रदान किया जायेगा, ८ वर्ष तक के बच्चो के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा हेतु राष्ट्रीय

पाठ्यचर्चा का संचालन एनसीईआरटी (NCRTE) द्वारा किया जायेगा।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० की आवश्यकता —**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६, के पारित होने पर जो तत्कालीन लक्ष्य लिए थे, वे वक्त के हिसाब में मानव संसाधन के अनुसार उचित थे, परन्तु आज के बदलते परिवेश में और आज के मानव संसाधन के अनुसार इसको विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थीद्य १९८६ की शिक्षा नीति अनुसार इसके लक्ष्य आसमानताओ को दूर करके विशेष रूप से महिलाओ अनुसूचित जातिध्जनजाति को शिक्षा से जोड़ना और उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना और उन्हें बराबरी के साथ शैक्षणिक अवसर प्रदान करना था, वर्त्तमान शिक्षा नीति २०२० में भी यह प्रावधान है, शिक्षा नीति १९८६ ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ''ओपरेशन ब्लेकबोर्ड'' लांच किया था, साथ ही इस नीति ने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का विस्तार किया, ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढावा देने के लिए ''महात्मा गाँधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय मॉडल'' के निर्माण के लिए नीति का भी आव्हान किया था।

परन्तु वर्त्तमान शिक्षा नीति २०२० में उदयमान भारत की जनसँख्या के अनुपात में विज्ञान एवं तकनीकियो का उपयोग, मानव संसाधन का उपयोग एवं उससे रोजगारध स्वरोजगार, उद्योग, व्यवसाय किया जा सके। हमारे प्राकृतिक संसधानो का धारणीय विकास कार्यक्रम, अनुसार मांग की आपूर्ति की जा सके राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२०, इस नीति में व्यावहारिक शिक्षा के साथ साथ, कौशल विकास तथा रचनात्मक शिक्षा, स्वरोजगारोंमुखी व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ में परम्परागत शिक्षा विज्ञान, कला के सिधान्तो वाले पाठ्यक्रम को महत्व दिया गया था। जिसे पढकर विद्यार्थी यदि शासकीय रोजगारध्स्वरोजगार में नहीं आता था, तो उसके जीवन में उसके द्वारा ली गई शिक्षा का १० प्रतिशत भाग भी उपयोग नहीं हो रहा था, शिक्षा केवल किताबो में लिपटी पड़ी रह जाती थी, उसका व्यवहारिक रचनात्मक, कौशल विकास तथा व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा था, यह भी मुख्य कारण है, शिक्षा नीति में बदलाव और आज के बदलते परिपेक्ष में जनसँख्या वृध्दि के अनुरूप मानव संसाधन का उपयोग आधुनिक समय की मांग का आंकलन कर, आपूर्ति का प्रबंधन किया गया है।

**विश्वविध्यालय एवं कॉलेज के संस्थागत विद्यार्थियो का आकर्षण का केंद्र है राष्ट्रीय शिक्षा नीति — २०२०**

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० की प्रमुख विशेषता—**

मुख्य विषय (Major Subject) — राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का मुख्य (Major) विषय इसका मस्तिष्क एवं दिमाग (Brain) है, जो प्रमुख स्थान रखता है, विद्वान नीति निर्धारको ने इस नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया हैद्य इस विषय में सैधांतिक व प्रयोगात्मक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम दिए जायेगे इसके अध्ययन करने से रचनात्मक एवं साहित्यिक ज्ञान प्राप्त किये जा सकेंगे। इसके पाठ्यक्रम संरचना में मुख्य विषय जिसमे विद्यार्थी को दो पेपर पड़ना होते है, और उसी मेजर विषय में अपना परियोजना कार्य जो अपनी रूचि के अनुसार किसी शीर्षक पर लघु शोध कर, अपना कौशल विकास, रचनात्मक एवं प्रायोगिक कार्य किया जा रहा है।

**गौण विषय (Minor Subject) —**

इस नीति में गौण विषय का भी प्रमुख स्थान है इसे व्यवस्था की आत्मा (Soul) कहा जा सकता है, यह विद्यार्थी की इच्छा शक्ति को बढाएगा, यह मुख्य (major) विषय का अनुपूरक है और इसमे सेधान्तिक ज्ञान के साथ सन्दर्भ धारणाएं से पूर्ण है इसके पाठ्यक्रम में वह सभी विधियाँ सिधांत होंगे, जो मुख्य विषय को प्रयोगात्मक व रचनात्मक आकार देता है, इसके पाठ्यक्रम का निर्माण विषय की मुख्य धारणाए एवं सिधान्तो से किया गया है, जिसका आधुनिकीकरण कर विषय के विकसित भाग को मेजर प्रथम पाठ्यक्रम के रूप में विकसित किया गया हैद्य यह विद्यार्थी का आधारस्तंभ होता है विद्यार्थी इसे पढकर विषय का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे।

इलेक्टिव विषय (Open Elective Subject) —

विषय का भी प्रमुख स्थान है, इसे इस व्यवस्था की भुजाओ वाला मेरुदंड (Backbone) माना है, जिस

पर मुख्य विषय भी टिका हुआ है, दोनों मिलकर व्यवस्था का डबल इंजन है, जो निश्चित रूप से विद्यार्थियो में आत्मविश्वास भरते है, इसे अन्तरसंकाय परिवर्तन कर विद्यार्थी इसका चयन कर सकेंगे, विज्ञान, कला, वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी अपनी रूचि से चयन कर सकेंगे।

**व्यासायिक विषय ( Vocational Subject)—**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अंतर्गत व्यावसायिक विषय का भी प्रावधान किया गया है, इस विषय को पढकर विद्यार्थी अपने अन्दर छुपी प्रतिभा क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे इसके अंतर्गत विद्यार्थी का बौद्धिक कौशल विकास हो सकेगा, वह इससे नोकरी नहीं होने की स्तिथि में अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकेगा, ऐसे विषय का चयन अपनी रूचि अनुसार किया जा सकेगा, इस विषय से भारत के कौशल विकास कार्यक्रम संचालित होंगेद्य इस विषय को बोद्धिक क्षमता के साथ कौशल कला विकास (Brain with skill Art) कहा जा सकता है। इससे देश के मानव संसाधन का धारणीय प्रबंधन (Sustainable Management) हो सकेगा। भारत के लगभग राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० लागू हो गई है, वर्तमान में इस शिक्षा नीति को लेकर संस्थागत विद्यार्थियो का रुझान बड़ा है, साथ ही विद्यार्थियो के द्वारा इसके पाठ्यक्रम का अध्ययन करने पर उन्हें उनके कौशल विकास तथा करियर बनने से सम्बंधित आसार दिखाई दे रहे है इसके कारण यह आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

संस्थागत विद्यार्थियो को यह शिक्षा नीति रुचिकर लग रही है, इसकी मुख्य विशेषता है की इसके पाठ्यक्रम संरचना में मुख्य विषय जिसमे विद्यार्थी को दो पेपर पड़ना होते है, और उसी मेजर विषय में अपना परियोजना कार्य जो अपनी रूचि के अनुसार किसी शीर्षक पर लघु शोध कर, अपना कौशल विकास, रचनात्मक, एवं प्रायोगिक कार्य किया जा रहा है।

विद्यार्थियो को (NEP—२०२०) के अंतर्गत मुख्य विषय के साथ ये सुविधा दी गयी है, कि विद्यार्थी ४ वर्ष की स्नातक डिग्री सफलतम पूर्ण करता है तो वह स्नातक शौध के साथ प्राप्त करेगा, और इसी मुख्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री एक वर्ष में ही पूर्ण हो जाएगी और विद्यार्थी आगे इसमे शौध जारी रख सकेगा, इस प्रकार विद्यार्थी के समय की बचत हो सकेगी, इस प्रकार की व्यवस्था एवं सुविधा परिवर्तित की गई शिक्षा नीति १९८६ में नहीं थी

**विद्यार्थियो के लिए वरदान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०—**

१. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को २९ जुलाई २०२० को लागू किया गया है, यह शिक्षा नीति १९८६ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर संशोधित की गई है, वर्तमान शिक्षा नीति (NEP२०२०) आधुनिकीकरण, मानव संसाधन के अनुपात में प्राकृतिक स्त्रोतों का धारणीय उपयोग, सुचना प्रौधोगिकी का उपयोग, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों, भारतीय दर्शन, प्राचीन शिक्षा पद्धितियों के ज्ञान का विद्यार्थियो, युवाओ, नागरिको को उन्हें व्यावहारिक, रचनात्मक एवं साहित्यिक कार्यो को करने के लिए प्रेरणा, देती रहेगी, उन्हें अच्छे नागरिक बन्ने के लिए अनुकूलित अवसर प्रदान करेगी, उनके करियर के लिए, रोजगारध्स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी, विविध भाषा दक्षता, व्यक्तित्व विकास, विद्यर्थियो के जीवन में उत्साह उमंग के साथ उनके जीवन को धन्य होगाद्य आज के युवाओ में अंग्रेजी कान्वेंट स्कूल परंपरा के कारण भारतीय शिक्षा पद्धति, जीवन दर्शन, परम्पराए, विरासते, संस्कृति की और ध्यानआकर्षण कम हो रहा था, इस शिक्षा नीति में उक्त सभी विषयों का विद्यार्थियो में भरपूर प्रचार—प्रसार एवं ज्ञान प्राप्त होता रहेगा।

२. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में विद्यार्थियो को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी की वह मनपसंद किसी भी संकाय, विषय को चून सकेगाद्य विद्यार्थियो का सबल पक्ष यह भी होगा कि वो १ वर्ष से लेकर ४ वर्ष तक किसी भी कारणवश अध्ययन छोड़ना चाहे या छोड़ी हुई डिग्री पाठ्यक्रम को अन्तराल के बाद करना चाहे तो, विद्यार्थी कर सकेगा, विद्यार्थी के सभी वर्षो के प्राप्तांक अन्तराल के बाद भी संरक्षित रहेंगे, इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंको अथवा क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of

Credit) दिया जाएगा द्य इसके आधार पर वह किसी भी शिक्षण संस्था को बदलना चाहे तो बदल सकेगा। यह सभी व्यवस्था विद्यार्थी के लिए यह सुविधा वरदान साबित होंगी। शिक्षा नीति का यह लचीलापन का गुण विद्यार्थियो के लिए उनके जीवन में स्वतंत्रता के साथ समय प्रबंधन कर सकेगा, यह नीति का श्रेष्ठतम गुण है।

३. NEP-२०२० में मुख्य विषय इसका मस्तिष्क एवं दिमाग (Brain) है, वही माइनर गौण विषय इसकी की आत्मा (Soul), इलेक्टिव (Open Elective) विषय इसका मेरुदंड (Backbone) है, साथ व्यासायिक विषय (Vocational) को (Brain with Will-power skill Art) बोद्धिक इच्छाशक्ति के साथ कौशल कला विकास कहा जा सकता है।

४. व्यावसायिक विषय (Vocational) से विद्यर्थियो में अपने करियर को बनने के लिए रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान हो सकेंगे, इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपना लघु शौध प्रबंध परियोजना कार्य/ इंटर्नशिप, (Internship/ Project) कार्य पूर्ण कर विषय में दक्षता हासिल कर सकेंगे, इस कार्य से विद्यार्थियो में व्यावसायिक कौशल विकास (Entrepreneurship Development skill) आ सकेगा। नीति के इस खंड से विद्यार्थी अपनी रूचि का विषय चुन सकेंगे, यह अपने आप में एक अचूक वरदान है, करियर बनाने की दिशा में, इसका लाभ उठाकर विद्यार्थी जीवन में आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को पूर्ण रूप लागु करने में विश्वविध्यालय एवं कॉलेज स्तर पर संस्थागत चुनौतियाँ —

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को पूर्ण रूप लागु करने में शैक्षणिक संस्थाओ को निम्न चुनोतियो का सामना करना पढ़ सकता है।

१. विश्वविध्यालय एवं कॉलेज में स्नातक स्तर पर शिक्षा नीति—२०२० अनुसार पाठयक्रम में तीसरा विषय जो इलेक्टिव (Elective-subject) को जिस प्रकार से विज्ञान, कला, वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियो को विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है,ऐसे में यदि कला या वाणिज्य महाविद्यालय का विद्यार्थी विज्ञान संकाय के विषय को चुनेगा। तो सम्बंधित विषय के लिए आवश्यक प्रयोगशाला तकनिकी एवं रसायन, उपकरण संसाधन की व्यवस्था जुटाना एक चुनोती होगी। भारतीय परंपरा, विरासत, दर्शन, संस्कृति साहित्यिक आदि नए विषयों की सूची लम्बी होगी, इनके शिक्षण की व्यवस्था, मूल्यांकन, के लिए शिक्षक के पेनल तैयार करना भी चुनोतिपूर्ण रहेगा। साथ ही विज्ञान, कला और वाणिज्य सभी में सम्बंधित विषय के सभी संस्था में सभी विषय के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना भी एक चुनोती होगी। परन्तु इन सभी चुनोतियों को ध्यान में रखकर सरकार के दिशा निर्देश पर विद्वान (शिक्षादूत, Ambassador) प्राध्यापको की पेनल बनाकर उन्हें ट्रेनिंग देकर तैनात किये जायेगे खंड स्तर पर निगरानी समिति बनाई जाएगी जो सतत निरक्षण करेगी, सुझाव और सुधार करेगे। आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु राज्य और केन्द्रीय सरकार के सहयोग से जीडीपी का अनुपातिक आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

२. विश्वविध्यालय एवं कॉलेज में स्नातक स्तर पर शिक्षा नीति—२०२० अनुसार पाठयक्रम में के चौथे पाठ्यक्रम में (Vocational course) व्यावसायिक विषय चुनने के स्वतन्त्र व्यवस्था की गयी है, जो विद्यार्थियो के भविष्य व करियर, व्यावसायिक दक्षता, निर्माण से सम्बंधित है, इसके परिणाम अच्छे मिलने के आसार है, इसमे भी (Elective subject) जैसे ही प्रायोगिक कार्य के साथ परियोजना कार्य/ इंटर्नशिप की जाएगी। इसमे भी विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, सभी में सभी विषय विशेषज्ञ प्राध्यापको की, व्यवस्था करनी एक चुनोती होगी, परियोजना कार्य/ इंटर्नशिप के लिए विद्यार्थी दुसरे विभाग में जायेगे यैसे सभी विभागों की कार्य करवाने की इच्छाशक्ति व संसाधन पर निर्भर करेगा जिसे दिशानिर्देश अनुसार निर्देशित करना होंगे। साथ ही इसी (Vocational course) व्यावसायिक विषय में प्रायोगिक कार्य भी संपन करवाना होगा, जिसके लिए प्रयोगशाला एवं आवश्यक तकनिकी—रसायन, उपकरण संसाधन की व्यवस्था करना भी, चुनोतिपूर्ण होगा। विषयों की विविधता के कारण शिक्षण व मूल्यांकन पद्धति को विकसित करना होगा।

३. विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में स्नातक स्तर पर शिक्षा नीति—२०२० के अनुसार पाठयक्रम में भारत की राष्ट्रभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषाए भी सिखाई जाएगी, छात्रो के भविष्य निर्माण में भाषाई दक्षता में कमी को, अवरोधक नहीं बनने दिया जायेगा, इस हेतु महाविद्यालय/विश्वविद्यालयो में सम्बंधित भाषाई दक्षता वाले शिक्षको की पेनल तैयार करना होगा। क्षेत्रीय भाषा के लिए भी दक्षता वाले शिक्षको की पेनल तैयार करना होगी।

**उपसहार —**

सन १९८६ में भारतवर्ष की जनसँख्या ६८ करोड़ थी, समय के साथ जनसँख्या में दोगुनी वृद्धि हो गई, अब २०२० में भारत की जनसँख्या १४० करोड़ हो गई है, एसे में बढती जनसँख्या और घटते प्राकृतिक संसाधन और इन संसाधनों में मांग की आपूर्ति भी एक चुनौती है, मानव संसाधनों का जनसँख्या के अनुपात अनुसार प्रबंधन करने के लिए, पुरानी शिक्षा नीति १९८६ जिसमे परम्परागत विषय संकायों का संचालन पर्याप्त नहीं था,एसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० की आधुनिक आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को पारित करना, लागु करना जरुरी हो गया थाद्य वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को लागु करने से भारत के विद्यार्थियो में उत्साह है और अब ये उनकी वक्त के साथ आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकेगी, विधार्थी नई आधुनिक तकनिकी विषयो सुचना प्रद्योगिकी, व्यावसायिक दक्षता, भारत की प्राचीन विरासतों, भारतीय जीवन दर्शन, कला, योग, वैदिक ज्ञान, भारतीय शिक्षा पद्धति, हमारी धरोहरे, भाषाई दक्षता सीख सकेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० से भारत की इकॉनमी बढेगी रोजगार के अवसर मिलेंगे, और भारत दुनिया की शक्ति बनकर उभरेगा, भारत विकाशील देश से विकसित देश होने की दिशा में तेजी से बढेगा, विद्यार्थियो का जीवन धन्य होगा उनमे साहित्यिक, रचनात्मक कौशल का विकास होगा, और विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनेगेद्य

**संदर्भ (References):**

१. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार (१ से १०३ ist ) राजपत्र भारत सरकार.

2- Kumar, K- (2005)- Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India- Indian Educational Review 2- Draft National Education Policy 2019-

३. बिरेन्द्र सिंह २०२२, उच्च शिक्षा के विशेस सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० २०२२ IJRAR January 2022, Volume 9, Issue 1 www-ijrar-org (E&ISSN 2348&1269, P& ISSN 2349&5138).

४. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० THE VISION ट्रस्टी.

५. गिरीश्वर शर्मा राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० ''संभावनाएं एवं चुनोतियाँ, ISSN २५८२—६५३०, कंचन जंघा पत्रिका.

६. नरेश कुमार २०२०, भारतीय आधुनिक शिक्षा ISSN&0972&5636 NCERT पत्रिका.

७. HANS SHODH SUDHA- Vol- 1, Issue 3, (२०२१), pp- ५९—६२.

❑❑❑

**13**

# स्टार्टअप प्रबंधन

**परागी गुप्ता**
विद्यार्थी, एम.ए. राजनीती विज्ञान

***********

**संक्षिप्त परिचय :**

किसी कम्पनी, साझेदारी था अस्थायी संगठन के रूप में शुरू किए गए उद्यम या नए व्यवसाय को स्टार्टअप कहा जाता है जो किसी कम्पनी के संचालन के प्रथम चरण को संदर्भित करता है तथा ये इकाईया जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यावसायीकरण की दिशा में काम करती हैं उसे 'स्टार्टअप प्रबंधन' की संज्ञा दी जाती हैं।

आज भारत महान अवसरों की दहलीज पर खड़ा हैं । तेजी के साथ आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था और ग्रामीण एवं शहरी साक्षर युवाओं की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का व्यापक आधार इसे एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिसकी बदौलत भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा हैं।

स्टार्टअप्स हो या डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो या फिर ५जी टेक्नोलॉजी, भारत हर क्षेत्र में सफलता के झण्डे गाड़ रहा हैं। देश में जिस तेजी से स्टार्टअप्स और यूनिकॉन की संख्या बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में स्टार्टअप के लिए यह स्वर्णिम काल हैं।

**आखिर स्टार्टअप प्रबंधन क्यों ?**

वो इसलिए कि भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया मिशन जैसे कई कार्यक्रमों की वजह से ही नए उपक्रमों को काम करने में मदद मिल रही हैं जिससे ग्रामीण विकास से लेकर कृषि कार्यो से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिल रहा हैं साथ ही कौशल आधारित संज्ञान अथवा अधिगम एवं रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं। पिछले एक दशक में कई स्टार्टअप्स अस्तित्व में आए हैं जिससे ग्रामीण जीवन आसान व देश के सीमान्त और सुदूर क्षेत्रों तक कई राज्यों में इनका विस्तार हो रहा है।

इस दिशा में निरंतर सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष २०१६ के ४७१ से बढ़कर वर्ष २०२२ में ७२,९९३ हो गई हैं, जिसमें महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी करीब १४ प्रतिशत हैं।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रेबोटिक्स, कत्रिम बुद्धिमत्ता, एनालिटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित क्षेत्रों में ४५०० से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई हैं।

भारत को स्टार्टअप्स के लिए इसकी विशाल वाणिज्यिक क्षमता के लिए प्रायः 'उभरते बाजारों के पोस्टर चाइन्ड' के रूप में वर्णित किया जाता हैं। दुनिया के कई अन्य भागों की तरह भारत में भी स्टार्टअप्स पर हाल के वर्षो में अधिक ध्यान दिया गया हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही हैं और उन्हें व्यापक रूप से विकास एवं रोजगार सश्जन के महत्वपूर्ण इंजन के रूप में चिन्हित किया जा रहा हैं।

हालांकि दूरंदेशी नीतियों और वित्तीय बाध ााओं की कमी के कारण, भारत के स्टार्टअप पारितंत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। इस परिदृश्य में प्रभावशाली स्टार्टअप समाधान उत्पन्न करने के लिए नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता हैं। इस प्रकार यह भारत के सामाजिक—आर्थिक विकास और परिवर्तन के लिए एक वाहन के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है।

भारत में स्टार्ट—अप पारितन्त्र की वर्तमान स्थिति — वर्ष २०२१ में भारतीय स्टार्टअप्स मे १००० से अधिक सौदों के माध्यम से २३ बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए और ३३ स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के रूप में उभरे। वर्ष २०२२ में अभी तक यूनिकॉर्न क्लब में १३ और भारतीय स्टार्टअप शामिल हो चुके है।

स्टार्टअप पारितन्त्र के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। बेनएंड कंपनी (Bain and company) द्वारा प्रकाशित इंडिया वेंचर कॅपिटल रिपोर्ट, २०२१ के अनुसार भारत

में संचयी स्टार्टअप की संख्या वर्ष २०१२ से १७ प्रतिशत के चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (CAGR) से बढ़ी है और १,१२,००० की संख्या को पार कर गई हैं।

**हतंची :**

विश्व में भारत इस क्षेत्र में तीसरे स्थान पर हैं प्रथम स्थान ै। व द्वितीय पर चीन विद्यमान हैं।

वहीं भारत में प्रथम स्थान पर बेंगलुरु व अन्तिम अथवा १० वें स्थान पर गोवा है।

बेंगलुरू का स्टार्टअप प्रतिशत लगभग ८ फीसदी हैं जबकि गोवा का २ फीसदी।

इस भागदौड़ वाली दुनिया में कितना जरूरी हैं तकनीक आधारित स्टार्टअप्स का होना — ? आइए जानते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक आधारित स्टार्टअप्स के मायने—

तकनीक का सम्बन्ध केवल मशीनी प्रत्ययों से नहीं, बल्कि इसमें वैज्ञानिक विधाओं और ज्ञान विधियों का व्यावहारिक अनुप्रयोग भी होता हैं। यह अनुप्रयोगों द्वारा समस्याओं का व्यावहारिक समाधान करती है और कार्यप्रणाली में सुगमता लाती हैं। दुनिया का हर तकनीकी आविष्कार सामाजिक— आर्थिक वर्ग में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए उत्प्रेरक रहा हैं जिसने अपने दौर की कार्य प्रक्रियाओं की पुन: परिभाषित कर प्रतिस्पर्धी आर्थिक लाभ के नए मानक स्थापित किए हैं। जिसमें स्टार्टअप एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो एक ऐसे उत्पाद या सेवा का विकास करना चाहते हैं जिसकी बाजार में मांग या समाज में आवश्यकता हैं।

ये कंपनिया प्राय: सीमित राजस्व के साथ शुरू होती हैं। देश में उद्योग एव आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप से संबंधित ५६ विविध क्षेत्रों को मान्यता दी हैं. और भारत का स्टार्टअप पारितंत्र १२—१५ प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद हैं। आज देश भर में फैले सैकड़ों तकनीकी स्टार्टअप ग्रामीण जीवन को सुगमता प्रदान कर विकास की मुख्यधारा में ला रहे हैं।

आधुनिक तकनीक और इंटरनेट इत्यादि में विश्व—स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। आईटीसी ग्रुप के मिशन सुनहरा कल (एमएसके) का उद्देश्य जल और वन संसाधनों को विकसित करने के लिए स्थानीय समुदायों की साझेदारी में ग्रामीण क्षमता का निर्माण करना, नए गैर—कृषि आजीविका को खोलना, महिलाओं को सशक्त बनाना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और भारत में 'फ्यूचर स्किल' को विकसित करना हैं।

इसका एग्री बिजनेस समूह ग्राम दत्तक ग्रहण कार्यक्रम चल रहा हैं। इसमें आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान के २५० मॉडल गाँव शामिल हैं।

**स्टार्टअप के विभिन्न क्षेत्रों में तरीके —**

स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप — स्टार्टअप पेयजल से लेकर कृषि कार्यों से जुडी समस्याओं का समाधान लेकर आ रहा हैं और स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से कई समस्याओं का समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में इनका विस्तार हो रहा हैं।

जैसे—ओलपाड जो अरब सागर से सटे सूरत जिले का एक तरीय गांव हैं, यहां समुद्र का खारा पानी पीने और रोजमरों की दूसरी जरूरतों के लायक नहीं होता, पानी की किल्लत रहती हैं व स्थानीय लोंगों को पानी के लिए हमेशा टैंकर का इंतजार रहता था लेकिन चार साल पहले सोलंस टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप ने स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाला एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाया जा सकें। इसकी सफलता के बाद अब यह तकनीक भारत के कई तटीय इलाकों में बल समस्या को हल कर रही हैं।

विमल पंजवाणी द्वारा २०२० में शुरू किया गया एग्री—विजय स्टार्टअप महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाको के किसानों को सौर पम्प, बायोगैस डाइजेस्टर व स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले कई उपकरणों से कृषि क्षेत्र की समस्याओं से राहत दिला रहा हैं।

शिंकरां स्टार्टअप ने ओडिशा कालाहांडी में किसानों की स्वच्छ ऊर्जा और इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी से जोड़ा। रसने 'कृषिधेनु' नामक सौर ऊर्जा से चलने वाला एक संयंत्र बनाया जिससे कीटनाशकों को बिना पानी और हाथ लगाए खेतो में डालना सम्भव हुआ हैं।

इसने मत्स्य पालन में उत्पादन को बढ़ाने और तालाब की देखरेख हेतु हैदीव्र मित्र नामक उत्पाद भी बनाया हैं।

एक्जल्टा इंडिया स्टार्टअप ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली वातानुकूलित मशीन (एयर कंडीशनर) बनाई, जा सीधे करंट से चल सकती हैं।

**ग्रामीण आजीविका स्टार्टअप** –

भारत जिस गति से स्टार्टअप पारितंत्र का केन्द्र बन रहा है, कमोवेश उसका प्रभाव ग्रामीण भारत में भी बढ़ रहा है और ग्रामीण भारत में सक्रिय रूप से काम कर रहे स्टार्टअप्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं।

फ्रंटियर मार्केट्स स्टार्टअप सौर या हरित ऊर्जा उत्पाद बेचने से शुरू होकर अब महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण आजीविका, सम्मानजनक आय के अवसर प्रदान करता हैं।

इसने 'सहेलिस' नामक ११ हजार महिला बिक्री बल के मजबूत नेटवर्क के साथ विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रवेश किया है। इसने अपने उत्पाद पोर्टफोलियों को एनर्जी एक्सेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एग्री इनपुट्स, एफएमसीजी, फिनटेक उत्पादों और सेवाओं तक बढ़ा दिया है।

स्टार्टअप विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई को डिजीटल वेबस्टोर बनाने में सक्षम बना रहा हैं जिससे उन्हें सस्ती सोर्सिंग, समकालीन डिजाइन क्यूरेशन, अनुकूलन और उत्पादों के वर्गीकरण के साथ घरेलू और अंतरर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना कारोबार फैलाने में मदद मिल रही हैं।

जल संरक्षण और तकनीकी स्टार्टअप –कम लागत, टिकाऊ, उचित जल प्रबंधन समाधानों की कमी के कारण भारत में ७० प्रतिशत से अधिक सीवेज को अनुपचारित, प्रदूषित नदियों, तटीय क्षेत्रों और कुओं से देश के तीन–चौथाई जल को बहा दिया जाता है। अनुमान हैं कि अकेले भारत का कुल जल और अपशिष्ट जल उपचार बाजार करीब ४२० मिलियन डॉलर का हैं, जो सालाना १८ प्रतिशत बढ़ रहा हैं। आज उपचारों के विकल्पों की कमी अपशिष्ट जल की समस्याओं की जन्म दे रही हैं। जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। परन्तु इस दिशा में कार्यरत स्टार्टअप्स के प्रयासों से पानी की खपत और संरक्षण की लगातार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल उपचार के सरल तरीके, तेजी से प्रमुख समाधान के रूप में उभर रहे हैं। जैसे–

'अमृत' स्टार्टअप्स प्रबंधन एक स्वदेशी पहल हैं। जो बिजली का प्रयोग किए बिना सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने, आर्सेनिक को अवशोषित करने, धातुओं को हटाने और पेयजल में उपलब्ध कीटनाशक सामग्री को डाउनग्रेड करने के लिए नैनो तकनीक का उपयोग करता हैं।

'उरातु' यह लैब्स तकनीक केन्द्रित स्टार्टअप है और इसने शत–प्रतिशत नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करके ''हवा से पानी का स्त्रोत'' बनाने के लिए कई उत्पादों का निर्माण किया हैं।

'वीगाट' स्टार्टअप ने आईओटी आधारित एंड–टू–एंड जल प्रबंधन समाधान के रूप में किफायती अल्ट्रासोनिक सेंसर वेनएक्वा स्थापित किए हैं।

'स्वजल' स्टार्टअप ने सभी के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुँच को सुलभ बनाने और पानी की चुनौती से निपटने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ऊर्जा कुशल पानी के एटीएम स्थापित किए हैं जो जल शोधन और वैडिंग के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और मरम्मत, उन्नयन आदि हेतु आईओटी आधारित रिमोट मॉनिटरिंग क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं।

स्वजल ने रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, शहरी झुग्गियों, ग्रामीण क्षेत्रों, बस स्टेशनों आदि में ४०० से अधिक वॉटर एटीएम स्थापित किए हैं। इसने अब तक देश के १७ राज्यों में ५ लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया है और अगले २ वर्षों में २ करोड़ लोगों को लाभावित करने की योजना हैं।

कृषि और तकनीकी स्टार्टअप – भारत का कृषि क्षेत्र भी तकनीकी स्टार्टअप के लिए अनगिनत संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी कृषि भूमि हैं और करीब ६० प्रतिशत ग्रामीण भारतीय परिवार कृषि से अपना जीवनयापन करते हैं। भारत में कृषि तकनीक केंद्रित स्टार्टअप उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने और किसानों को प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान

करने के लिए बहुमुखी संसाधन आवंटित कर रहे हैं। जैसे—

कामेश गुपराजू और लिनुस लिंडग्रेन द्वारा स्थापित एसकार्म्स इंडिया स्टार्टअप — कृषि क्षेत्र में लिस्टिंग और अंश व्यापार का कार्य करता हैं। लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर खरीदार कृषि भूमि ढूँढ सकते हैं और विक्रेता कृषि भूमि को बिक्री या पट्टे के लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं। इस तरह किसानों हेतु डिजिटल भूमि अनुबंध द्वारा उपलब्ध कृषि भूमि के लिए एक प्रभावी और कुशल मंच बनाकर तथा कीमतों को बढ़ाकर मुनाफा कमाने वाले बिचौलियों ने खत्म करने का काम किया गया है।

प्रवीण शिंदे और विष्णु घास द्वारा स्थापित 'खेतीगाड़ी' स्टार्टअप — दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म हैं, जहां कोई भी ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी को खरीद खेच, किराए पर लेने और लेनदेन के लिए तुलना और समीक्षा कर सकता हैं। यह कृषि मशीनीकरण और कृषि में प्रौद्योगिकी व उच्च तकनीक उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करता हैं। हाईटेक कोणीय तकनीक पर निर्मित एग्रीटेक 'खेतीबाड़ी' पोर्टल ५० लाख किसानों से जुड़ा हैं।

कृषि तकनीक केंद्रित स्टार्टअप न केवल देश में खेती करने का तरीका बदल रहे हैं बल्कि यह गरीबी को कम करने और खेती में सुधार के लिए विस्तृत सुविधा और सुगमता की आपूर्ति भी कर रहे हैं।

**१. स्वास्थ्य देखभाल और तकनीकी स्टार्टअप—**

स्वास्थ्य सेवा एक मौलिक अधिकार होने के बावजूद भारत में अभी तक इतकी सुलभता न तो सार्वभौमिक हैं और न ही समावेशी हैं। भारत मुश्किल से अपनी जीडीपी का १.३ प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च कर पा रहा है और अभी भी कोई ग्रामीण व अर्ध—शहरी क्षेत्रों की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं हैं। फिलहाल ५१ हजार से अधिक लोगों के लिए केवल एक प्राथमिक स्वास्थ सेवा केंद्र हैं, जिसमें मुश्किल से स्टॉफ के नाम पर एक डॉक्टर होता हैं।

— 'चिकित्सक' एक हेल्थटेक स्टार्टअप हैं। इसका उद्देश्य सस्ती प्राथमिक स्वास्थ सेवा तक पहुँच प्रदान कर ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल समाधान लाना है। यह स्टार्टअप ज्यादातर गैर संचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित करता है और मरीजों को सस्ती कीमतों पर लागत प्रभावी जॉंच व सुविधा प्रदान करता है।

आवाज ऐप आधारित स्टार्टअप है । यह ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या बोलने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए संचार शुलभ कराता है। इसके ७५ हजार से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं

मातृत्व स्टार्टअप का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के लिए जटिलताओं को रोकना, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान ट्रेकिंग करके सुरक्षित प्रसव को सक्षम बनाना हैं।

'नेटमेड्स' एक स्वास्थ्य स्टार्टअप और अग्रणी ऑनलाइन फार्मेसियों में से एक हैं, जो लाखों ग्राहकों को दवा और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की खरीदारी प्रदान करता हैं।

**ऐसी कौन—सी चुनौतियाँ हैं जो बनती हैं बाधाएँ स्टार्टअप प्रबन्धन के मार्ग में—? तो आइए जानते हैं—**

नवाचार पर जोर देने में कमी—भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण और 'इंडस्ट्री एक्सपोजर' का अभाव हैं जो छात्रों को नवाचार उन्मुख होने से वंचित रखता है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली अनुसंधान एवं विकास के मामले में पीछे रह जाती है।

इसके कारण युवा प्रतिभाएं विदेशों में अनुसंधान और व्यापार के लिए भारत से पलायन कर रही हैं, जिसकी देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती हैं।

पहचान की कमी — लगभग ७० प्रतिशत भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं जो अभी भी विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच से वंचित हैं। इसके कारण ग्राम आधारित कई स्टार्टअप चिन्हित नहीं हो पाते और सरकारी वित्तपोषण पहल के लाभ से वंचित रह जाते हैं 'स्केलेबिलिटी' सम्बन्धी चिंता— भारत में छोटे स्टार्टअप के पास ग्राहकों की सीमित समझ होती हैं और वे केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं, जहाँ वे स्थानीय भाषा और स्थानीय लोगों की समझ रखते हैं।

— इस भाषाई बाधा और कनेक्टेड आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमी के कारण स्टार्टअप्स के लिए अपने उत्पादों को देश भर के ग्राहकों तक पहुँचाना कठिन हो जाता हैं।

'बूटस्टैण्ड स्टार्टअप' स्टार्टअप के कार्यान्वयन के लिए उल्लेखनीय मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। भारत में कई स्टार्टअप, विशेष रूप से अपने आरंभिक चरणों में 'बूटस्ट्रैपिंग' के लिए बाध्य होते हैं, यानी संस्थापकों की अपनी बचत के माध्यम से स्ववित्तपोषित होते हैं क्योंकि उपलब्ध घरेलू वित्तपोषण सीमित हैं।

इसके परिणामस्वरूप, भारत में अधिकांश स्टार्टअप पहले ५ वर्षो के अंदर ही विफल हो जाते हैं और इसका सबसे आम कारण हैं औपचारिक धन की कमी।

अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्यन्त सीमित पेठ– फिनटेक और ई कॉमर्स क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप पिछड़े बने रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग ४४० Billion अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें भारत की बाजार हिस्सेदारी २ प्रतिशत से भी कम हैं।

१. इसका कारण हैं – अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वतन्त्र निजी भागीदारी का अभाव

**सुझाव –**

जो होंगे स्टार्ट अप के विकास में सहयोगी कृषि, ऊर्जा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, संचार, परिवहन जैसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए तथा देश के समुचित विकास के लिए विकास गतिविधियों में तकनीकी स्टार्टअप्स का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। अत: स्टार्टअप्स प्रबंधन के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं–

- स्टार्टअप्स उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया पेशेवरों और इंजीनियरों से भरी हुई हैं, जिन्हें वित्त व निवेश की अच्छी जानकारी हैं। वित्तीय और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर उद्यमी बाजार से पूंजी जुटाने में सफल हो सकते हैं।
- बैंकों से पूंजी और नाबार्ड जैसे संस्थानों द्वारा क्रेडिट प्लस सेवाओं का विस्तार करके ग्रामीण स्टार्टअप को सहयोग देने का प्रयास महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता हैं।
- मुहम्मद युनूस द्वारा प्रचारित सामाजिक व्यापार मॉडल से प्रेरणा लेकर स्टार्टअप उद्यमी कम लागत वाले फंड का उपयोग कर सकते हैं।
- एंजेल निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों और निजी इक्विटी धारकों को ग्रामीण स्टार्टअप हेतु प्रोत्साहन दिया जा सकता है। विशेष रूप से, सरकार को ग्रामीण स्टार्टअप क्षेत्र में धन को आकर्षित करने के लिए एक निवेशक अनुकूल व्यवस्था बनानी चाहिए।
- देश में ग्रामीण विकास के अनुकूल कई प्रोद्योगिकियाँ हैं, लेकिन उनका व्यवसायीकरण नहीं किया गया हैं। इसलिए स्टार्टअप निर्माता सार्वजनिक–निजी भागीदारी के तहत सही हितधारकों की पहचान करके, इन तकनीकों को अपनी उपयोगी उत्पादों अथवा सेवाओं में बदलने के लिए सक्रिय हो सकते हैं।
- जलवायु परिवर्तन सतत विकास लक्ष्य और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे स्टार्टअप निकट भविष्य में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।

**आगे की राह**

- स्कूल–उद्यमिता गलियारा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० स्कूल स्तर पर उद्योग और नवाचार के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर छात्र उद्यमियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती हैं
- यदि नई शिक्षा नीति के तहत उद्यम कौशल को शिक्षा पाठ्यक्रम साथ एकीकृत किया जाए तो भारत में स्टार्टअप पारितंत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- उद्यमशीलता का सम्पोषण – उद्यमशीलता के संपोषण के लिए नीति –स्तरीय निर्णयों के अलावा आवश्यक होगा कि भारत कॉर्पोरेट क्षेत्र उद्यमशीलता को बढ़ावा दें और सतत् एवं संसाधन–कुशल विकास के लिए सक्रियताओं का निर्माण करें।

भारत में कम्पनियों को स्टार्टअप के साथ सहयोग करने और विभिन्न कॉर्पोरेट–विशिष्ट संसाधनों के साथ उनका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता हैं। यह संलग्नता परस्पर लाभकारी बन सकती है। हालाँकि, सरकार के डिजिटल भारत का

मिशन के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया हैं तो स्टार्टअप प्रबंधन के इस शोधपत्र में निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि स्टार्टअप्स ने लोंगो के जीवन में प्रौद्योगिकी को सक्षम किया हैं। ये स्टार्टअप ग्रामीण विकास और ग्रामीण विपणन के लिए एक समर्थ संरचना बनाकर टियर—२ बाजार में आजीविका के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये वंचित आबादी पर सकारात्मक प्रभाव लाकर सामाजिक नवाचार, वित्तीय समावेशन, डिजिटल सक्षमता, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुँच को सुगम बना रहे हैं। साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता से लेकर ग्रामीण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही देश के विकास की अवधारणा को बहुमुखी बना रहे हैं।

**सन्दर्भ :—**

➢ गजेन्द्र सिंह गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय चित्रकूट में सहायक प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) के आलेख से।

**इन्टरनेट के माध्यम से —**

➢ https:// www- startupindia.gov.in
➢ https://in-linkedin-com
➢ https://drishtiias.com
➢ कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका

❑❑❑

**14**

# कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण

**वन्दना सिसोदिया**
विद्यार्थी : एम.ए. राजनीति विज्ञान

**********

**सारांश —**

एक देश के तीव्र आर्थिक विकास में महिला सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिये प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विशय मे निर्णय लेने के लिये समर्थ एवं स्वतंत्र होता हैं, इस दृष्टि से देखे तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहु—आयामी दृष्टिकोण हैं। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में महिलाओं के प्रयास व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है, एक देश के तीव्र विकास के लिये महिलाओं को सशक्त बनना अति आवश्यक हैं, महिलाओं के संदर्भ में कौशल विकास का अर्थ केवल महिलाओं को रोजगार प्रदान करना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा किये गये कार्यों में गुणात्मक सुधार कर कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाना तथा उत्पादक बनाना हैं। कौशल विकास उनके रोजगार को सुनिश्चित तो करेगा ही, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सशक्त करने में सहायक होगा। महिला सशक्तिकरण वर्तमान में महत्वपूर्ण विषय है। यह महिलाओं को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित करता है। कौशल विकास महिलाओं में आत्म विश्वास तथा आत्म निर्भरता लाने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। कौशल विकास महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा दोनों में परिवर्तन लाने का सकारात्मक प्रयास है। भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की जहां कार्य शक्ति में भागीदारी का निम्न दर एवं लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं वर्तमा में भी विद्यमान हैं एवं एक चिंता का विषय है। महिला कौशल

विकास अवश्य इस समस्या का समाधान करेगा। कौशल विकास तथा महिला सशक्तिकरण यह दोनों देश के समावेशी तथा संतुलित विकास हेतु आवश्यक हैं।

इस शोध पत्र के द्वारा कौशल विकास एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के पारस्परिक संबंधों एवं कौशल विकास की आवश्यकता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

सतत् विकास का लक्ष्य करने के लिए महिला कौशल विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है।

**मूल शब्द** — कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन।

**परिचय** —

यह सत्य है कि महिलाओं की भागीदारी एक परिवार और समाज के विकास में हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है एवं पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की कार्यस्थल से जुड़ी भूमिका में परिवर्तन आया है। वर्तमान में हमारा संविधा महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करता है। लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं से भेदभाव, मजदूरी दर में भिन्नता, निम्न महिला भागीदारी आदि समस्याएँ आज भी पायी जाती है। अधिकांश कार्य करने वाली महिलाएँ अप्रशिक्षित है, अकुशल हैं। यही कारण है कि वह असंगठित भी हैं।

महिलाओं की श्रमिक सहभागिता दर १९९० में ३५ प्रतिशत थी, जो साल २०१८ में गिरकर २७ प्रतिशत रह गयी, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट २०२१ में १५६ देशों की सूची मे भारत १४० वें स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर में बहुत तेजी से गिरावट हुई है महिला श्रमबल भागीदारी दर २४.८ प्रतिशत से गिरकर २२.३ प्रतिशत रह गयी है, वरिष्ठ एवं प्रबंधक पदों पर केवल १४.६ प्रतिशत महिलाएँ हैं केवल ८.९ प्रतिशत कम्पनियाँ ही ऐसी है जहाँ शीर्ष प्रबंधक पदो पर महिलाएँ अपना योगदान दे रही है। महिला कार्य शक्ति भागीदारी भारत में लगभग ३१.८ है जो कि पुरुश कार्य शक्ति भार्गी परी दर ७३.२ से आधी से भी कम है।

इस स्थिति के लिये सामाजिक एवं आर्थिक दोनो कारण में जिम्मेदार है, महिलाओं की स्थिति में सुधार अवश्य होगा परन्तु इसके लिये उनकी कार्य उत्पादकता में सुधार आवश्यक है महिलाओं से जुडी समस्याएँ जैसे— लैंगिक भेदभाव, लैंगिक आधार पर वेतन में विसंगतियां लैंगिक आधार पर पदों का बटवारा तभी दूर हो पाएंगी जब महिलाओं के कौशल विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे।

**कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण —**

किसी भी समाज व देश के विकास एवं वृद्धि के लिये उस समाज एवं देश की महिलाओं का शिक्षित व कौशलपूर्ण होना बहुत की आवश्यक है एक महिला के शिक्षित होने से दो परिवार शिक्षित होते है एवं एक महिला के कौशलपूर्ण होने से सामाजिक परिवर्तन होता है जब समाज में शिक्षा का अभाव था तो महिलाओं को केवल घर के कामों के लिये ही उपयुक्त माना जाता था और उन्हें घर तक ही सीमित रखा जाता था लेकिन समाज में शिक्षा के विस्तार से समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदली है और अब महिलाएँ घर व बाहर दोनों जगह अपनी भूमिका बखूबी निभाने का प्रयत्न कर रही हैं परन्तु इतना कुछ होने के बाद यह भी सत्य हैं की समाज मे महिलाएँ अभी भी सबसे ज्यादा अशिक्षित एवं अकुशल हैं।

अत: कौशल विकास के माध्यम से ही हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है यह उनकी कार्य भागीदारी में उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि करेगा, आज के समय की माँग है कि महिलाएँ निम्न कौशलो को अवश्य प्राप्त करें

१. संचार कौशल
२. नेतृत्व कौशल
३. निर्णय शक्ति कौशल
४. सामूहिक संघ कार्य कौशल,
५. समय प्रबंधन कौशल
६. रचनात्मकता कौशल
७. लोच शीलता एवं अनुकूलनशीलता कौशल
८. समस्या निवारण कौशल

९. व्यक्तित्व विकास कौशल

१०. प्रबंधन कौशल

११. लेखांकन कौशल

१२. कम्प्यूटर कौशल

१३. आधार नीति कौशल

१४. व्यावहारिकता कौशल

**समस्यायें :**

कौशल विकास द्वारा महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्यायें कम नहीं है।

**१. सामाजिक आदर्श —**

पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई इलाकों में लोगों के घर से निकलने पर महिलाओं पर रोक हैं। ऐसे क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा व रोजगार के लिये घर से बाहर जाने की आजादी नहीं है ऐसे माहौल में रहकर महिलाएं खुद को पुरुषों से कमतर मानती हैं और अपनी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलने में असफल रहती है।

**२. कार्यस्थल पर शारीरिक शोशण**

कार्यस्थल पर शोशण श्री महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। सेवा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल जैसे निजी क्षेत्र इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है समाज में पुरुश प्रधानता के प्रभुत्व के कारण यह महिलाओं के लिये अधिक समस्याएँ पैदा करता है। हाल के दिनों में कामकाज के क्षेत्र में महिलाओं के उत्पीड़न में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और पिछले कुछ दशकों में इसमें करीब १७० प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

**३. लैंगिक भेदभाव —**

भारत में आज भी लिंग स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है कई क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिये बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। साथ ही उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने या परिवार से जुड़ी कमियों को उठाने की आजादी नहीं होती हैं और हर काम में उन्हें हमेशा पुरुशों से हीन समझा जाता है। इस प्रकार के भेदभाव से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति खराब होती है तथा महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

**४. भुगतान/मजदूरी में असामनता—**

भारत में महिलाओं को उनके पुरुश समकक्षों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, और असंगक्ति क्षेत्र में समस्या और भी बदतर है। खासकर दैनिक मजदूरी वाले स्थानों में। समान मात्रा में काम करने के बाबजूद, महिलाओं को पुरुशों की तुलना मे बहुत कम भुगतान किया जाता है, और इस तरह के काम महिलाओं और पुरुशों के बीच शक्ति असमानता को दर्शाते है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं वो अपने पुरुश समकक्षों के समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद पुरुशों की तुलना में कम चेतन दिया जाता है।

**५. अशिक्षा —**

महिलाओं में अशिक्षा और पढ़ाई छोड़ देने जैसी समस्याएँ भी महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधाएँ है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में से लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यो हो इस मामले में बहुत पीछे है। भारत में महिला शिक्षा दर ६४.६ प्रतिशत है, जबकि पुरुशों की शिक्षा दर ८०.५ प्रतिशत हैं। कई ग्रामीण लड़कियाँ जो सरकार जाती हैं उनकी भी पढ़ाई छूट जाती है और वे दसवीं कक्षा भी पास नहीं कर पानी है।

**६. बाल—विवाह—**

पिछले कुछ दशकों में सरकार द्वारा लिखे गए प्रभावी फैसलों से भारत में पथ—विशद प्रचलन में आने कमी आई है, लेकिन २०१८ में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अभी भी साम १५ लाख लड़कियां बाल—विवाह का शिकार होती है। १८ वर्श से पहले विवाह करने से महिलाओं का प्रारंभिक विकास हो जाता है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाती है।

**७. महिलाओं के खिलाफ अपराध—**

भारतीय महिलाओं के खिलाफ कई घरेलू हिंसा के साथ—साथ दहेज, ऑनर फिलिंग और ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराध भी देखने को मिलते हैं। हालांकि, यह काफी विचित्र है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में आपराधिक हमलो से अधिक पीडित होती है।

इस प्रवर हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक रूप से इतने विकसित, हो जाने के बावजूद भी हम आज भी एक पुरुश प्रधान समाज के रूप में जाने जाते हैं और यही पुरुशवादी सोच हमारी सोच का हिस्सा बन गयी है बस यही सोच से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और इसी कारण समान में आज भी महिलाओं को पुरुशों के समान स्थान अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा नहीं मिल पा रहे हैं जो की चिंता का विशय आज भी बने हुये हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी दयनीय हैं ऐसे में महिलाओं के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य अत्यंत कठिन हैं, सरकार प्रयास अवश्य करती है परन्तु अपने द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन सही से नहीं कर पाती हैं ये महिलायें जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं उन्हें प्रशिक्षण देना तो और भी कठित करते है क्योंकि अशिक्षा व गरीबी बाधा बन कर बीच में खड़े हो जाते हैं ऐसा नहीं हैं कि सरकारी व गैर सरकारी प्रयास नहीं हो रहे हैं परन्तु अभी भी सफलता पर काफी कम हैं।

**८. कौशल विकास — महिला सशक्तिकरण के लिये एक शर्त —**

भारत अपने उज्जवल और जीवंत युवाओं के लिये दुनिया भर में जाना जाता है, कई देशों में कामकाजी आबादी की मात्रा दिन—ब—दिन कम हो रही हैं भारत को..... है क्योंकि इसका जनसांख्यिकीय लाभांश युवाओं की और अति रूप में झुका हुआ है। एक भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था को वर्ष २०१७—२०२२के बीच लगभग १०३ मिनियन (डद) कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। इसके बावजूद ३० फीसदी से ज्यादा यानी १५—२४ आयु वर्ग के १०० मिलियन युवा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण (एनईईटी) में नहीं है। इस १०० मिलियन युवाओं में लगभग ८८.५ मिलियन युवा महिलाएँ है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में व्यावसायिक

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली कामकाजी महिलाओं के अनुपात में निश्चित रूप वृद्धि हुई हैं। लेकिन यह वृद्धि पुरुषों द्वारा प्राप्त की जाने तुलना में स्पष्ट रूप से कम है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली कामकाजी उम्र की महिलाओं का.. २०११—२०१२ में ६.८ प्रतिशत से बढ़कर २०१८. ..में ६.९ प्रतिशत हो गया जबकि पुरुशो के अनुपात में वशद्धि १४.६ प्रतिशत से बढ़ गई २०१८— २०१९ में १५.७ प्रतिशत हो गई जो कि महिलाओं के अनुपात से काफी ज्यादा है।

कॉविड—१९ की दूसरे लहर में दुनिया में आने से पहले ही औद्योगिकी में प्रगति और काम करने के लिए विभिन्न नौकरियों को बाधित कर दिया है।

एक लिंग आधारित डिजिटल विभाजन बढ़ गया। जीएसएमए की ''कनेक्टेड वुमेन— द मोबाईल जेंडर गैर रिपोर्ट २०२१'' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार २०२० के सेल्स फोन रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत ४१% पुरुशों की तुलना में २५ था।

कोविड—१९ से पहले भी अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा भारत में कौशल प्रशिक्षण और श्रम बाजार में महिला भागीदारी पर बाधाओं की पहचान करने के लिए लिंग अध्ययन'' शीर्षक से एक अध्ययन में दावा किया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित २८.३ महिलाओं ने यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को एक कारण के रूप में उल्लेख किया था। सार्वजनिक स्थानों पर लैंगिक हिंसा का खतरा बढ़ गया था, जिसके कारण महिलाओं की गति शीलता और भी प्रतिबंधित हो गई थी।

**९. सुझाव —**

एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है महिला संविधान किसी भी देश के प्रभावशाली विकास के लिए अद्भुत संगम से एक है।

यह मुख्य रूप से उनके कौशल और ज्ञान से महिला संविधान की सामजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की प्रक्रिया है दुनिया भर में कई उद्यमी भभी महिलाओं को समाज में सबसे आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसे कई उपाय हैं जो महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहें है।

(१) बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ

(२) महिला व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा

को प्रोत्साहन

(३) लैंगिक संवेदनशीलता

(४) प्रशिक्षण केन्द्रो का विस्तार

(५) वित्त प्रबंधन

(६) महिला उद्यमिता का विकास

(७) डिजिटल प्लेटफार्म का विस्तार

(८) रोजगार अक्सरों में वशद्धि

(९) स्वरोजगार को प्रोत्साहन

यह सत्य हैं कि सशक्त का महिला वहीं है जो आर्थिक रूप से समश्द्ध है महिला आर्थिक रूप से तभी समृद्ध होगी जब शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी तथा कौशल विकास होगा, इसके लिये गाँव तथा शहर के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में प्रारम्भ से ही कौशल ज्ञान हो प्रोत्साहन मिलना चाहिये, ऐसी शिक्षा जो रोजगार दिलायें, कौशल निर्माण को बढ़ावा दे विशेष रूप से बालिकाओं को प्रदान करनी चाहिये, यही बालिकाएँ ''भविष्य में सशक्त होगी न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, कौशल ज्ञान पर महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार है सरकार बड़े स्तर पर कौशल विकास को प्रोत्साहन रही है सरकार कई योजनाएं चला रही हैं जो सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है।

(१) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना

(२) राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

(३) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

(४) प्रधानमंत्री कौशन विस योजना

(५) उड़ान कार्यक्रम (कौशल विकास मंत्रालय)

(६) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम—जुलाई १५, २०

(७) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

(८) कौशल भारत — जुलाई १५, २०१५

(९) सीखों और कमाओं, अल्पसंख्यक हेतु स्कीम २०

**युवा — कौशल विकास कार्यक्रम (दिल्ली पुलिस**

सरकार के कार्यक्रम जैसे 'मेक इन इंडिया', 'स्टैंड अप इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया उद्देश्य रोजगार सृजन करके कौशल विकास ताकि महिला सशक्त हो और देश के विकास में अपना योगदान दे सके सरकारी तथा कार्यक्रम जैसे 'मेक इन इंडिया 'आदि में उद्यमियों की भागीदारी बहुत संतोशजनक रही अपनी तरह से बहुत योजनाएँ चला रही है जो.. को सशक्त बना रही है जो महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दे रही है।

**(१) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना**

यह कार्यक्रम बालिकायों के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से २२ जनवरी २०१५ से हरिया पानीपर से शुरू किया गया था।

इस कार्यक्रम का लोगों को लड़कियों के घटते निम्न लिंगानुपात के प्रति जागरूक करना है।

इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार लड़को और लड़कियों के बीच भेदभाव को रोकना है, साथ ही प्रत्येक लड़की की सुरक्षा, शिक्षा और स्वीकृति सुनिश्चित करना है।

**२. उज्जवला योजना**

यह योजना १ मई २०१६ को मंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेगा योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनके स्वास्थ की रक्षा करना है।

**३. महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहायता (ैज्म्च्)**

यह योजना १९८६—८७ में फेन के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना महिला विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाई जा रही है। का उद्देश्य महिलाओं में कौशल विकास कर उन्हें कृ बनाना है ताकि वे स्वरोजगार या उद्यमी बनने का कौशल प्राप्त कर सके। इस योजना का मुख्य लक्ष्य १६ वर्श या उससे अधिक उम्र की लड़कियों/महिलाओं से कौशल विकास करना है।

**४. पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण—**

पंचायती राज संस्थाओं मे महिला आरक्षण इस बात का एक बड़ा उदाहरण प्रदान करता है कि आरक्षण का उपयोग महिला सशक्तिकरण के लिये एक उपकरण के रूप में किया जा सकता हैं। इससे संसद और राज्य विधानमंडलों में महिला सदस्यों की

संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में लोकसभा में महिलाएं केवल ११.६ प्रतिशत और राज्यसभा में ११ प्रतिशत है।

बिहार, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पंचायती राज संस्थानों (पीआर आई) में महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण प्रदान करते हैं।

**५. महिला हेल्पलाइन योजना —**

अगर कोई महिला मुसीबत में है तो इस नम्बर पर कॉल करें, यह पूरे देश में काम करता है। सरकार ने महिलाओं की मदद के लिये नंबर जारी किये है सरकार ने महिलाओं को को इस नम्बर पर कॉल करके तुरंत मदद करने का सुविधा दी हैं। महिला हेल्प—लाइन नम्बर १०९१/१०९० पूरे देश के लिये है। इसके अलावा महिलाये राष्ट्रीय महिला आयोग (New) में ०१११—२३२१९७५ पर कॉल कर सकती हैं। राज्यों ने भी अपने स्तर पर हेल्प लाइन नम्बर जारी किये हैं।

**निष्कर्ष :**

आज जिस तरह से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं मे, सुधार है, उसे देखते हुये भारत के निकट भविश्य में महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान देने की जरूरत है। यह बहुत जरूरी है। हम महिलाओं के खिलाफ अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक पूर्ण, कानूनी प्रावधानों को भी बदलें। भले कारण हो आज के समाज में कई भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन गई है फिर भी कई महिलाओं को सहायता और समर्थन की आवश्यकता है। महिला शक्तिकरण का यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की सामाजिक—आर्थिक प्रगति पर उसकी महिलाओं की सामाजिक— आर्थिक प्रगति मध्य पर निर्भर करती हैं। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के लिये लडने मे मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि तुलना करें तो भारतीय महिलाओं की भागीदारी और कौशल विकास के नये कार्यक्रम, सरकार तथा निजी क्षेत्र की कौशल निर्माण में भागीदारी, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम, वित्तीय समावेश आदि। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक योगदान देंगे। कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ३५ कृ. महिलाओं को कौशल प्रदान किया गया जो वर्तमान में नए भारत के निर्माण में सकारात्मक योगदान दे रही है।

**संदर्भ—**

(i) ७ March २०२२ सम्पादकीय (इन्वेस्ट इंडिया आउटलुक) द्वारा रणनीतिक निवेश अनुसंधान इकाई (SIRU)

(ii) anubooks.com https://anubesks.com

(iii) https://www.eduzenejournal.com

(iv) https://www.investindia.gov.in

(v) indian Council of Agricultural Research

(vi) शोध मंथन, २०१८ ISSN (P) Journal No- ४०९०

(vii) ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल लेंडर रिपोर्ट २०२१

❑❑❑

15

# कुशल कार्यबल तैयार करना : नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका

**डॉ. ज्योति मेहता**
(प्राध्यापक — समाजशास्त्र)
शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या महाविद्यालय
किला भवन, इंदौर

***********

**सार :—**

भारत में नई शिक्षा नीति २०२० (एन.ई.पी.) ने देश में कोशल भिन्नता को दूर करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वी.ई.टी) को महत्व दिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य (एन.ई.पी. में वी.ई.टी.) के अनुप्रयोग और कुशल कार्यबल बनाने की क्षमता का अध्ययन करना है। इसकी शुरूआत एन.ई.पी. का एक अध्ययन और रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के साधन के रूप में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने से होती हैं। फिर एन.ई.पी. में वी.ई.टी. को लागू करने में आने वाली समस्याओं और अवसरों को जांच करता है जिसमें पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क तैयार करना शिक्षक प्रशिक्षण और उद्योगों के सहयोग से संबंधित मुद्दे शामिल है। व्यावसायिक शिक्षा पैदा करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालता है। भारत और अन्य देशों में सफल व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। अंत मे एन.ई. पी. में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने के नीतिगत विषयों पर चर्चा किया गया है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचे में अधिक निवेश की आवश्यकता, व्यवस्थित उद्योग और अकादमिक संबंध शामिल है।

**शब्दकुंजी :—** व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण (वी.ई.टी., एन.ई.पी.)

**परिचय :—**

कुछ समय से भारत में निर्माण क्षेत्र उद्योग, कारखाना, भवन निर्माण से लेकर स्वास्थ्य देखभाल तथा विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता महसूस किया जा रहा है। इस मांग के बावजूद देश में महत्वपूर्ण कौशल अंतर दृष्टिगोचर होता है, देश की बड़ी आबादी के एक हिस्से में कौशल एवं दक्षता का अभाव है। इस समस्या के समाधान के रूप में भारत सरकार में व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को महसूस किया है। २०२० में सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की जिसका उद्देश्य भारत में व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नई शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता पर जोर देती है। इसे देश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए प्रमुख घटक के रूप में मान्यता देती है। कौशल आधारित विचारधारा और बदलाव की कल्पना करता है। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता इस अध्ययन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों मे महत्वपूर्ण महत्व एवं स्थान का पता लगाना है।

**एक कुशल श्रमिक बल :—**

नई शिक्षा नीति और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर प्रदान करता है। नवीन नीति की आधारभूत आवश्यकता के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करने में समस्या एवं अवसरों पर प्रकाश डालता है। भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं मुख्य अध्ययन विषय में विद्यार्थियों की संख्या में अंतर एवं व्यावसायिक शिक्षा की महत्व पर प्रकाश डालता है। इसमें पाठ्यक्रम तैयार करना शिक्षण प्रशिक्षण एवं उद्योगों से संबंध सहयोग से संबंधित विषय पर विचार विमर्श किया गया है। जिसमें व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अधिक निवेश एवं उद्योगों के बीच मजबूत संबंधों की आवश्यकता महसूस किया गया है।

**नई शिक्षा नीति :—**

व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए नई शिक्षा नीति २०२० शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, जिसमें परम्परागत शिक्षा प्रणाली को बदलने में अधिक जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति

व्यावसायिक विकास और रोजगार सश्जन के मुख्य घटक के रूप में मान्यता देती है। ५/१५ नई शिक्षा नीति एव अधिक समग्र केन्द्र केन्द्रित शिक्षा प्रणाली में बदलाव की कल्पना करता है। जहाँ छात्रों के व्यावसायिक शिक्षा के साथ अन्य विषयों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इस नीति के अनुसार सभी छात्रों का झुकाव अकादमिक शिक्षा की तर नहीं है। नौकरी, उद्योग कारखानों में तकनीकी कौशल और व्यावहारिक अनुभव की मांग बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रों में रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, और व्यावसायिक शिक्षा को इस लक्ष्य प्राप्ति के पूरक के रूप में देखा जा रहा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक नौकरी उन्मुख कौशल प्रदान करना है जो छात्रों को रोजगार दिलाने या अपना उद्यम प्रारंभ करने में मदद की। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देकर कुशल और अकुशल के बीच अंतर को घटाने का प्रयास है। यह अपेक्षा की जाती है कि नियोक्ता द्वारा जिस कौशल और दक्षता की मांग की जाती है, छात्र उसमें परांगत हो। नई शिक्षा नीति में कहा गया है, व्यावसायिक शिक्षा को द्वितीय श्रेणी की परम्परागत धारणा को बदलने की जरूरत है। मुख्य धारा के विषय एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच समानता बनाने के साथ—साथ व्यासायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देती है। नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिखा से जुड़े सामाजिक मिथक को दूर कर नये आयामों के तौर पर विकसित करना है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एन.ई.पी. भारत में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव करता है। मुख्य प्रस्तावों में से एक व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों में जोड़कर सभी छात्रों के लिए सुगम बनाना नीति का प्रमुख लक्ष्य एक राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ) बनाना है। जो व्यावसायिक कौशल को पहचानने के लिए एक मानक प्रदान करेगा। इसके अलावा नीति में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी. आई.एस.), पॉलिटेक्निक और कौशल विकास केन्द्रों सहित व्यवसायिक शिक्षा केन्द्रों का एक समूह बनाने का प्रस्ताव है। संस्थानों को उद्योगों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। साथ ही नए पाठ्यक्रमों की जरूरत अनुसार एन.ई.पी. व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षण प्रशिक्षण के महत्व के पहचानता है। एन. ई.पी. का जोर भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव कर कुशल कार्यबल तैयार करना है, जो भारत की आर्थिक वश्द्धि ओर विकास में साथ दे सके। व्यावसायिक शिक्षा पर एन.ई.पी. का जोर अधिक समावेशी और व्यावहारिक शिक्षा की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

**नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने में चुनौतियाँ और अवसर :—**

भारत में नई शिक्षा नीति २०२० व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को पहचानती है और पारंपरिक शैक्षणिक उन्मुख शिक्षा के व्यवहार्य विकल्प के रूप में बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। लेकिन कई समस्याएँ है जिनका समाधान व्यावसायिक शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रमुख समस्याओं में से एक है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का अभाव। भारत के स्कूल, कॉलेज विश्व विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु आवश्यक उपकरणों एवं संसाधनों का अभाव है। योग्य शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की कमी है। जो उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा दे सके। महत्वपूर्ण समस्या यह भी है कि व्यावसायिक शिक्षा को 'दोयम दर्जे' के विकल्प के रूप में समझना है। इन समस्त समस्याओं के चलते व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश कम हो गया है। यह व्यावसायिक शिक्षा के लाभों की जानकारी के अभाव के कारण और अधिक बढ़ गया है। जिसमें छात्रों द्वारा अकादमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। एन. ई.पी. के लक्ष्यों की सफलता के लिए शैक्षणिक उन्मुख शिक्षा का विकल्प महत्वपूर्ण है। एन.ई.पी. का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य ध ारा के पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए। इसे लागू करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। जिसमें पाठ्यक्रम विकास शिक्षण प्रशिक्षण एवं आधारभूत ढांचा का विकास शामिल है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अकादमिक शिक्षा केन्द्रित है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता

फेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ) बनाने का एन.ई.पी. का सकारात्मक कदम है। एन.ई.क्यू.एफ. को लागू करने के लिए उद्योग, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों सरकारी एजेंसी सहित अन्य हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है। एन.ई.क्यू.एफ. का प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण समस्यसा है। इन समाधान के बावजूद व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के कई अवसर है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यावासयिक शिक्षा की बढ़ती मांग व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। व्यावसायिक शिक्षा पर एन. ई.पी. का जोर इसे मुख्य धारा के पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर सभी छात्रों को अवसर प्रदान करना है। तथा व्यावसायिक शिक्षा के व्यावहारिक प्रशिक्षण शिक्षा तक पहुच प्रदान कर सकता है। छात्रों को दुनिया के किसी भी कोने उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच बनाने का अवसर प्रदान करना इससे सहपाठियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है, जिससे सहयोगात्मक सीखने का अनुभव बढ़ता है। प्रोद्योगिकी का उपयोग छात्रों को गहनता एवं अनुभव के साथ सीखने का अवसर प्रदान करता है। जिससे सुरक्षित एवं नियंत्रित वातावरण में अपने कौशलों को विकसित करने का अवसर मिलता है।

छात्रों को संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच बनाने में सहयोग प्रदान करता है। जो पारंपरिक कक्षाओं में यह नहीं था। उदाहरण छात्र विडियों, ऑनलाईन संसाधनों का पहुचं सकते है। जटिल अवधारणाओं के प्रति समझ बढ़ा सकता है। व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा पारम्परिक शिक्षा से अधिक सस्ती हो सकती है। व्यवसायिक शिक्षा और उद्योग के जरूरतों के बीच अंतर को घटाने का कार्य करता है। पाठ्यक्रम में विशिष्ट पाठ्यक्रमों प्रौद्योगिकियों और सॉफ्टवेयर को शामिल करके छात्र विभिन्न कौशलों को विकसित कर सकते है। जिनकी वर्तमान में जरूतर है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के निर्माण एवं विकास में विभिन्न चुनौतियाँ है, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या डिजिटल विभाजन है। जो उन लोगों के बीच अंतर को संदर्भित करता है, जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नही है, विकासशील देशों में यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

एन.एस.डी.सी. एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है जिसकी स्थापना २००९ में किया गया था, जिसका उद्देय कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ कुशल कार्यबल तैयार करना है। एन.सी.डी.सी. ६०० से अधिक प्रशिक्षण भागीदारों के साथ २० मिलन से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। इसकी सफलता का मुख्य कारण है पहले यह नियोक्ताओं और उद्योगों से सझेदारी किया है। इसके द्वारा सिखाए गय कौशलों की बाजार में मांग है। इसके लिए एनएसडीसी कठोर प्रणाली और नियमों के साथ प्रशिक्षण दिया है जो सभी मानकों को पूरा करता है। सार्वभैमिकता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। जो ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो देश भर में सुलभ है। इसके अतिरिक्त एक जर्मन दोहरी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम डी.वी.टी. प्रणाली है, जिसे दुनिया भर के कई देशों में लागू किया है। डी.वी.टी. प्रणाली कक्षा में सीखने की नौकरी प्रशिक्षण के साथ जोड़ती है। जो छात्रों को वास्तविक एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती है। डीवीटी की सफलता का मुख्य कारण उद्योगों एवं नियोक्ताओं की साझेदारी है। इस प्रणाली को उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श से डिजाइन किया गया है। इसके द्वारा सिखाए गये कौशलों की बाजार में मांग है, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ ले पाते है। उपरोक्त सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करके व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम छात्रों को सफल होने और अर्थव्यवस्था की वशद्धि एवं विकास में योगदान के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान कर सके। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने के निहितार्थ एन.ई.पी. २०२० भारत में लागू किया गया जो छात्रों को बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने पर जोर प्रदान करता है। छात्रों को २१वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। एनईपी का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में शामिल करना है। जिसका उद्देश्य छात्रों को वर्तमान आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्रदान करना है। एन.ई.पी. में व्यावसायिक

शिक्षा को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना है। दूसरा व्यापक पाठ्यक्रम तैयार की आवश्यकता है जो व्यावसायिक शिक्षा के अकादमिक शिक्षा के साथ जोड़ती है।

एन.ई.पी. एक लचीले पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर जोर देती है जो छात्रों को विषय चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो छात्रों के रूचियों के अनुरूप है। इसके लिए कौशल आधारित विचारधारा में बदलाव की आवश्यकता है। जो हाथों से सीखने एवं वास्तविक दुनिया के प्रयोग पर केन्द्रित हो। तीसरा एक कठोर नियम एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है इससे सुनिश्चित होगा कि प्रदान किए गये प्रशिक्षण आवश्यक मानकों को पूरा करना है और इसकी बाजार में आवश्यकता है। चौथा लचीलेपन के साथ सीखने का अवसर प्रदान करना जिससे प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सके।

एन.ई.पी. में सीखने के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रणाली पर अधिक जोर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था, मोबाईल एप्लिकेशन और अन्य डिजिटल उपकरणों के विकास की आवश्यकता है जो छात्रों तक सुलभ पहुंच को आसान करती है। पांचवा नीति नियोजन है छात्रों को मार्गदर्शन एवं परामर्श की आवश्यकता है, जिसमें वे अपना भविष्य निर्माण कर सके।

**निष्कर्ष :—**

निष्कर्ष कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने के नीतिगत निहितार्थ व्यापक और जटिल है। उन्हें एक बहुयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधनों एक व्यापक पाठ्यक्रमों कठोर मान्यता प्राप्त निगरानी प्रणाली प्रौद्योगिकी का उपयोग और कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की आवश्यकता पर जोर देती है। इन नीतियों को लागू करके देर यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके छात्र नौकरी बाजार उद्योग में सफल होने के लिए और अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं योग्यताओं से युक्त है।

**संदर्भ :—**

1. www. Education.gov.in/li/nep 2020
2. www. Nsdcindia.org
3. nevtmis.gov.inpages/home.aspx
4. www.worldbank.org/en/country/Indi/publication/India -skills-reprt-2019-skilling-for-a-s-trillion-economy
5. www.workdbank.org/en/news/factor/2021/01/18/vacational-education-and-training-in-india-chalanges/oppertunites.
6. www. Ccs.in
7. nios.ac.in
8. nsda.gov.in
9. www.cii.in/policy advacacy.aspx
10. www.nisd.org in

❑❑❑

16

# रोजगारोन्मुखी शिक्षा और कौशल विकास

**डॉ. शैल श्रीवास्तव**
सह प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
शा.म.ल.बा. कन्या महाविद्यालय, इन्दौर

***********

कोई भी सभ्य समाज शिक्षा के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसके लिये वह अपनी आवश्यकता अनुरूप ही शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में शिक्षा का उद्देश्य लोगों की आर्थिक स्थिति एवं उनके जीवन स्तर में सुधार कर समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना भी है। देश की तथा समाज की उन्नति के लिये यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना आवश्यक है। न केवल पुरूषों को बल्कि महिलाओं को भी व्यवसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय हित के संवर्धन का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

२००८ की वैश्विक मंदी, जिसने न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया बल्कि मानव संबंधी एक नयी अवधारणा को जन्म दिया और जो नई अवधारणा निकल कर आयी वह थी ''रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं कौशल विकास।'' अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की २००९–१० की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मंदी के फलस्वरूप करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, या पद अवनति का शिकार होना पड़ा था, वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा। और इसका मुख्य आधार माना गया श्लोगों में कौशल की कमी। अर्थात् कुछ विशेष दक्षताओं का अभाव होना। इसी कमी को दूर करने के लिये विभिन्न देशों ने अपने यहां प्रचलित शिक्षा–नीति में परिवर्तन के संकेत दिये तथा नई शिक्षा नीति अपनाने का कार्य प्रारंभ किया। विश्व बैंक ने भी विश्व के विभिन्न देशों से प्रायोगिक एवं रोजगारपटक विषयों को सम्मिलित करते हुए रोजगार आधारित शिक्षा प्रणाली स्थापित करने की अपील की। भारत में भी योजना आयोग की जगह स्थापित 'नीति आयोग' ने भी शिक्षा प्रणाली में सुधारों की भूमिका को अहम माना।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में भारत में जुलाई २०२० में मंजूर की गयी नवीन शिक्षा नीति इस दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट पर आधारित है। तत्कालीन केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर द्वारा २९ जुलाई २०२० को प्रस्तुत की गयी। विश्व की पूर्वगामी स्थितियों को दशष्टिगत रखते हुए इस नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जबरदस्त बदलाव किये गये ताकि विद्यार्थियों को रोजगारपटक और कौशल आधरित शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके और विश्व पटल पर भारत को ज्ञान की महाशिक्त के रूप में स्थापित किया जा सके। इस नयी शिक्षा प्रणालीस का उद्देश्य सभी स्तरों पर छात्रों के लिये आवश्यक कौशल, आलोचनात्मक सोच को प्राथमिकता देना है।

**कौशल विकास :–**

कौशल या दक्षता, या निगुणता या कला का कोई ऐसा मानवीय गुण जो कि उसको अन्य मनुष्यों से अलग या बेहतर साबित करता है, उस व्यक्ति का कौशल कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकागण से भी मनुष्य के ऐसे गुणों का विकास करना जो विशेष काल या परिस्थितियों में अनुभव व प्रशिखण के द्वारा उस व्यक्ति को अन्य से बेहतर साबित करे, कौशल कहलाता है। नेशनल काउन्सिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च २०१८ की रिपोर्ट के अनुसार कौशल तीन प्रकार का होता है। पहला संज्ञात्मक कौशल जो बुनियादी कौशल है। व्यवहारिक ज्ञान, के समाधान की योग्यता तथा रचनात्मकता शामिल है। दूसरी 'तकनीकी और व्यवसायिक कौशल'। जिसमें किसी भी व्यवसाय में उपकरणों और विधियों का उपयग करके विशिष्ट कार्यो को करने की योगयता। और तृतीय स्वप्रबंधन कौशल नवीन शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में कौशल विकास के लिये व्यवसायिक पाठ्यक्रम समावेशित किये गये हैं।

यह पाठ्यक्रम किताबों (Theory) की जगह प्रायोगिक सिद्धांतों से संबंधित है और किताबें (Theory) गौड़ पद का काम करती है। कम्प्यूटर डिप्लोमा, व्यक्तित्व विकास, योग, कटिंग, कुकिंग, फार्मिंग तथा अन्य बहुतसी विशेष कलायें इसमें सम्मिलित की गयी है।

**कौशल विकास और रोजगार :—**

गरीबी, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे भारत में इन समस्याओं के समाधान के लिये ''प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना'' जुलाई २०१५ मं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लांच की गई। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम सेभी जाना जाता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में यह एक महती योजना है। कम पढ़े लिखे या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके लोगों को रोजगार के लिये प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नि:शुल्क, अल्पावधि कौशल, प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिये यह एक सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। भारतीय युवाओं को उनकी रूचि के क्षेत्रों में उनके कौशल का विकास करना तथा विकासोपरान्त उनहें आजीविका के लिये रोजगार उपलब्ध कराने में यह योजना सकारात्मक कार्य कर रही है। इसमें ४० विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में युवाओं को ापससमक किया जाता है। स्वास्थ्य वित्त, निर्माण कार्य, सिलाई, तथा अन्य कई क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। इसके लिये राज्यों में अलग—अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये है। प्रशिक्षणोंपरान्त युवाओं के लिये स्टाइपैंड आदि की भी व्यवस्था की गयी है। इस योजना से जुड़ने के लिये सरकार ने कई टेलीकॉम कंपनियों को इस कार्य के लिये अपने साथ जोड़ रखा है और यह कंपनियां मैसेज के द्वारा सभी को योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस योजना के लिये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया है। राष्ट्रीय कौशल नीति के अंतर्गत यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में २००९ में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की गयी थी। अन्य विभिन्न मंत्रालयों में चल रही बहुत सारी कौशल विकास सम्बंधी योजनाओं में कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत लाकर सरकार ने बिखराव को कम किया है।

भारत एक ऐसा देश है जहां कुशल कार्यबल की बहुत कमी है। यहां शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् रोजगार न मिलने के कारण बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बडी हैं एक और कंपनियां कुशल कार्यबल की कमी का सामना कर रही है वहीं शिक्षित बेरोजगार की संख्या में बढ़ौतरी होती जा रही है। ऐसे में युवाओं की मानिकस क्षमता और उनकी रूचि को ध्यान में रखते हुए उनमें किसी न किसी कौशल का विकास करना आवश्यक है। सरकारी नौकरी सभी के लिये संभव नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे में कोई प्रशिक्षित कुशल युवा अपनी कला के बल पर समाज में जीविकोपार्जन कर देश हित में अपना सहयोग दे सकता है।

**चुनौतियाँ —**

भारत में कम पढ़े लिखे, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है और शिक्षा को भी रोजगारोन्मुखी बनाने के लिये नवीन शिक्षा नीति भी लागू कर दी गयी है, लेकिन व्यववहारिकता में देखने पर स्थिति संतोषजनक ही लगती है न कि बहुत अच्छी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नि:संदेह एक सरकारी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। लोगों के कौशल में वश्द्धि कर उसे निखारना इसका मकसद है। इस तरह से मनुष्य को एक संसाधन के रूप में माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदीजी का यह कथन कि यदि चीन दुनिया की फेक्ट्री बन सकता है तो भारत विश्व को मानव संसाधन प्रदान करने वाली क्यों नहीं बन सकता। एक संभावना जो उभर कर आ रही है, वह यह कि आगामी वर्षों में जहां पूरे विश्व में करोड़ो नौकरियों के लिये मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, वहीं भारत में बेरोजगारी बढने के आसार भी दिखाई दे रहे है। अगर पाश्चात्य देश भारत से मानव संसाधन लेना भी चाहेंगे तो अति उत्तम दक्षता वाले अपने क्षेत्र में अत्यंत निपुन लोगोंको ही प्राथमिकता देंगे ऐसे में अपेक्षाकश्त कम कुशल लोगों का क्या होगा ? आज के भौतिकवादी युग में भारत के ग्रामीण युवा भी चकाचौंध वाली दुनिया के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तथा

ऐसे ही क्षेत्र में प्रशिक्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं जिसका दायरा शहरों, विशेषकर महानगरों तक सीमित है। यदि गांव से युवाओं का पलायन जारी रहा तो देश में अस्थिरता और असंतुल्य की स्थिति बन सकती है।

इस संभवना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि, जिस क्षेत्र में युवाओं ने आज दक्षता हासिल की है और उसकी आज उपयोगिता है, लेकिन आने वाले वर्षों में भी क्या वह कला उतनी उपयोगी बनी रहेगी? आज जिस्तेजी से तकनीक का विकास हो रहा है उसमे नित नए नए अविष्कार हो रहे है। कुछ दिनों पहले वाली उपयोगी तकनीक का स्थान नयी तकनीक ले लेती है ऐसे में कुशल युवाओं का कुछ वर्षों बाद भी क्या भिवष्य सुरक्षित रह सकता है? इसलिए कौशल विकास के साथ साथ उच्च शिक्षा की भी आवश्यकता है, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना में कौशल प्राप्त कर चुके लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों को शत प्रतिशत प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे है।

नवीन शिक्षा निति के द्वारा शिक्षा कोरोजगार परक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन व्यावहारिकता ये है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए प्रक्शिक्षित शिक्षिको का अभाव है द्य यद्यायापी विभिन्न प्रक्षिक्षण कार्यकर्मो को आयोजित कर सरकार इस दिशा में काम कर रही है लेकिन इसका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से नही हो पा रहा है। अत: निजी सन्सथानो, संघठनो तथा अंतराष्ट्रिया मंचो के माध्यम से स्तरीय प्रक्शिक्षित शिक्षिको का वर्ग तैयार करना होगा। अतिरिक्त संसाधनों कि कमी भी इस निति कि सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए यद्यायापी बोहत से जागरूकता अभियान तथा अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी अधिकाँश ग्राह्मिन युवा इसकी जानकारी से अनभिज्ञ हैं।

**निष्कर्ष**

प्रत्येक कार्य का, निति का अच्छा और बुरा पहलु होता है। युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लाइ गयी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निसंदेह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ठोस कदम है और इस्से करोरो लोग स्किल्ड भी हुए हैं लेकिन किसी भी योजना कि सफलता में दोनों पक्षों कि सक्रीय भागीदारी अपेक्षित होती है। सरकार ने योजना लांच कि लेकिन अधिकाँश युवा कुछ करना ही नही चाहते। योजनाओं का सही उपयोग न होने के कारण उसकी कमियां स्वत: ही दिखने लगती है। सरकार के एकतरफा प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते। योजना की सफलता उसके सिद्धांतों व नियमों में नहीं बल्कि उसके सही क्रियान्वयन में है, उसकी पारदर्शिता में है।

शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया है। शिक्षा को रोजगार के संबंध में देखा जाए तो कई भारतीयों ने अपनी बुद्धि का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है। स्वास्थ्य, विज्ञान, औषधि तथा अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है। फिर भी इस वास्तविकता से इंकार नहीं किया जा सकता कि, भारत में रोजगार परक एवं उच्च शिक्षा की स्थिति पिछड़ी अवस्था में ही है। नवीन शिक्षा नीति इस कमी को दूर करने की शिक्षा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता या असफलता के इस प्रश्न का उत्तर भविष्य ही दे पाएगा। भारत में कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार की समस्या बनी रहती है। ऐसे लोगों को स्वरोजगार आधारित शिक्षा देकर रोजगार से जोड़ने में सुफलता प्राप्त की जा सकती है। रोजगार परक शिक्षा भारत की राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अत: कहा जा सकता है कि, कौशल विकास के साथ—साथ रोजगार परक उच्च शिक्षा की आवश्यकता, अनिवार्यता होनी चाहिये। मेक— इन— इंडिया और कौशल विकास की राष्ट्रीय योजनाओं की सफलता तभी संभव होगी जब कुशल भारतीय युवाओं के लिये देश के अंदर और बाहर एक इज्जतदार जीवन जीन के लिये सुनिश्चत हो सके

**संदर्भ** :—

1- https://hi.m.wekipediaorgwiki.
2- Amar Ujala-https://www.ama rujala .com/digital.
3- JSLPS SARKARI YOJNA
4- https://nbsslup.in/national-education -policy-2023/
5-https://hindi.nvshq.org/pradhan mantri-kaushal-vikas-yojana/
6- https://www.livehindustan.com/news/ guestoco/umm/article1.story-487099.amp.html.

17

# महिला सशक्तिकरण और कोशल विकास

**आयशा ताहैरा खान**
सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान
शा. महारानी लक्ष्मी बाई कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, किला भवन, इंदौर

***********

**संक्षिप्तिका :**

किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओ की भागीदारी प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। प. जवाहरलाल नेहरू ने भी कहाँ है कि ”किसी भी देश की स्थिति उस देश कि महिला को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है’’। अत: हम कह सकते है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए महिला सशक्तिकरण का महत्व नकारा नही जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिला को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं अन्य स्तर पर मजबूत बनाये जाने का प्रयास किया जाता है, जिससे महिलाएं सशक्त होकर अपने स्वयं के फैसले ले सके एवं स्वतंत्र रूप से जीवन को उन्नति कि ओर अग्रसर कर सकें। प्राचीन समय सें तुलना करने पर पाया गया कि प्राचीन काल मे महिलाओ की शिक्षा, चिंताजनक थी किन्तु वर्तमान समय में शिक्षा के प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ रहा है जो की प्रशंसनीय है। महिला सशक्तिकरण के साथ—साथ महिलाओ की कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना आज के समय की जरूरी आवश्यकता बन गई है। प्रस्तुत शोध पत्र में कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया हैं

**कुंजी शब्द :—** महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास

**प्रस्तावना :**

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता:। अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। उक्त कथन से यहाँ आशय महिलाओ को हर स्तर एवं हर क्षेत्र मे सम्मान देने से है ताकि वह उभरे और परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास मे अपना अधिक से अधिक योगदान दें सकें।

स्वामी विवेकानंद का कथन है कि ‘‘दुनिया की तरक्की तब तक संभव नही जब तक कि महिलाओ की स्थिति नही सुधरती। एक पंख की मदद से कोई चिड़िया उड़ नहीं सकती’’। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओ की स्थिति सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से एक समान नही रही हैं। पूर्व वैदिक काल की महिलाएं बहुत शिक्षित थीं इसके प्रमाण हमे प्राचीन ग्रंथो में मैत्रयी जैसी महिला संतो के रूप मे देखने को मिलते है। वैदिक काल के पश्चात से धीरे दृ धीरे महिलाओ की स्थिति मे गिरावट आती गई। गुप्तकाल के दौरान महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा, बदतर देखी गई। मध्यकाल के दौरान महिलाये पर्दा प्रथा व बाल विवाह जैसी कुरितियो का सामना करना पड़ा। महिलाओं के शिक्षा के अधिकार को धिरे धिरे छिना गया और महिलाएं अज्ञानता के अंधेरे में घिरती चली गई। ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा हेतू प्रयास तो किये गए लेकिन पुरुष शिक्षा के लिए किए गए। श्री एडमस ने उस समय की स्थिति की देखकर कहाँ था कि य समस्त स्थापित शिक्षण संख्याएं पुरुषों के फायदे के लिए बनी है, और महिला जगत अज्ञानता के अंधकार मे भटक रहा हैं। इसी दौरान महिलाओ की इस दर्दनाक स्थिति को देखकर कई समाज सुधारको ने महिला हित हेतू अपना योगदान दियाय जैसे घ्‍ राजाराम मोहनराय ने अपने सतत प्रयासो के द्वारा सति प्रथा समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सत्ता को विवश किया।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर के आंदोलनो के परिणामस्वरूपम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शर्तों मे सुधार किया गया।

१९१७—४७ तक महिला शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। आजादी के उपरान्त से ले कर वर्तमान में भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।

**कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण :.**

महिलाओं के विषय में बात की जाए तो कौशल विकास का अर्थ सिर्फ महिलाओ को रोजगार प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर उनके कार्य प्रदर्शन को बेहतर तथा उत्पादक बनाना हैं। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा वर्तमान मे महत्वपूर्ण है, यह महिलाओं को अपने अधिकारो के प्रति सजग बनाकर उन्हे सशक्त बनाता है तो वही कौशल विकास आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भता लाने मे एक महत्वपूर्ण माध्यम का काम करेगा । कौशल विकास द्वारा महिला सशक्तिकरण को ओर बेहतर तरीके किर्यान्वित किया जा सकता हैं। वर्तमान मे हमारे राष्ट्र मे लेंगिग असमानता एंव कार्यशक्ति मे महिलाओ की निम्न भागीदारी जैसी समस्याए विद्यमान है, और महिला कौशल विकास इस समस्या का समाधान अवश्य करेगा।

**कौशल विकास के विभिन्न क्षेत्र :**

राष्ट्र के विकास मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं का महत्व अवश्य रहा हैं। पहले वह घर के काम काज करके, बच्चों का पालन पोषण करके अपना समय व्यतित करती थी वर्तमान मे शिक्षा एव कौशल विकास के परिणाम स्वरूप वें घर एवं बाहर दोनो के कार्यो को कुशलता पूर्वक संभालने मे प्रयासरत हैं। महिलाओं के कौशल विकास हेतू उन्हें संचार कौशल, निर्णय शक्ति कौशल, समय प्रबंध, रचनात्मक कौशल, समस्या निवारण, कम्प्यूटर शिक्षा, प्रबंधन, लेखांकन, व्यव्हारिक शिक्षा, नेटवर्किंग एवं अन्य आवश्यक कौशल के ज्ञान की आवश्यकता है।

**कौशल विकास की समस्याये :**

कौशल विकास द्वारा जहां महिलाओ को आर्थिक रूप से विकसित एवं सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है वहीं इसके मार्ग में कई समस्याए है— सामाजिक, अर्थिक, राजनैतिक एवं प्रशिक्षण से सम्बंधित समस्याए।

**सुझाव :**

कौशल विकास के लाभ को महिलाओ तक पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक पहुचाने हेतू उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य—सेवाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, डिजिटल प्लेटफार्म, रोजगार के अवसरो मे वृद्धि इत्यादि सुविधाएं पहुंचाना आवश्यक है ,ताकि वे स्वतंत्र होकर कौशल विकास के पथ पर आगे अग्रसर होकर सशक्त बनें।

**सरकारी प्रयास एवं योजनाएँ —**

भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त — बनाने एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय— समय पर प्रयास किये गये. जैसे:

- ➢ राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन,
- ➢ कौशल भारत
- ➢ सीखो और कमाओ
- ➢ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना
- ➢ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- ➢ राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
- ➢ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- ➢ उड़ान कार्यक्रम
- ➢ स्किल इण्डिया
- ➢ स्काई इत्यादी।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री सीखो — कमाओ योजना २०२३ मे लांच की गई जिसमे युवाओ को कौशल प्रशिक्षण के साथ —साथ ८—१० हजार प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस प्रकार देश की सरकार कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतू आवश्यक कदम उठा रही है।

**निषकर्ष —**

उपरोक्त बिन्दूओ के आधार पर हम यह कह सकते है कि प्राचीन काल की तुलना में आधुनिक काल की महिलाओ की स्थिति मे सुधार आया है। महिलाएँ पहले से सशक्त बनी है और कौशल विकास द्वारा उन्हे प्रशिक्षत कर और आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर चल रहा हैं। अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम श्तुलना करे तो भारतीय महिलाओं की स्थिति अभी भी श्असंतोषजनक है। भारत सरकार द्वारा निरंतर इस दिशा मे प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप संतोषजनक परिणाम सामने आ रहे हैं।

**सन्दर्भ सूची :**

१. International Journal of Research- n-d-- https://edupediapublications-org/journals/index-php/IJR/

२. चन्द्रा, डॉ तूलिका. २०१८. ''कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण".शौध मंथन १२२—१२६

३. सिंह , एस. २०१६, कौशल विकास, दिल्लीरू अग्नि प्रकाशन

**18**

# जनजातीय समुदाय में कौशल विकास की आवश्यकता एवं महत्व

**पूजा जायसवाल**
सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग,
शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या स्ना. महाविद्यालय इंदौर

**********

**सारांश**

भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, परंपराओं, भाषाओं, जातियों और पंथों के लोग रहते हैं। भारत के लोकतांत्रिक देश में आदिवासी लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने वाले समूहों में से एक हैं। जनजातियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, संपर्क में शर्म और आर्थिक रूप से पिछड़ापन हैं। कुल मिलाकर, जनजातियाँ जंगल और मैदानों से लेकर पहाड़ियों तक विभिन्न भौगोलिक जलवायु और पारिस्थितिक स्थितियों में रह रही हैं और इस क्षेत्र में पहुंच की कमी है। यद्यपि उन्हें भारत में हाशिए पर या सबसे कमजोर आबादी के रूप में माना जाता है, उनकी जीवन शैली और परंपरा, संस्कृति को संरक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। आदिवासी समुदाय को ऊपर उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके कौशल का विकास बहुत जरूरी है। कौशल विकास किसी अर्थव्यवस्था के परिवर्तन और विकास के लिए प्रेरक शक्ति है। भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और अन्य कल्याण के साथ—साथ कई कौशल विकास योजनाएं भी शुरू की हैं अनुसूचित जनजाति (एसटी), भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग ८.६: है। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर और वंचित, एसटी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच शामिल है। हालाँकि, इन असमानताओं को दूर करने और कौशल विकास पहल के माध्यम से एसटी समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में, अनुसूचित जनजातियों के बीच कौशल विकास के महत्व को स्पष्ट करते हुए उनके कौशल विकास के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का विश्लेषण किया गया।

**१. प्रस्तावना—**

जनजातीय समूह ऐसा समूह है जिनके विकास हेतु विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है। इन जनजातियों की स्थिति निम्न होने के कारण शासन के समक्ष इन समूहों का विकास एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है । (लक्ष्मी और पॉल, २०१९) आजादी के बाद भारत सरकार ने जनजातियों को संविधान में शामिल किया और कल्याणकारी कदम उठाते हुए जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान आवंटित किये। भारत के राज्यों में जनजातीय समुदायों के मामले में ७.५ प्रतिशत एसटी आबादी सबसे अधिक पिछड़ी है। जनजातीय क्षेत्र जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों के ऊबड़—खाबड़ और दुर्गम पठारी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे विकासात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कठिनाइयाँ आती हैं। भारत, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इसमें विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हैं इसके क्षेत्र में विभिन्न आदिवासी आबादी का निवास करते हैं। वे अधिकांश अविकसित देशों में संगठित हुए और निवास करने लगे। साथ ही, वे समान जीवन शैली के साथ संस्कृति, परंपराओं, रीति—रिवाजों और विरासत में समृद्ध हैं। भारत की संपूर्ण जनजातीय आबादी दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित हैरू उत्तर पूर्वी राज्य और मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों के मैदानी और ऊंची भूमि। उत्तर पूर्वी और उच्च भूमि वाले राज्यों तथा मध्य मैदानी और दक्षिणी क्षेत्रों में ८० प्रतिशत जनजातियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जनजातियाँ गैर—आदिवासी आबादी के साथ सह—अस्तित्व में रहती हैं जबकि उत्तर पूर्वी जनजातियाँ आम तौर पर अलग—थलग समुदायों के साथ रहती हैं। २०११ की जनगणना के अनुसार जनजातियों (tribes of Madhya Pradesh) का

प्रतिशत मध्यप्रदेश में २१.१ : है। लगभग २४ जनजातियां यहां निवास करती हैं। इनकी उपजातियों को मिलाकर इनकी कुल संख्या ९० है। मध्यप्रदेश में लगभग १.५३ करोड़ जनसंख्या इन जनजातियों की है, जो अब भी भारत में सर्वाधिक है ।

## २. साहित्यों का पुनरवलोकन

कुमार पी (२०२१) ने भारत के तेलंगाना राज्य में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का वित्तीय और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया अध्ययन में पाया गया कि कौशल विकास कार्यक्रम जनजातियों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर रहे हैं। कौशल विकास योजनाओं का जनजातीय लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और उन्होंने संतोष व्यक्त किया है क्योंकि उनके जीवन में महत्वपूर्ण सामाजिक उन्नति हुई है। शेन और वेंकटरमन (२०००) ने कहा कि अध्ययन के माध्यम से आदिवासी सदस्यों के बीच पौधों से संबंधित ज्ञान (पीआरके) बढ़ाना स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पौधों और उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यावसायिक उद्यमों के लिए कम वित्तीय पूंजी और निचले स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। आस—पास के जिलों में ऐसे बाजारों की बहुतायत है जो ऐसे सामानों के लिए उपयुक्त हैं। यह जरूरी है कि शैक्षणिक संस्थान अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम डिजाइन करें ताकि छात्र प्रासंगिक तकनीकी और विपणन क्षमताएं हासिल कर सकें। साहू एवं अन्य (२०१९) ने अपने अध्ययन में जनजातीय युवाओं के रोजगार और आय पर वीवीटीसी द्वारा प्रदान किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को स्पष्ट किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वीईटी के प्रभावों का आकलन करने के साथ साथ रोजगार, आय, जीवन के लिए प्रशिक्षण, उपरोक्त पहलुओं पर ध्यान प्रशिक्षुओं की राय था। एक बड़ा मुद्दा जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या कौशल विकास प्रशिक्षण से उसके एसटी किशोर जीवन में कोई फर्क पड़ता है। उन्होंने बताया कि छात्रों को अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद कई समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को समझना जरूरी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रशिक्षण केंद्रों को यह आकलन करने में मदद करता है कि प्रशिक्षण और प्लेसमेंट व्यवस्था प्रशिक्षकों के लिए जीवन बदलने वाली है या नहीं। इसलिए, उन छात्रों के विचारों और अनुभवों पर विचार करना आवश्यक है जिनके लिए ये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन किए गए हैं। छात्र वीटीसी, बुनियादी ढांचे और मध्यस्थता प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपनी धारणाएं, शिकायतें और सुझाव साझा कर सकते हैं। पांडेय और नेमा, (२०१७) ने देश की युवा आबादी को दिए जाने वाले तकनीकी प्रशिक्षण में कौशल विकास कार्यक्रम और इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा की। उन्होंने पाया की कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आदिवासी उत्तरदाताओं को कौशल हासिल करने के साथ—साथ आदिवासी युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है। भारत के कौशल विकास कार्यक्रम ने जनजातीय युवाओं को स्टार्ट अप जैसी स्व—रोजगार गतिविधियों में प्रेरित किया है और उन्होंने दूसरों को भी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है।

## ३. शोध के उद्देश्य एवं प्राविधि —

अनुसूचित जनजाति समूहों में कौशल विकास का महत्व का अध्ययन करना प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही प्रस्तुत शोध पत्र जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

मध्यप्रदेश जनजातीय जनसँख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा जनजातीय निवास है प्रस्तुत शोध में द्वितीयक तथ्यों के आधार पर मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति समूह में कौशल विकास की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। शोध हेतु द्वितीयक तथ्य विभिन्न शोध पत्र, प्रकाशित—अप्रकाशित शोध, पुस्तक, शासकीय प्रतिवेदन आदि का प्रयोग किया गया है।

## ४. परिणाम—

मध्य प्रदेश में मुख्य समस्या औपचारिक

टीवीईटी प्रणाली की अपर्याप्त पहुंच और गुणवत्ता के कारण राज्य में निवेश वृद्धि का समर्थन करने के लिए शिक्षित और सीमित कुशल श्रमिकों के बीच नौकरी के लिए तैयार कौशल की कमी है। परियोजना का समग्र लक्ष्य राज्य की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) प्रणाली को आधुनिक और मजबूत करके मध्य प्रदेश में युवाओं और अन्य कामकाजी उम्र की आबादी के रोजगार के अवसरों में सुधार करना है। यह परियोजना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यवसाय—तैयार कौशल प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का विकास करेगी, मौजूदा आईटीआई को उद्योग—प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मॉडल संस्थानों में अपग्रेड करेगी, प्रशिक्षकों की योग्यता बढ़ाएगी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रासंगिकता में सुधार करेगी और क्षमता का निर्माण करेगी। राज्य की टीवीईटी प्रणाली का समर्थन करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां। परियोजना का दृष्टिकोण समावेशी होगा और युवाओं, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों के दूरस्थ और वंचित समूहों तक पहुंचेगा।

भारत की जनगणना, २०११ के अनुसार, राज्य की जनसंख्या लगभग ७३ मिलियन है, जिसमें ७२% ग्रामीण और २८% शहरी क्षेत्रों में रहते हैंय राज्य की लगभग ५२% जनसंख्या २५ वर्ष से कम आयु की है। राज्य की साक्षरता दर ६९% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर ७९%और महिलाओं की साक्षरता दर ६०% थीय और राज्य का लिंग अनुपात प्रति १,००० पुरुषों पर ९३१ महिलाएं था। अनुसूचित जातियों के लिए साक्षरता दर कम, ६६% और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत कम, ५१% है। कामकाजी उम्र की लगभग २३% आबादी (१५—५९ वर्ष की आयु) निरक्षर है, जबकि १४% ने केवल प्राथमिक शिक्षा पूरी की है और ११% ने डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, या स्नातक और उससे ऊपर की डिग्री हासिल की है। मध्य प्रदेश की ७३ मिलियन आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक या सामाजिक रूप से हाशिए पर है लगभग २३ मिलियन लोग (३२%) गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं१ और २००९—१० में, लगभग ६ मिलियन (८%) आदिवासी थे या दूरदराज के इलाकों में रहते थे। राष्ट्रिय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएसओ ६४वें दौर, २००७—२००८) के अनुसार, लगभग १० लाख लोग देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या १५३.१६ लाख (जनगणना २०११ के अनुसार) जो कि राज्घ्य की कुल जनसंख्या का २१.१० प्रतिशत है, इस प्रकार मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहाँ हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। लगभग २४ जनजातियां यहां निवास करती हैं। इनकी उपजातियों को मिलाकर इनकी कुल संख्या ९० है। जनजातीय लोग अपनी आजीविका के लिए बड़े पैमाने पर वनोपज एवं कृषि पर निर्भर हैं। किन्तु उपजाऊ कृषि क्षेत्र के आभाव से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं में कौशल विकास एक बड़ा विषय है जिससे जनजातीय विकास को गति दी जा सकती है।

**तालिका ०१ जनजाति बाहुल्य जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल प्रशिक्षित**

| जिले का नाम | जनजातीय जनसंख्या (प्रतिशत में) | साक्षरता (प्रतिशत में) | जनजातीय साक्षरता (प्रतिशत में) | PMKVY के अंतर्गत कुल पंजीकृत | प्रमाणपत्र प्राप्त | प्लेसमेंट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डिडोरी | 65 | 56 | 50 | 5533 | 4654 | 2935 |
| अलीराजपुर | 89 | 30 | 26 | 4367 | 2631 | 806 |
| खरगोन | 69 | 59 | 36 | 14879 | 10434 | 3261 |
| धार | 56 | 51 | 38 | 11783 | 8595 | 3953 |
| बडवानी | 69 | 41 | 31 | 4904 | 3186 | 689 |

स्त्रोत – PM

स्त्रोत _ PMKVY डैशबोर्ड

मध्यप्रदेश के जनजातीय बाहुल्य जिलों में जनजातीय जनसंख्यात्मक का विवरण तालिका क्र ०१ में दिया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है की जनजातीय साक्षरता का प्रतिशत एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से इन जिलों के जनजातीय युवाओं में कौशल विकास को गति मिली है साथ ही उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। जनजातीय बाहुल्य जिलों में इस प्रकार की कौशल विकास की योजनायें उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

**कौशल विकास की आवश्यकता**

अनुसूचित जनजाति समूहों में कौशल विकास की आवश्यकता को स्पष्ट करने हेतु निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

**आर्थिक सशक्तिकरण :**

एसटी के बीच कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्राथमिक कारण उनकी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाना है। ऐतिहासिक रूप से, कई एसटी समुदाय निर्वाह कृषि या कम वेतन वाली शारीरिक श्रम वाली नौकरियों पर निर्भर रहे हैं। कौशल विकास कार्यक्रम नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें उच्च वेतन वाली नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों तक पहुंचने में मदद मिलती है।

**समावेशी विकास :**

समावेशी विकास हासिल करने के लिए कौशल विकास आवश्यक है। प्रासंगिक कौशल प्रदान करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एसटी आर्थिक विकास प्रक्रिया में पीछे न रहें। इससे समाज के भीतर मौजूद आय और धन असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है।

**पारंपरिक शिल्प का संरक्षण :**

कई एसटी समुदायों के पास अद्वितीय और मूल्यवान पारंपरिक कौशल और शिल्प हैं, जैसे हथकरघा बुनाई, मिट्टी के बर्तन और स्वदेशी कृषि तकनीक। कौशल विकास पहल इन पारंपरिक कौशलों को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद कर सकती है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए उनकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

जनजातीय कौशल विकास की शासकीय योजनायें केंद्र एवं राज्य शासन ने जनजातीय समुदाय में कौशल विकास के महत्व को स्वीकारते हुए और इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनायें शुरू की हैं

**वन धन योजना:** इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक आदिवासी आजीविका को बढ़ावा देना और आदिवासी समुदायों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके और उन्हें उद्यमिता और वन उपज के मूल्यवर्धन में प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी आय को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसटी और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों की इन कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड): ट्राइफेड अपने उत्पादों का विपणन करके और उनके बीच उद्यमिता को बढ़ावा देकर आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए काम करता है।

जनजातीय उप—योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से टीएसएस): यह योजना आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास और आय—सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

**मुख्यमंत्री कौशल्या योजना**

कौशल्या योजना मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा वित्त—पोषित योजना है जिसके अंतर्गत रोजगार उन्मुखी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना है। महिलाओं की रोजगार अवसर में वृद्धि कर गैर—परम्परागत क्षेत्रों में कौशल प्रदान कर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

**चुनौतियाँ —**

कौशल विकास योजनाओं से अनुसूचित जनजति वर्ग की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है किन्तु फिर भी इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है

- ➢ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच: कई एसटी समुदायों में अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव है, जिससे उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेना मुश्किल हो जाता है।
- ➢ जागरूकता और भागीदारी: एसटी समुदायों के बीच कौशल विकास कार्यक्रमों और उनके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जाने चाहिए।
- ➢ अनुकूलन: कौशल विकास कार्यक्रमों को विभिन्न आदिवासी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं

और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। एक आकार—सभी के लिए फिट दृष्टिकोण प्रभावी नहीं हो सकता है।

➢ बुनियादी ढांचा: कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, विशेष रूप से दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में, पर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

**निष्कर्ष** :

निष्कर्षत:, अनुसूचित जनजातियों के बीच कौशल विकास उनके आर्थिक सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की पहल सही दिशा में एक कदम है, लेकिन मौजूदा कौशल अंतर को पाटने और एसटी समुदायों के उत्थान के लिए नागरिक समाज संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। चुनौतियों का समाधान करके और सहयोगात्मक ढंग से काम करके, हम अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी सदस्यों के लिए अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं।

**सन्दर्भ ग्रन्थ—**


- Kumar, P- V- 2021 Financial and Social Impact of Skill Development Programs for Empowerment of the Tribal Community in Telangana State India: An Empirical Study ? IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices; Hyderabad Vol- 20 Iss- 4 pp: 223&239-
- Brahmanandam T- & BosuBabu T- 2016- Educational status among the scheduled tribes: Issues and challenges- Journal of Politics and Governance 5,357&66-
- Joseph M- D- & Sridharan R- 2020- A Study on Skill Development Training & Self Employment Schemes Instigated By The Scheduled Tribes Development Department In Kerala- PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology 176 2683&2691-
- Sahu G- B- & Trivedi V- 2019- Skill development training and its impact on schedule tribe youths- Centre for Social Studies CSS Veer Narmad South Gujarat University Campus Udhna Magdalla Road Surat – 395007
- Tharu M- & Yadav R- G- 2018- Impact of skill development programmes on tribal communities: a case study of Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh- IMPACT: International Journal of Research in Humanities] Arts and Literature IMPACT: IJRHAL 69 237&250-
- Karade] J- Ed-2009- Development of scheduled castes and scheduled tribes in India- Cambridge Scholars Publishing-
- Website& https://www-pmkvyofficial-org/
- https://scdevelopmentmp-nic-in/
- https://dindori-nic-in/scheme/


❑❑❑

19

# प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

**डॉ. संगीता शर्मा**
सह प्राध्यापक समाजशास्त्र
शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई
स्नाकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर

**********

हमारे देश के प्रधानमंत्री युवाओं को स्वरोजगार की ओर बढ़ावा देने में बड़ा जोर दे रहे हैं। इसी कारण मोदी सरकार द्वारा बहुत साडी योजनाए शुरू की गयी है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है ।इस योजना को भारत सरकार ने जुलाई २०१५ को शुरू किया था। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वह बड़े कोर्स करके अपनी स्किल को निखार सके और नई हर व्यक्ति अपने ।र से दूर रहकर पढ़ाई कर सकता है। ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हमारे पास स्किल मौजूद होती है पर जब तक उसे निकालने की बात आती है तो हमारे सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत करके हम उसे निखार सकते हैं। जब स्किल मजबूत हो जाती है तो आसानी से रोजगार पा सकते हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उद्योग में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों और पूर्ण सीखने का अनुभव रखने वालों पर ध्यान केंद्रित करती है। इच्छुक व्यक्ति पात्रता मानदंड के आधार पर इस योजना के तहत सूचीबद्ध किसी भी पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं। पूर्व अनुभव या कौशल रखने वाले उम्मीदवार मूल्यांकन से गुजरते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त करते है।

इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहय्या करना है।जो कम पढ़े लिखे या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनसे कौशल को निखार कर उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना है। इस योजना में लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें इसके लिए युवाओं को ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा प्रदान की जाती है। भारत में रह रहे पढ़े—लिखे बेरोजगारों को नौकरी देना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में आता है।

इस योजना के अंतर्गत युवा कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन हार्डवेयर फूड प्रोसेसिंग फर्नीचर फिटिंग हैंडीक्राफ्ट जेम्स और ज्वेलरी समेत ४० क्षेत्र की ट्रेनिंग कोर्स फ्री में कर सकते हैं। इस योजना के तहत देश में ५००० ट्रेनिंग सेंटर्स पर ३२००० ट्रेनिंग पार्टनर्स के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस योजना से जुड़ने के लिए सरकार ने कई टेलीकॉम कंपनियों को इस कार्य के लिए अपने साथ जोड़ रखा है यह मोबाइल कंपनियां मैसेज के द्वारा इस योजना को सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है ।इस योजना के तहत मोबाइल कंपनियां योजना से जुड़े लोगों को मैसेज करके एक टोल फ्री नंबर देती है जिस पर कैंडिडेट को मिस्ड कॉल देना होता है। मिस्ड कॉल के तुरंत बाद एक नंबर से फोन आएगा जिसके बाद आप आईवीआर सुविधा से जुड़ पाएंगे इसके बाद कैंडिडेट को अपनी जानकारी निर्देशानुसार भेजनी होती है। कैंडिडेट द्वारा भेजी गई जानकारी कौशल विकास योजना के सिस्टम में सुरक्षित रख ली जाती है ।जानकारी मिलने के बाद आवेदन करता को उसी के क्षेत्र में यानि की उसके निवास स्थान के आसपास ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ दिया जाता है।

इस योजना में आवेदक की आयु १५ से ४५ वर्ष के बीच होनी चाहिए उम्मीदवार को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए उम्मीदवार जो बेरोजगार है। और उनके पास आएगा कोई साधन नहीं है ।वह आवेदन के पात्र होते हैं।

इस योजना में ३ महीने ६ महीने और १ साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस योजना में शॉर्ट टर्म

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318 | Vidyawarta® Peer-Reviewed International Journal | Special Issue | 085

ट्रेनिंग रिकांशस ऑफ प्रॉपर लर्निंग स्पेशल प्रोजेक्ट के जरिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके आधार कार्ड वोटर आईडी आईडी कार्ड बैंक अकाउंट की पासबुक मोबाइल नंबर पर स्पेशल प्रोजेक्ट के जरिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

सरकार द्वारा इसके लिए एक अलग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया है यही मंत्रालय इसके संपूर्ण प्रशिक्षण का अन्य योजना की मॉनिटरिंग करता है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को इनाम का प्रावधान भी रखा गया है जो लगभग ८००० है इससे बेरोजगारी कम होगी वह युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा वर्तमान में इस योजना के माध्यम से १.२५ करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में सूचित किया कि वर्ष २०२१—२२ के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ३ लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।अत: अंत में हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ सबको उठाना चाहिए इसकी जानकारी ऑनलाइन जाकर उनकी लिंक पर से भी प्राप्त की जा सकती है। किसी भी व्यवसाय में स्किल निखरना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ लें सकते हैं।

**संदर्भ ग्रंथ —**

➢ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवोलोप्मेंट
➢ विकिपीडिया
➢ राष्ट्रीय पोर्टल

❑❑❑

**20**

# पर्यटन और व्यवसाय

**डॉ. उशा महेबिया**
सहायक प्राध्यापक, इतिहास
शासकिय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय,
किला मैदान, इन्दौर

*********

**पर्यटन का इतिहास :—**

‘‘पर्यटन एक सामाजिक आन्दोलन है, जिससे आराम, मनोरंजन खेल एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओ की पूर्ति होती है’’

पर्यटन अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिये यात्रा करना या लाभ व्यापार के लिए यात्रा करना। प्राचीन काल से हो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक यात्रा के लिये। भार में तीर्थ स्थलो का अलग—अलग हिस्सो में होने से एक उद्धेश्य मनुष्य को अपने घर से बाहर की दुनिया घूमना समझने के अवसर प्रदान करना है। पर्यटन को चार अक्षरो के अर्थ में बांधा नही जा सकता है। साथ ही व्यक्तित्व विकास का मनो विज्ञान भी विद्यमान है। पर्यटन का इतिहास तना ही पुराना है जितना की सभ्यता और संस्कृति के विकास का इतिहास ह। तकनीकी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के पर्यटन को रोमांचिक बना दिया है। नये—नये स्थानो के प्रति मनुष्य की जिज्ञसा को रोमांचक बना दिया है। नये—नये स्थानो के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा अनुसंधान, तीर्थटन आदि कारणो में पर्यटन का विकास किया गया तथा मात्राओ को व्यवस्थित रूप प्रदान किया।

रोजगार, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यावरण व मनोरंजन से संबधित जानकारी की लालसा मे पर्यटन धारणा को एक नया आयाम दिया है। भारत में धार्मिक चार धार्मो जो कि चारो दिशाओ में स्थित है। जिसका अपना वैभवपूर्ण इतिहास है। जिसक कारण पर्यटन का विकास का अपना एक अलग ही समृद्ध इतिहास है। भारत में पर्यटन का इतिास आदिम मानव की दैनिक

जरूरतो से प्रारम्भ होता है। शिकार के लिए घुमना, रहने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आदि, गतिविधियो से जुडा है पर्यटन का इतिहास। धीर–धीरे मात्राओ में शैक्षणिक भ्रमण ने पर्यटन के क्षेत्र को विकसित कर से एक नया स्वरूप प्रदान किया।

मेहन जोदडो के उत्खनन से ऐसी सामग्रीया प्राप्त हुए है, जिसे यह लगता है कि उस समय लोग व्यापार व्यवसाय के लिए दूर देशो की यात्रा करते थे। इनके व्यापारिक संबंध अन्य देशो से थे।

ईसा से ४००० वर्ष पूर्व पर्यटन का सार्थक रूप उभर कर आया तब से, यात्रा के महत्व को समझा गया। मुद्रा के आगमन से व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ ही पर्यटन की शुरूआत हुई।

अधुनिक समय में पर्यटन मे हो रहे निरंतर विकास मे नये उद्योग का रूप दिया, उद्योग में युवाओ के लिये रोजगार के नये – नये क्षेत्र खोल दिये है। इससे बडी मात्रा में देश की विदेशी पर्यटन से धन प्राप्त होता है। और लोगो को रोजगार भी प्राप्त हेाता है। पर्यटन केवल घूमना भर नही बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधि है जो पारस्परिक सदभाव, भाईचारे की भावना को बढाती है। सभ्य है सामाजिक एकता को भी मजबूती प्रदान करती है।

पर्यटन के लिए भारत एक विस्तृत स्थान है । यह की विभिन्न संस्कृतिया और प्राकृतिक आर्कषण भ्रमण के मुख्य स्त्रोत है। हमारे रीति रिवाज, नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक धरोहर लोगो द्वारा पसंद किये जाते है। हिमाच्छादित पहाडिया, हिमखण्ड, उष्ण जलस्त्रोत, गुफाए, झीले, समुन्द्रतट, पर्वतमालाए, रोमांचक वन्य प्राणी मनभावन मस्स्थल आदि ५००० वर्ष पूर्व की हमारी ऐतिहासिक परम्परा आज भी विद्यमान है इसक साथ ही ऐतिहासिक इमारते जैसे सांची के स्तूप मध्यकालीन इमारते, कला व वास्तुकला के मंदिरे, मजिस्दो एवं गिरजाघरो में विविध कला के उदाहरण मिलते है।

वर्तमान में प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक और सहिष्णु, विरासत के लिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद पर्यटन एक उद्योग का रूप ले चुका है। विश्व के देशो मे भी इसके विकास के और बढावा देने के लिए परिवहन व संचार के विभागो व कार्यालयो की स्थापना कीं ट्रेवव ऐजेन्सीयो के द्वारा सुविधाओ और सुविधाओ को बढाने के लिए प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गई ।

देश के जिस भी भाग में हम भ्रमण को जाते है वहॉ के कलात्मक हस्तशिल्प व्यवसाय को बढावा देते है जिसे हम सांस्कृतिक खरीदारी कहते है। और पर्यटन इस खरीदारी को अपने साथ स्मृति के रूपम में जाता है। भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओ अपने डिजाइन आकार, रंगो के लिए प्रसिद्ध है। बनारस, सूरत, और अहमदाबाद का सिल्क, मिर्जापुर की दरिया, मिटटी के बर्तन, कॉसा और ताम्बे की सजावटी वस्तुए प्रसिद्ध है। इससे स्थानीय व्यवसाय के साथ – साथ लोगो की रोजगार भी प्राप्त होता है।

लकडी पर नक्काशी भी हमारे देश का पारम्परिक कार्य है। उ.प्र. के सहानपुर की नक्काशी, शीशे का फ्रेम, अदभुत कारीगरी की जाती कश्मीर के अखरोट की लकडी पर सुन्दर डिजाइन बनाये जाते है। इसी प्रकार देश के विभिन्न हिस्सो में (असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड) विभिन्न प्रकार की काश्ठ कला देखने को मिलती है।

दारी व्यवसाय भारत के दक्षिणी राज्य के कई किलो में फैला है। वर्तान में आधुनिक बाजारो की आवश्यकताओ के अनुरूप इनकी बनाबट मे प्राकृतिक के दर्शन के साथ – साथ ऐतिहासिक गाथाओ, कहानियो, बाग बगीचो, वनस्पति को भी चित्रित किया जाता है।

पारंपरिक वस्तुओ ने पर्यटन स्थल पर व्यवसाय करने के लिए युवाओ को रोजगार के नये – नये मार्ग प्रशस्त किये है। बच्चो के खिलौने जो कि बच्चो की जिज्ञास को शांत करते है। भारतीय लोक गाथाओ, परंतु एक बच्चो की जिज्ञासा को शांत करते है। भारतीय लोक गाथाओ, परंतु पक्षियो आदि का चित्रण करते है।

वाराणसी के  लकडी के बने खिलौने, कोडा, बल्ली  के मिट्टी के खिलौन आदि प्रसिद्ध भारतीय वस्त्र का व्यापार लगभग २०० वर्ष पूर्व से है। वस्त्रो पर रंगाई, छपाई, कडाई, गोटा, कन्ज, और मोती का प्रयोग कर अधिक आर्कशक बनाया जा सकता है। कपडे प्राय मखमल, सिल्क, उनी, सूती वस्त्रो का प्रयोग होता है।

चम्बा हिमालय मे साधे टांको से कृष्ण लीला तथा अन्य धार्मिक घटनाओ को दिखाया जाता है। कपडो पर चिकन की कढाई का केन्द्र लखनउ है। उनी

वस्त्रो, शालो पर कढाई साडियो पर जरी, सोने चांदी के तारो से कसीदाकारी की जाती है। कलमकारी भी पोशाको साडीयो पर की जाती है। शंख हड्डी और हाथी दांत से भी आभूषण और घर की सजावट की वस्तुए बनाई जाती है, हमारे देश मे प्रत्येक क्षेत्र में लेघु—कुटीर उद्योग है। हतकरघे से सूती, रेश्मी, वस्त्र, कपडा बुनना, कढाई, कसीदे, सिलाई व वस्त्रो पर सजावटी कार्य कर पर्यटन स्थालो पर व्यवसाय कर स्थानीय कला को प्रोत्साहन मिलता है।

पर्यटन से स्थानो के भ्रमण, व्यवसाय, मनोरंजन, शिक्षा प्राप्त होती है। बर्तन मे परिवहन के गतिमान साधनो के विकास के कारण कम समय में एक स्थान से दूर सारे स्थान पर आसानी से घूम सकते है। देश की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन से सुद्रढ होती है। स्थानीय लोगो को व्यवसाय से आय प्राप्त होती है। फोटोग्राफर, गाइड, वस्तुओ के विक्रेताओ , पारस्परिक वस्त्र आभूषण तथा अन्य वस्तुओ के उत्पादन व विक्रय से जुडे व्यक्तियो की आय की पर्यटन से बढ जाती है। साथी में नये — नये रोजगार उत्पन्न होते है।

पर्यटन को बढावा देना आज की आवश्यकता है। अत: प्रोत्साहन के साथ — साथ हमे पर्यटन के संवर्धन ओर संरक्षण जैसे पैड पौधो, जीव जन्तुओ की रक्षा करना, प्राकृतिक सौन्दर्य को बनाये रखना, जल को कचरे से प्रदुशित नही करना, स्थलो के प्रति, स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करे। ताकि और अधिक लोग आर्कशित हो। धार्मिक स्थलो पर भिक्षावृत्ति को बढावा न दे, नही ही भडकाउ वस्त्रो को धारण करने चाहिए। इससे सामाजिक व सांस्कृति वातावरण स्वच्छ हो सके।

पर्यटन का महत्व किसी से छुपा नही है। आज यह हमारी सामाजिक आर्थिक गतिविधियो का महात्वपूर्ण अंग है। ओर एक बडा गृह उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। यहां हम निवेश कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते है। होटल, रेस्तरो के क्षेत्र कई लोगो को रोजगार मिलता है। साथ ही यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मुख्य साधन हो गया है। इसके अलावा पर्यटन से राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, एकता सदभावना व मैत्री के भाव मजबूत होते है।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची :**

१) सम्पूर्ण भारत के सांस्कृतिक पर्यटन स्थल — जगमोमहन नेगी

२) पर्यटन के एतिहासिक अनुपयोग — डॉ. हंसा व्यास

३) पर्यटन और परिधान —विमल कुमार कपूर

४) पर्यटन के विविध आयाम — के. के. दीक्षित, जे. पी. गुणा

❑❑❑